Library

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

7 मार्च, 2003

खण्ड-1, अंक-3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 7 मार्च, 2003

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3)16
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)22
स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं/वाक आऊट	(3)25
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)29
बैठक का समय बढ़ाना	(3)63
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)63
बैठक का समय बढ़ाना	(3)77
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)78

मूल्य :

88

HVS/Lib/(12)/82604

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 7 मार्च, 2003

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

श्री अध्यक्ष : Hon'ble Members, questions hour. Sh. Banta Ram

तारांकित प्रश्न संख्या : 1291

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री बन्ता राम सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Number of Posts of Medical Officers lying vacant

***1303. Shri Ramesh Kumar Khatak :** Will the Minister of State for Health be pleased to state the number of posts of M.Os, if any, lying vacant in the State at present togetherwith the steps taken or proposed to be taken to fill up the said vacancies ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ० एम०एल० रंगा) : चिकित्सा अधिकारियों के 1693 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से 187 पद रिक्त हैं। ये पद शीघ्र ही भरे जाएंगे। 150 रिक्त पदों को भरने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 17-02-2003 से साक्षात्कार लिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे यहां हरियाणा में चिकित्सा अधिकारियों के कुल 1693 पद स्वीकृत हैं जिनमें से इस समय 1506 पद भरे हुए हैं तथा चिकित्सा अधिकारियों के 187 पद आज के दिन खाली पड़े हैं।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि चिकित्सा अधिकारियों के जो पद रिक्त पड़े हुए हैं ये पद कब तक भर दिये जाएंगे? इस के साथ ही क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा अधिकारियों की जो टोटल संख्या दर्शाई गई है इनमें से कितने एस०सीज० तथा कितने बी०सीज० कैटेगरीज के हैं तथा कितने पद जनरल कैटेगरीज के हैं। चिकित्सा अधिकारियों के जो पद रिक्त पड़े हैं क्या उन पदों को भरने के लिए सरकार ने कोई तिथि निर्धारित की है? अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहूँगा कि इस समय एस०एम०ओज० के पदों की क्या पोजीशन है, इनकी कितनी पोस्टें खाली हैं और ये खाली पोस्टें कब तक भर दी जाएंगी? इस समय सोनीपत जिले में एस०एम०ओज० की कितनी पोस्टें खाली हैं? ये पोस्टें कब तक भर दी जाएंगी माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करें।

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, तीन साल पहले जब हमारी सरकार आई थी उस समय 52 अस्पताल ऐसे थे जिनमें एक भी डॉक्टर नहीं था। हमारी यह प्राथमिकता रही कि पूरे

[डॉ० एम०एस० रंगा]

हरियाणा में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने वर्ष 2000, 2001 तथा वर्ष 2002 में डॉक्टरों की नियुक्तियां कीं और कोई पी०एच०सी० या सी०एच०सी० ऐसी नहीं रही जिसमें कोई डॉक्टर न हो। अभी 187 रिक्त पदों की बात आई है। आज भी हमारे हरियाणा लोक सेवा आयोग में चिकित्सा अधिकारियों के इन्टरव्यू चल रहे हैं और दो दिन में यह साक्षात्कार समाप्त हो जाएगा। 150 पदों को भरने के लिए यह साक्षात्कार किया जा रहा है। जिस समय यह सूची हमारे पास आएगी यह पद भी भर दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने दूसरा जो प्रश्न किया है कि एस०एम०ओज० के कितने पद खाली हैं तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि हमारे यहां पर अस्पतालों में तथा डायरक्टोरेट हैल्थ सर्विसीज में अपर स्तर के अधिकारियों के 362 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 324 पदों पर हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं और 38 पद खाली हैं। यहां कुछ पद परमोशन के कारण खाली हैं, कुछ वरिष्ठ अधिकारी इमिजियेट त्याग-पत्र दे जाते हैं। उन खाली स्थानों के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया भी साथ ही साथ चल रही है क्योंकि 25% पद आरक्षण से पदोन्नति से भरे जाने हैं जो पद खाली हैं, उन पर परमोशन की प्रक्रिया पूरी होने पर जल्दी ही ये पद भर दिए जाएंगे। इस प्रकार चिकित्सा अधिकारी तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का कोई पद खाली नहीं रहेगा। तीसरा सम्मानित सदस्य ने यह भी पूछा है कि जिला सोनीपत में कितने पद एस०एम०ओज० के हैं और उनमें से कितने खाली हैं। इस समय सोनीपत जिले में चिकित्सा अधिकारियों के 96 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 86 पदों पर चिकित्सा अधिकारी काम कर रहे हैं और 10 पद खाली हैं। ज्योंही चिकित्सा अधिकारियों की चयन प्रक्रिया पूरी होगी इन पदों को भर दिया जाएगा। जल्दी ही वह समय आएगा जब सोनीपत जिले में डॉक्टर का कोई भी पद खाली नहीं रहेगा।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से यह जानना चाहूँगा कि चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरने के लिए क्या वे रोस्टर प्रणाली का ध्यान रख रहे हैं और क्या इन पदों के लिए रोस्टर रजिस्टर मेनटेन किया हुआ है?

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, पहली बार वर्तमान सरकार ने ऐसा कार्य पूरा किया है तथा अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षित पदों का हमने रोस्टर रजिस्टर बनाया हुआ है और उस रजिस्टर के हिसाब से ही डॉक्टरों के पद तथा दूसरे पदों पर नियुक्तियां होती हैं और उसमें आरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाता है। आज भी हमारी जो चयन प्रक्रिया चल रही है उसमें भी रोस्टर रजिस्टर के अनुसार आरक्षण का पूरा ध्यान रखते हुए जितने भी पद आरक्षित हैं उनको पूरा किया जाएगा। पी०एच०सी० के स्तर पर भी हमने दन्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की हुई हैं। आज के दिन 118 पी०एच०सीज० ऐसी हैं जहां पर दन्त चिकित्सा सेवा प्रदान की गई है, किसी और प्रान्त में आज तक यह सेवा पी०एच०सी० स्तर पर प्रदान नहीं की जा रही है।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी, डॉ० एम०एल० रंगा से जानना चाहता हूँ कि ये जो 187 पद रिक्त पड़े हैं जिनमें से 150 पदों के लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार लिए जा रहे हैं जो 37 रिक्त पद रह जाएंगे इनको भरने के लिए आपकी तरफ से क्या कोई कार्यवाही की जाएगी? इसके अलावा मेवात में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने स्वास्थ्य सेवा शिविर लगा करके स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत विकास करवाया है। हथीन, मंडगोला, औरंगाबाद, नांगलजाट और उटावड़ सी०एच०सीज़० हैं इनमें डॉक्टर्ज के कितने स्वीकृत पद हैं और कितने पद इनमें से रिक्त पड़े हुए हैं और जो रिक्त पड़े हुए हैं उनको भरने के लिए क्या कोई कार्यवाही की जाएगी?

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी ने कहा है कि डॉक्टर्ज के 187 पद खाली हैं और इसमें 150 की भर्ती की जा रही है बाकी 37 पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी। मैं इनको यह बताना चाहूँगा कि हमने दिसम्बर में सभी डॉक्टर्ज को नियुक्तियां दी थीं। जब नियुक्तियां दी थीं उस समय केवल 150 पद ही खाली थे। हमारी नियुक्तियां मैरिट के आधार पर होती हैं और नियुक्ति पत्र देने के बाद उन डॉक्टर्ज ने ज्वायन नहीं किया था जिसकी वजह से हम वह पद एडवरटाईजमैंट में नहीं दे सके इसलिए हम 150 पद ही भर रहे हैं और बाकी जो पद रह जाएंगे उनको भी भरने का प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मानित साथी ने निजी क्षेत्र की बात पूछी है कि वहां पर कितने पद खाली हैं तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि वहां पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बात की है उनके बारे में हमारे पास लिस्ट नहीं है। मैं आपको फरीदाबाद के बारे में बता देता हूँ कि वहां पर 216 पद स्वीकृत हैं और इनमें से डॉक्टरों के 194 पद भरे हुए हैं, जो फरीदाबाद और मेवात में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने यह भी पूछा है कि ये जो 22 पद खाली पड़े हुए हैं ये कब भरे जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, चाहे रावत साहब का क्षेत्र हो या श्री बिसला जी का क्षेत्र हो, मैं इनको यह बताना चाहूँगा कि जब कोई पोस्ट खाली ही नहीं रहेगी तब इनके द्वारा यह प्रश्न पूछने का औचित्य ही नहीं रहेगा। जो पद खाली हैं जल्दी ही उनको भी भर दिया जाएगा और हरियाणा में कहीं पर भी डॉक्टर्ज की कोई प्रोब्लम नहीं रहेगी।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने डाक्टर्ज के बारे में बताया है कि कितने पद खाली पड़े हैं तो क्या ये हमें यह भी बताएंगे कि हमारे यहां पर कितने पैरा मैडीकल के पद खाली पड़े हुए हैं और जो पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरने के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? इसके साथ ही अक्सर यह सुनने को मिलता है कि जो डाक्टर्ज हमारे सिविल अस्पताल में कार्यरत हैं, ये प्राइवेट प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। एक्चुअल में हमारे सिविल अस्पताल डॉक्टर्ज के लिए ट्रेनिंग सैंटर्ज बन गए हैं। वहां पर वे अप्वायंटमैंट लेते हैं, कुछ साल काम करते हैं और उसके साथ-साथ प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन डाक्टर्ज पर चैक रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने दो प्रश्न पूछे हैं। एक तो इन्होंने पूछा है कि पैरा मैडिकल स्टाफ के कितने पद रिक्त हैं और जो पद रिक्त हैं उनको भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अभी इनसे पहले मेरे भाई श्री रमेश खटक ने अपना प्रश्न पूछते हुए चिकित्सा अधिकारियों के बारे में जानना चाहा था उसकी लिस्ट तो मेरे पास है। विज साहब ने पैरा मैडिकल स्टाफ के बारे में पूछा है। यदि इन्होंने किसी विशेष अस्पताल के बारे में जानकारी लेनी है या यदि कहीं पर ये अपना इलाज करवा रहे हैं तो ये मुझे बता दें, वहां पर रिक्तियां पूरी कर दी जाएंगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो खाली पद हैं उनको हम भरेंगे और जो यह बात पैरामैडिकल स्टाफ के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में मेरे पास इस समय एग्जेक्ट फिगर नहीं हैं क्योंकि इसके बारे में तारांकित प्रश्न में कुछ नहीं था। जहां तक इन्होंने डाक्टर्ज द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं इस बारे में इनको बताना चाहूँगा कि इसके बारे में हमें पहले भी लगातार शिकायतें मिलती रही हैं लेकिन हमारे से पहले वाली सरकारों ने इस बारे में कुछ नहीं किया। 3 साल पहले जब हमारी सरकार आई तो हम सभी ने सलाह करके यह निर्णय लिया कि हम कैसे इस प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद करें, हमने डाक्टर्ज की एसोसिएशन के साथ बैठ करके मीटिंग की और इस समस्या का हल निकालने के बारे में उनसे बातचीत की। तो उन्होंने हमें सुझाव दिया कि बाकी स्टेट्स में वहां की सरकार डॉक्टर्ज को एन०पी० अलाउंस देती है, लेकिन हमारे यहां पर एन०पी० अलाउंस

[डॉ० एम०एल० रंगा]

नहीं मिलता है। डॉक्टर्ज को एन०पी०ए० दें ताकि वह प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करें। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का जिन्होंने एक ही बार में अपनी कलम से 53 लाख रुपये मंजूर करके एन०पी०ए० दिया जिसकी वजह से अब डॉक्टर्ज द्वारा की जाने वाली प्राइवेट प्रैक्टिस में कमी आयी है। जहां तक एक-आध डॉक्टर द्वारा चोरी छिपे प्राइवेट प्रैक्टिस करने की बात है, मैं बताना चाहूँगा कि यह सब मानसिकता की बात होती है क्योंकि जब वे एम०बी०बी०एस० एवं एम०डी० करके आते हैं तो समाज उनको हाईली इंटैलैक्चुअल मानने लगता है। डॉक्टर भी अपने आपको हाईली इंटैलैक्चुअल मानने के कारण प्राइवेट प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। लेकिन हम सभी विधान सभा सदस्यों की भी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर कहीं पर इस तरह के डॉक्टर उनके ध्यान में आते हैं तो कृपा करके वे हमें अवगत करवाएं ताकि इस तरह के डॉक्टर्ज पर भी विशेष ध्यान दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमें सभी का सहयोग अपेक्षित है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल मेन क्वैश्चन से अलग है। मंत्री जी बड़े काबिल हैं और तैयारी करके भी आते हैं इसलिए इनसे क्वैश्चन से अलग हटकर भी जनरल सवाल पूछा जा सकता है। जैसा अभी विज साहब ने भी इस बारे में कहा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कई जगहों पर डॉक्टर्ज की हाजिरी तो सरकारी अस्पतालों में चलती रहती है लेकिन वे प्राइवेट प्रैक्टिस कहीं और करते रहते हैं और कुछ इसी तरह से हमारे ऐलनाबाद में भी हो रहा है। मैं आपके माध्यम से इनसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐलनाबाद से इनके पास इस तरह की कोई शिकायत आयी है कि वहां किसी डॉक्टर ने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रखी है और वहां के अस्पताल की दवाइयां बाजार में भी बिकती हैं अगर ऐसी कोई शिकायत इनके पास आयी है तो क्या मंत्री महोदय ने इस पर कोई ऐक्शन लिया है? मेरा दूसरा सवाल यह है कि हमारे सिरसा जिले की ग्रीवैंसिज कमेटी के चेयरमैन शिक्षा मंत्री जी हैं और इन्होंने इसकी मीटिंग में ऐलनाबाद के एक डॉक्टर के बारे में भारी शिकायतें मिलने के बाद उसको सस्पैंड करने के आर्डर किए थे। इस बात को तीन-चार महीने हो गये हैं क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह की कार्यवाही कितने महीनों के बाद होती है? जब ग्रीवैंसिज कमेटी के चेयरमैन ने उसको सस्पैंड करने के आर्डर कर दिए तो अब तक भी यह कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, हमारे जो डॉक्टर्ज प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उसके विषय में मैं विस्तार से पहले ही बता चुका हूँ। सम्मानित साथी चौधरी भागी राम जी ने विशेषत: ऐलनाबाद का इस बारे में जिक्र किया है। ऐलनाबाद में एक दम्पति की शिकायत हमें मिली थी जोकि प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। उस दम्पति को तुरन्त प्रभाव से हमने वहां से स्थानान्तरित किया और ऐसे एस०एम०ओ० के अधीन किया जो उन पर निगरानी रख सके कि वे अब भी प्राइवेट प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं। सर, हमें जैसे ही सिरसा जिले की शिकायत प्राप्त होगी कि वहां पर किसी डॉक्टर ने अनियमितता की थी और उस डॉक्टर के अगेन्स्ट हमारे ग्रीवेंसिज कमेटी के चेयरमैन ने भी सिफारिश की है कि उसको सस्पैंड किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस समय तो मेरे पास विशेषत: उसका ब्यौरा नहीं है इसलिए मैं सम्मानित साथी से अनुरोध करूंगा कि वे मुझे इसी समय पर्ची पर लिखकर उसका नाम दे दें दोपहर से पहले-पहले ही उसको निलम्बित कर दिया जाएगा। (विघ्न)

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर साहब, जैसा कि अभी भागी राम जी ने बताया कि मंत्री जी बहुत समझदार हैं और अपने महकमे को अच्छी तरह से चला रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आज एक

ट्रैंड सा हो गया है कि गरीब आदमी ही सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जाता है जबकि अमीर आदमी दूसरे अस्पतालों में इलाज करवाने जाता है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्ज की अच्छी खासी कमी रहती है इसका एक कारण यह भी है कि डॉक्टर्ज आमतौर पर कोर्ट्स में मिलते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा प्रोविजन किया जा सकता है जिससे सर्जन कोर्ट्स के चक्कर न लगाएं और वह केवल लोगों का ही इलाज करें?

डॉ० एम०एल० रेगा : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूँगा कि तीन वर्ष पहले जब हमारी सरकार आई तो इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुईं कि हमारे डॉक्टर्ज साहिबान कोर्ट में गवाही के नाम से सुबह ही चले जाते थे और उसके बाद नहीं आते थे। इस विषय में मैंने व्यक्तिगत पत्र परम आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को लिखा, उनसे समय लिया और स्वयं मिला और निवेदन किया कि हमारे जो डॉक्टर्ज हैं गवाही के लिए आते हैं। (विघ्न) गवाही के लिए अध्यक्ष महोदय डॉक्टर्ज को जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि जब एम०एल०आर० कटती है तो डॉक्टर्ज की विटनैस होती है इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया था कि हमारे अस्पतालों के डॉक्टर्ज जब विटनैस के लिए आएं तो उन्हें पूरे दिन न बैठाया जाए। डॉक्टर सात बजे आएं तो उन्हें 8 बजे तक फारिग कर दिया जाए ताकि वे बचे हुए समय में जाकर मरीजों की देखभाल कर सकें। इसके अलावा मैंने डॉक्टर्ज की पर्सनली रिक्वैस्ट भी की उसके बावजूद भी वे गवाही देने के बाद अस्पतालों में नहीं पहुंचते हैं तो यह मानसिकता की कमी की बात है। मैं मौके पर जाता हूँ डॉक्टर्ज को बैठाकर उनसे रिक्वैस्ट करता हूँ और यह भी कहता हूँ कि भगवान के बाद दूसरा दर्जा डॉक्टर का होता है डॉक्टर पर विश्वास होता है इसलिए जैसे ही आपकी पेशी खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको अस्पताल में आकर मरीजों की देखभाल करनी चाहिए। सिविल सर्जन भी उनको इस प्रकार की हिदायतें देते हैं और उसके बाद से इस प्रकार की शिकायतों में कमी भी आई है लेकिन जहां तक डॉक्टर्ज की कमी की बात है, तो हिन्दुस्तान से बाहर से तो डॉक्टर आएंगे नहीं। जहां तक मानसिकता की बात है उसे बदलना हम सभी का कार्य है सिविल सर्जन भी ये काम कर रहे हैं और हमने कोर्ट्स में भी निवेदन किया है कि हमारे जो डॉक्टर्ज तारीख पर आते हैं उन्हें जल्दी फारिग किया जाए ताकि वे अस्पतालों में ज्यादा समय दे सकें।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि चौधरी देवी लाल जी के आदर्शों पर यह सरकार चल रही है। अध्यक्ष महोदय, हम अधिकांश जनप्रतिनिधि गांवों से और पिछड़े क्षेत्रों से आए हुए हैं और मध्यमवर्गीय परिवारों से संबंधित हैं। हमारे फरीदाबाद जिले में डॉक्टर्ज के 216 पद हैं उनके अगेंस्ट 194 पद भरे हुए हैं और 22 पद रिक्त हैं और मुझे ऐसा अनुभव है कि इनमें से ज्यादातर रिक्त पद हमारे मेवात क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्र से हैं साथ ही एस०एम०ओ० हथीन की स्टेट्मैंट के अनुसार हमारे यहां मैडिकल आफिसर्ज के 5 पद रिक्त हैं, फार्मासिस्ट के 3, रेडियोग्राफर का 1 व लैब टैक्नीशियन के 4 पद और एम०पी०एच०डब्ल्यू० के 13 पद रिक्त हैं इस प्रकार से काफी पद रिक्त पड़े हैं। मंत्री जी ने भी कहा है जो 37 की कमी रही थी वह नौकरी छोड़कर चले गए थे ग्रामीण अंचलों में डॉक्टर्ज की अध्यापकों जैसी अवस्था है वहां पर सुविधाओं और शिक्षा का अभाव है इसलिए वह वहां ज्वॉइन ही नहीं करते हैं और इस प्रकार रिक्त पद रिक्त ही पड़े रहते हैं इस बात को दृष्टिगत रखकर क्या सरकार कोई विशेष कदम उठाएगी ताकि देहाती क्षेत्रों में डॉक्टर्ज के पद भरे जा सकें?

श्री अध्यक्ष : बरवाला जी, आप भी अपना सवाल पूछ लें मंत्री जी इकट्ठा जवाब दे देंगे।

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि

[चौ० जय प्रकाश]

एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि हमने प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी लगा दी है। जींद, नरवाना और हिसार के सिविल अस्पतालों में प्रतिदिन कितने ही मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि वहां बंदर इतने ज्यादा है कि वहां आदमी नहीं घुसते। इससे पता चलता है कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कितनी चिंतित है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूँगा कि सरकार डॉक्टर बनाने पर करोड़ों रुपया खर्च करती है और डॉक्टर 5-7 साल सरकारी नौकरी करने के बाद अपना प्राइवेट क्लीनिक खोल लेते हैं इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित साथी श्री रावत साहब ने जिस प्रकार से बताया है कि हमारे मेवात एरिया में काफी ज्यादा पद खाली हैं तो मैंने चिकित्सा अधिकारियों के पदों के बारे में जानकारी दी थी। जहां तक विशेष ग्रामीण अंचल की बात है, हमारी सरकार आदरणीय चौधरी देवी लाल जी की नीतियों पर चल रही है। गांव के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना हम अपना कर्त्तव्य मानते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम गांवों में जाकर चलाया है उसी प्रकार से 'स्वास्थ्य आपके द्वार' कार्यक्रम गांव-गांव जाकर चलाया जा रहा है जिसमें 22 डॉक्टरों की टीम सारी सुपर फैसिलिटीज के साथ गांवों में जाती है और गांवों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है जिनमें ग्रामीण अंचलों से आये हुए लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है और एक्स-रे, ई०सी०जी० और दूसरे जरूरी टैस्ट मौके पर ही किये जाते हैं और उनका वहीं पर पक्का ईलाज किया जाता है। यह हमारी ग्रामीण देहातों की योजना है। (विघ्न) मेरा सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि वे कृपया सुनने का कष्ट करें। (विघ्न) दूसरा जैसा कि रावत साहब ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में अध्यापकों की तरह ही चिकित्सा अधिकारी नहीं रहते इसके लिए सरकार ने क्या किया है। सरकार ने डॉक्टरों की नियुक्ति के समय यह अनिवार्य कर दिया है कि आपको सबसे पहले ग्रामीण अंचल में नौकरी करनी होगी। इस बात को उनके नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिख दिया जाता है। उनको साफ कह दिया जाता है कि अगर नौकरी करनी है तो पहले ग्रामीण अंचल में नौकरी करनी पड़ेगी। इसी वजह से कुछ डॉक्टर नौकरी छोड़कर चले गये तभी ये पद खाली पड़े हुए हैं। तीसरा मेरे माननीय साथी ने सवाल किया कि जींद, नरवाना और हिसार के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में कमी आई है। यह कमी इस लिए आई है क्योंकि हमारे स्वास्थ्य शिविर हर सप्ताह देहातों में लगते रहते हैं और देहाती मरीजों का शिविर में ही पूरा चैक-अप हो जाता है और उनको वहां से मुफ्त दवाइयां मिल जाती हैं और एक कैम्प में दो लाख से लेकर तीन लाख रुपये तक की दवाइयां मुफ्त दी जाती हैं इसलिए ग्रामीण मरीज शहरों में कम आते हैं और जनरल अस्पतालों में केवल शहरी मरीज ही आते हैं इसलिए वहां की संख्या कम हो गई है लेकिन फिर भी जनरल अस्पतालों की आक्यूपैंसी बढ़ी है वहां पर कोई भी बिस्तर खाली नहीं मिलेगा। तीसरी बात कि डॉक्टर नौकरी छोड़ जाते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं तो मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि आदमी को जो अच्छा लगता है वही करता है ऐसे हमारे कई साथी हैं जो नौकरी छोड़कर विधायक बन गये हैं इसलिए जिसको जो अच्छा लगता है वह वही अपनाता है।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, जो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं ****

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी जो कह रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को और हरियाणा सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि हर गांव में जाकर सरकारी डॉक्टरों की टीमें कैम्प लगाकर और शिविर लगाकर बहुत

ही सराहनीय काम कर रही हैं। गांवों में ऐसे गरीब आदमी भी हैं जो अस्पताल तक आने जाने का भाड़ा नहीं दे सकते वे इन शिविरों में जाकर अपना ईलाज करवा लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कोई ऐसा इंजैक्शन तैयार करें जो इन माननीय सदस्यों को स्थाई रख सके और ये अपनी पार्टी में टिके रहे और दलबदलू न हों (हँसी)।

डॉ० सीता राम : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने ग्रामीण अंचलों में बहुत सी पी०एच०सीज और सी०एच०सीज बनाई हैं क्या वहां पर डॉक्टरों की नियुक्ति भी की है? लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर यह देखने में आया है कि वहां पर डॉक्टर्ज की उपस्थिति कम मिलती है और वे अपना हैडक्वार्टर भी मेनटेन नहीं करते, इससे वहां के ग्रामीण लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती। क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठा रही है जिससे कि वहां पर डॉक्टर्ज की उपस्थिति अनिवार्य की जा सके और वे अपना हैडक्वार्टर मेनटेन कर सकें और लोगों को इससे फायदा मिल सके?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए पहली बार यह विचार किया है कि जिस गांव में सी०एच०सी० या पी०एच०सी० हैं वहां पर डॉक्टर्ज के रहने के लिए निवास स्थान हों। पहली बार 3 सालों में 40 भवन तैयार किए गए हैं और उनमें सबसे पहली प्राथमिकता डॉक्टर्ज के निवास स्थान के लिए रखी गई है। पहले डॉक्टर बहाना करते थे कि हमारे लिए निवास स्थान नहीं है। हमने पी०एच०सी० और सी०एच०सी० में निवास स्थान बनाकर डॉक्टर्ज को दिए हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि डॉक्टर्ज वहां रहें ताकि गांव के लोगों को अगर रात-बेरात कोई तकलीफ हो तो वे डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले सकें। ऐसी टीमें बनाई जा रही हैं जो आने वाले समय में चैक करेंगी कि डॉक्टर अपने हैडक्वार्टर पर है या नहीं। एस०एम०ओज०, सिविल सर्जन, डिप्टी डायरैक्टर और डायरैक्टर या उच्च स्तर के अधिकारी सरप्राईज चैक करेंगे, फ्लाइंग स्कवैड टीमें बनाई गई हैं और यह हिदायतें भी दी गई हैं कि डॉक्टर्ज अपना स्टेशन न छोड़ें। इसमें हमने कामयाबी भी हासिल की है। हां एक दो जगह पर पी०एच०सी० की बिल्डिंग बननी है या बन रही है फिलहाल ये पी०एच०सीज० प्राइवेट धर्मशाला में चल रही हैं, ऐसी जगहों पर तो ऐसी बात कुछ हद तक वाजिब है क्योंकि गांव में रहने की जगह नहीं हैं। गांव वाले बिल्डिंग के लिए जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। हम यह निश्चित कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो सी०एच०सी० और पी०एच०सी० बनेगी उनमें डॉक्टर्ज के निवास स्थान पहले बनाए जाएंगे। ऐसा करने से डॉक्टर्ज वहां टिकेंगें और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।

श्री बंता राम : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि सभी इस बात को मानते हैं कि पहले स्वास्थ्य के लिए निरोगी काया। मुख्य मंत्री महोदय ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अच्छे कदम उठाए हैं और हैल्थ मिनिस्टर ने एक-एक बात का जवाब दिया है। हरियाणा सरकार की तरफ से जो ट्रोमा सैंटर खोले जाएंगे, मैं जानना चाहूँगा कि इनकी बिल्डिंग पर कितना खर्च आएगा और इसके उपकरणों पर कितना खर्च आएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि ये सैंटर कहां-कहां खोलने का प्रावधान सरकार कर रही है?

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने ट्रोमा सैंटर के बारे में पूछा है, हमारी सरकार ने बैठकर यह विचार किया है कि हरियाणा में 4 मुख्य राजमार्ग हैं जो पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को राजधानी से जोड़ते हैं। उन राजमार्गों पर औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण लोग

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[डॉ० एम०एल० रंगा]

समृद्धशाली हुए हैं और वाहन इतने बढ़ गए हैं कि भीड़-भाड़ के कारण 33 प्रतिशत मृत्यु दर दुर्घटनाओं के कारण हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि दुर्घटनाग्रस्त लोगों को कैसे जल्दी से जल्दी चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए, मुख्य मंत्री महोदय ने विचार किया और उन्होंने प्रस्ताव बनाया कि चारों राजमार्गों पर 4 ट्रोमा सैंटर होने चाहिएं। इसमें करनाल को प्राथमिकता दी गई है। करनाल हाईवे पर ट्रोमा सैंटर 183 लाख रुपये की लागत से बनकर तैयार हो गया है जो हमने जनता को समर्पित किया है। इसमें जो लेटैस्ट इक्यूपमैंटस लगाए गए हैं उन पर 82 लाख रुपये खर्च आया है। 66 लाख रुपये भवन बनाने में खर्च किया गया है। भारत सरकार की तरफ से 150 लाख रुपये और हरियाणा सरकार की तरफ से 33 लाख रुपये लगाए गए हैं। आज आप इस ट्रोमा सैंटर को देखेंगे तो इसमें लेटैस्ट इक्यूपमैंट्स लगाए गए हैं, चाहे वह 300 एम०एम० की एक्सरे मशीन हो, 500 एम०एम० की एक्सरे मशीन हो, ई०सी०जी० मशीन हो, टी०एम०टी० मशीन हो, सभी लेटैस्ट तकनीक के इक्यूपमैंट्स हैं और इन पर 85 लाख रुपये खर्च किया गया है। 2 विशेष ऐम्बुलैंस तैयार की गई हैं। सरकार की हिदायतें थीं कि इस प्रकार की ऐम्बुलैंस तैयार की जाए ताकि वह एक्सीडैंटल जगह पर तुरन्त जाए और इसमें आपात्काल की सारी व्यवस्था हो और वह सारी व्यवस्था करके हमने 20 लाख की दो ऐम्बुलैंस तैयार की हैं। अगर एक्सीडैंटल जगह पर हमारी ऐम्बुलैंस 15 मिनट में पहुंच जाती है तो 50 प्रतिशत मृत्यु दर में हम कमी ला सकते हैं। हमने सुनिश्चित किया है कि ट्रोमा सैंटर से हमारी ऐम्बुलैंस 30 मिनट से पहले पहले एक्सीडैंटल जगह पर जाएगी और उनको ट्रोमा सैंटर में लाएगी और चाहे वह न्यूरो सर्जरी का केस हो, आर्थोपैडिक का केस हो या किसी और प्रकार घायल होने का केस हो उनका इलाज वहां किया जाएगा। वहां आई०सी०यू० की व्यवस्था की हुई है ताकि वहां मरीज को तुरन्त पहुंचा कर राहत प्रदान की जा सके। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरे साथी ने पूरक प्रश्न के रूप में पूछा है कि करनाल के अलावा सरकार और कहां-कहां ट्रोमा सैंटर बनायेगी। इस बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने पहले से चार राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर ट्रोमा सैंटर बनाने का हमारा प्रस्ताव मंजूर कर रखा है उनमें से करनाल में ट्रोमा सैंटर बन चुका है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय राज मार्ग-1, राष्ट्रीय राज मार्ग-2, राष्ट्रीय राज मार्ग-8 और राष्ट्रीय राज मार्ग-10 पर ट्रोमा सैंटर बनाये जायें। करनाल के बाद दूसरा ट्रोमा सैंटर जयपुर-रिवाड़ी हाईवे पर रिवाड़ी के आस-पास उसके बाद सिरसा हाई-वे पर सिरसा के आस पास और उसके बाद

10-00 बजे

आगरा-पलवल हाईवे पर पलवल के आस-पास ट्रोमा सैंटर बनाये जावेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने हमें यह लिखा हुआ है कि जब हम पहले ट्रोमा सैंटर का यूटेलाईजेशन सर्टीफिकेट भारत सरकार को दे देंगे तब हमें दूसरे ट्रोमा सैंटर को बनाने के लिए पैसा मिलेगा और जब दूसरे का यूटेलाईजेशन सर्टीफिकेट दे देंगे तब तीसरे ट्रोमा सैंटर के लिए पैसे मिलेंगे और जब तीसरे ट्रोमा सैंटर का यूटेलाईजेशन सर्टीफिकेट दे देंगे तब चौथे ट्रोमा सैंटर के लिए पैसा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से चारों हाईवेज पर ट्रोमा सैंटर बनने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी हमारी ट्रैफिक व्यवस्था, ऐम्बुलैंस व्यवस्था और मोबाईल व्यवस्था हिन्दुस्तान में सबसे अच्छी है। दूसरी स्टेट्स के स्वास्थ्य मंत्री उसे देखने के लिए आते हैं और हमारे से मीटिंग करके सारी जानकारी लेकर जाते हैं कि हरियाणा की ट्रैफिक व्यवस्था, ऐम्बुलैंस व्यवस्था और मोबाईल व्यवस्था में क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि वे ये सुविधाएं अपने यहां भी लागू कर सकें। वे यहां आकर देखते हैं कि हमारे यहां ऐम्बुलैंस से मोबाईल टैलीफोन की कैसी सुविधा है, ऐम्बुलैंस से वायरलैस की कैसी सुविधा है। अध्यक्ष महोदय, निःसन्देह इस तरह से हमारे

यहां दुर्घटनाओं के केसिज में तुरन्त राहत प्रदान की जायेगी। इन दिनों में आप भी अखबारों में पढ़ते होंगे कि हरियाणा के अन्दर करनाल में ट्रोमा सैंटर खुलने से 70 प्रतिशत दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में कमी आई है।

Quantity of Wheat and Rice Purchased

***1285. Shri Tej Vir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the total quantity of wheat and rice purchased for Central Pool are in stock with the State Government on 31-12-2002 ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्रीमान जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

31-12-2002 तक केन्द्रीय पूल के लिए राज्य संस्थाओं जिसमें भारतीय खाद्य निगम तथा मिलरज भी शामिल हैं, के निम्नलिखित भण्डार राज्य में उपलब्ध थे—

(आंकड़े लाख टन में)

		खाद्य एवं पूर्ति तथा राज्य संस्थाएं	एफ०सी०आई०	जोड़
(i)	गेहूँ	59.89	11.59	71.48
(ii)	चावल	—	7.73	7.73
(iii)	धान	5.88	0.08	5.96
	मिलरज़			1.50
	जोड़			86.67

श्री तेजवीर सिंह : स्पीकर सर मैं इस उत्तर से संतुष्ट हूँ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, इस प्रश्न पर ओरिजनली सप्लीमैंटरी पूछने का हक श्री तेजवीर जी का है। ये मंत्री जी की रिप्लाई से संतुष्ट हैं, प्लीज आप बैठें।

Medals Won by Sports Persons

***1300. Sh. Padam Singh Dahiya :** Will the Chief Minister be pleased to state—

[Sh. Padam Singh Dahiya]

(a) the number of sports persons from Haryana who have won Medals in Commonwealth Games, Asian Games, National Games held in the year 2002 ; and

(b) whether any award in cash has been given to the aforesaid sports persons, if so, the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) वर्ष 2002 के दौरान जिन विजेता खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रकुल, एशियाई तथा राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त किये गये हैं उन का वांछित विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र०सं०	प्रतियोगिता स्तर	खिलाड़ियों की संख्या
1.	राष्ट्रकुल खेलें, मानचेस्टर (यू०के०) 25 जुलाई से 4 अगस्त, 2002	11
2.	एशियाई खेलें, बुसान (दक्षिण कोरिया)–29 सितम्बर से 14 अक्तूबर, 2002	14
3.	राष्ट्रीय खेलें, हैदराबाद 14 दिसम्बर से 22 दिसम्बर, 2002	139
	कुल	164

(ख) राज्य की खेल नीति के अनुसार हरियाणा के उपरोक्त खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार दिये गये हैं, जिनका वांछित विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र०सं०	प्रतियोगिता स्तर	खिलाड़ियों की संख्या	नकद पुरस्कार की राशि
1.	राष्ट्रकुल खेलें, मानचेस्टर (यू०के०) 25 जुलाई से 4 अगस्त, 2002	11	72,00,000/–
2.	एशियाई खेलें, बुसान (दक्षिण कोरिया) 29 सितम्बर से 14 अक्तूबर, 2002	14	1,09,00,000/–
3.	राष्ट्रीय खेलें, हैदराबाद 14 दिसम्बर से 22 दिसम्बर, 2002	139	29,86,000/–
	कुल	164	2,10,86,000/–

श्री पदम सिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति से कितने खिलाड़ियों को रोज़गार दिया गया है, कृपया यह ब्यौरा देने का कष्ट करें।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, जहां पहले प्रदेश का वातावरण पथभ्रमित था और जब प्रदेश की बागडोर माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने संभाली तब प्रदेश के नौजवानों को रास्ते पर लाने के लिए प्रदेश की सरकार ने नई खेल नीति लागू की और इस नई खेल नीति के कारण 3 प्रतिशत

का कोटा सरकारी नौकरियों में ऐसे खिलाड़ियों के लिए रखा गया जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रदेश का नाम रोशन किया। इसी प्रकार से पुलिस भर्ती में भी 114 खिलाड़ियों को भर्ती किया गया है और आगे भी जो जेल वार्डन की पोस्टें एस०एस०एस०सी० ने एडवर्टाइज की हैं उनमें भी उच्च स्तर के खिलाड़ियों के लिए जो रिक्वीजिशन की मांग की है उसमें भी इनके लिए रिजर्व पोस्टें रखी गई हैं। इसी प्रकार से एच०एस०आई०डी०सी० और अन्य प्रदेश के जो बोर्ड या कार्पोरेशन हैं उनमें भी ऐसे खिलाड़ियों को नौकरियां दी जा रही हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की अच्छी खेल नीति के सुखद परिणाम हमारे सामने आए हैं। सारे देश में और देश से बाहर भी राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हरियाणा ने पैदा करने का गौरव प्राप्त किया है। लेकिन यह देखने वाली बात है और अनुभव करने की बात यह है कि उम्र के हिसाब से यानी ढलती उम्र में खिलाड़ी जब मैदान में खेलने के योग्य नहीं रहते तो उनको आर्थिक तंगी या बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। हम सभी ने अखबारों में और मैगजीनों में ऐसा पढ़ा है। देखने में आया है कि पुराने खिलाड़ी जो अच्छे स्तर के थे वे आर्थिक तंगी के कारण रेहड़ी लगा रहे हैं या कोयला बेच रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जहां हमारी खेल नीति अच्छी है, जिसको दूसरे प्रदेश कॉपी कर रहे हैं उसमें कृपया यह ऐड कर दिया जाये कि राष्ट्रीय स्तर के या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया है आने वाले समय में उन्हें रोजी-रोटी या कपड़े की तंगी का सामना न करना पड़े क्या इस प्रकार का कोई प्रावधान भी इस खेल नीति में सरकार कर पायेगी, कृपया मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, ऐसा है कि नई खेल नीति के तहत जो अच्छा खिलाड़ी रहा है यदि उसके पास आय का कोई भी साधन नहीं है तो उसको 2000 रुपये पर मन्थ के हिसाब से दिए जाते हैं।

श्री रमेश कुमार खटक : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो ये 114 खिलाड़ी भर्ती किए गए हैं और जो राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं उसमें ऐसे कितने परोमिजिंग खिलाड़ी हैं जो भर्ती किए गए हैं। रेलवे हो या बिजली बोर्ड ऐसे खिलाड़ियों को पदाधिकारी के तौर पर भी भर्ती किया जाता है। कृपया बताने का कष्ट करें कि इन 114 खिलाड़ियों में कितने प्रोमिजिंग खिलाड़ी भर्ती किए गए हैं?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए यह बताना जरूरी समझता हूँ कि मौजूदा सरकार ने खेल को बढ़ावा देने का निर्णय विशेष रूप से इसलिए लिया था क्योंकि अतीत में ऐसी सरकार आई जिसने शराब बंदी की आड़ में शराब की तस्करी को बढ़ावा दिया और उसके परिणामस्वरूप हमारी जो नई जैनरेशन थी यानी नई पीढ़ी थी उसका झुकाव शराब की तरफ हो गया था। उनकी प्रवृत्ति अपराध की तरफ बढ़ने लगी थी। जिन बच्चों के बस्तों में पुस्तकें होनी चाहिएं थीं उनके बस्तों में शराब के पाउचिज पकड़े गए। हमने उस प्रवृत्ति को बदलने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि नई पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल हो सके और वे देश के निर्माण में अहम् भूमिका निभा सकें, उनकी अटैंशन को डाईवर्ट करने के लिए खेल नीति को बढ़ावा दिया। इसमें मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमने सर्वप्रथम निर्णय लिया कि औलम्पिक गेम्ज़ में जो खिलाड़ी गोल्ड मैडल जीत कर के लाएगा उसको एक करोड़ रुपया इनाम की शक्ल में दिया जाएगा। 50 लाख रुपये चांदी का पदक प्राप्त करने वाले को और 25 लाख रुपये ब्रोन्ज पदक प्राप्त करने वाले को दिया जाता है। इसी सदन के एक सदस्य

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

ने इसी बात को लेकर समाचार-पत्रों में सरकार की खिल्ली उड़ाई थी और यह ब्यान दिया था कि मौजूदा सरकार का मुखिया केवल मुफ्त की बल्ले-बल्ले लेने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं क्योंकि किसी ने गोल्ड मैडल हासिल ही नहीं करना है इसलिए मुफ्त में श्रेय लेने की सरकार की यह सोच है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सोच तो यह थी कि हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें इसलिए यह किया गया था। दुर्भाग्य से इस सदन में ऐसे सदस्य भी हैं जो बच्चों को इस प्रकार के कार्यों के प्रति निरुत्साहित करने के पक्षधर हैं। हम यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने जो पुरस्कार घोषित किए थे वे बच्चों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निर्धारित किए गए थे। इन इनामों की घोषणा के दृष्टिगत हमारे प्रदेश की एक महिला कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलम्पिक खेलों में कांस्य पदक प्राप्त किया। पूरे राष्ट्र के एक करोड़ लोग सिडनी ओलम्पिक खेलों के समय मुंह लटकाए हुए बैठे थे और इस महिला ने वहां पर कांस्य पदक प्राप्त करके भारतवर्ष का नाम पदक तालिका में दर्ज करवा कर पूरे राष्ट्र को सम्मान प्रदान किया। हमारी सरकार ने उसी वक्त उसके विदेश से लौट कर आने से पहले ही घोषणा कर दी कि सरकार की ओर से उसे 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। सरकार ने उसे न केवल 25 लाख रुपये दिए बल्कि उसको आवास के लिए एक रिहायशी प्लाट भी प्रदान किया। हमारे इस फैसले की वजह से कर्णम मल्लेश्वरी को कई करोड़ रुपये देश के स्तर पर लोगों ने दिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी इस घोषणा का परिणाम यह निकला कि हर स्तर पर खेलों को बढ़ावा मिला। खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर मनीपुर खेलों में हमारा 16वां स्थान हुआ करता था लेकिन लुधियाना में राष्ट्रीय स्तर की गेमों में हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने 65 मैडल प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और पिछले वर्ष हैदराबाद में हमारे खिलाड़ियों ने 74 मैडल प्राप्त करके एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कॉमन वैल्थ गेमों में 11 पदक प्राप्त किये तथा ऐशियाड गेमों में जहां पूरे राष्ट्र ने 36 मैडल प्राप्त किए, अकेले हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने 14 मैडल हासिल करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, हमें इस बात पर फखर है। हॉकी में गोल्ड मैडल प्राप्त करने वाली टीम में गोल्डन गर्ल का पुरस्कार हमारी लड़की ममता खरब को प्रदान करके हमारे प्रदेश को सम्मान प्रदान किया गया। हमने 2078 लोगों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनाम दिए हैं और तीन करोड़ 47 लाख कुछ हजार के इनामात देकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर खेलों को बढ़ावा दिया है। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ 3% नौकरियों में आरक्षण की सुविधा खिलाड़ियों को इसलिए दी गई है ताकि हमारे बच्चों को प्रोत्साहन मिले और खिलाड़ियों का हौंसला भी बढ़े। इसमें सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है जो खिलाड़ी आगे निकलेगा उसे घोषित सुविधा सरकार की तरफ से प्राप्त होगी। खेलों की दृष्टि से बोर्डज और कारपोरेशन्ज के स्तर पर कहा गया है कि खेलों व खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए तथा वे अपने तौर पर अच्छी टीमों का गठन करें। हमारे बोर्डज तथा कारपोरेशन्ज ने अच्छी टीमों का गठन करके खेलों तथा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का अच्छा प्रयास किया है, इसी का यह परिणाम हुआ है कि लॉ एण्ड आर्डर में सुधार हुआ है। स्पीकर सर, लॉ एण्ड आर्डर स्टेट में पूरी तरह से खराब हो गया था। पूरे राष्ट्र के स्तर पर आज आतंकवाद का साया है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, *******

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाए। दलाल साहब, आप बैठें (विघ्न) दलाल साहब, आप बैठें।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : दलाल साहब, यह सब आपकी सोच नहीं है इस बात को समझिए यह आतंकवाद आपकी सरकार के समय की ही देन है और आप खुद उस सरकार में शामिल थे। (विघ्न) वह समय चला गया अब दूसरे दौर की बात आ रही है। विश्व के स्तर पर भी आज आतंकवाद पनपा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताने जा रहा हूँ कि इन लोगों की सरकार के वक्त में जो हालात पैदा हो गए थे जो परिस्थितियां पैदा हो गई थीं, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने वे परिस्थितियां बदल दी हैं। पूरे विश्व के स्तर पर हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कोई आतंकवाद नहीं है। इस प्रदेश में किसी प्रकार का कोई अलगाववाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई धार्मिक उन्माद नहीं है, किसी प्रकार का साम्प्रदायिक तनाव नहीं है और किसी प्रकार का जात-पात का झगड़ा नहीं है। हरियाणा प्रदेश के लोग आज प्रदेश की प्रगति के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। (विघ्न) फौजी बैठ जा। तेरा नेता आएगा तो उससे सुलटूंगा। (विघ्न)

श्री राम किशन फौजी : ******

श्री अध्यक्ष : राम किशन जी, बैठ जाएं। इनकी कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं की जाये।

श्री राम किशन फौजी : ******

श्री अध्यक्ष : फौजी साहब, अपनी सीट पर बैठ जाएं। आपका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है।

Construction of Subzi Mandi in Pataudi

*** 1342. Shri Rambir Singh :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under considration of the Government to construct New Subzi Mandi in Pataudi and Bhura-Kalan Sub yards?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : हाँ, श्री मान् जी।

श्री रामबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने भौड़कलां और पटौदी में नई सब्जी मण्डी के निर्माण के लिये स्वीकृति दी है। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हेली मण्डी के अन्दर काफी दिनों से नई अनाज मण्डी का प्रपोजल चल रहा है। इसके लिये पिछले एक साल से साईट सिलैक्ट हो चुकी है। मेरा इनसे यह पूछना है कि इसके लिये नोटिफिकेशन करके जमीन कब एक्वायर कर ली जायेगी?

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और मंत्री जी के माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि गुड़गांव में पिछली सरकार की तरफ से फ्लावर मण्डी बनाने की योजना थी और उस पर 110 करोड़ रुपये का खर्चा आना था। वहाँ पर आस-पास के किसान लोग फूलों की खेती करते हैं और उस मण्डी से उन किसानों का फूल एक्सपोर्ट होना था। अगर वह मण्डी बन जाती तो वह ए०सी० मण्डी बनती थी। उस मण्डी का ग्लोबल टैंडर भी हो चुका था लेकिन पिछली सरकार की लापरवाही की वजह से वह मण्डी नहीं बन पायी और वह मण्डी बंगलौर चली गयी, जिससे हमारे किसानों को नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि गुड़गांव के आस-पास पटौदी और फरूखनगर में किसान फ्लावर की खेती बहुत करते हैं तो क्या सरकार वहां पर कोई फ्लावर मण्डी बनाने के बारे में विचार करेगी ताकि हमारे किसानों को फ्लावर एक्पोर्ट करने की सुविधा मिल सके?

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित साथी ने पटौदी और भौड़कलां की सब्जी मण्डियों के बारे में अपने सवाल में पूछा था। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूँगा कि 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत मुख्य मंत्री जी 20 फरवरी 2003 को वहां पर गये थे और वहां के स्थानीय लोगों और सम्मानित साथी की मांग पर मुख्यमंत्री जी ने मौके पर ही सब्जी मण्डी को बनाने की घोषणा कर दी थी। उस मण्डी के लिये भूमि अधिग्रहण करने की कार्यवाही चल रही है जैसे ही इसकी प्रक्रिया कम्पलीट हो जायेगी तो हम इसका प्रस्ताव बनाकर मुख्य मंत्री जी के पास भेज देंगे और मुख्य मंत्री जी की मंजूरी मिलने के बाद इसका एस्टीमेट बनाकर टैण्डर काल करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

इसके अलावा इन्होंने फ्लावर मण्डी गुड़गांव में बनाने वाली बात की है, तो यह प्रोजैक्ट पिछली सरकार का है। यह सरकार खेती में विविधिकरण करने के लिये, डायवरसीफिकेशन प्रोजैक्शन करने के लिये बड़ी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। इसके अलावा मुख्य मंत्री जी ने कृषि विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों को सदा यह निर्देश दिये हैं कि पुरानी खेती को बदला जाये, खेती में डाईवरसीफिकेशन किया जाये ताकि किसी तरह से फलों फूलों और सब्जियों को बढ़ावा दिया जावे। इसके अलावा सम्मानित साथी ने फ्लावर मण्डी की बात जो करी है, इसके बारे में हमारी सरकार एग्जामिन करवाकर कोई न कोई कार्यवाही जरूर करेगी।

चौ० नफे सिंह राठी : स्पीकर साहब, 1989-90 में बहादुरगढ़ में सब्जी मण्डी और चारा मण्डी की जमीन चौधरी देवीलाल जी के आदेश से अधिग्रहित की गई थी लेकिन पिछली सरकारों ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं करवाई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि इस पर कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी?

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित साथी ने जो बहादुरगढ़ सब्जी मण्डी और चारा मण्डी के बारे में पूछा है मैं इनको बताना चाहूँगा कि सारे हरियाणा प्रांत में 107 सब्जी मण्डियां कार्यरत हैं। झज्जर एवं बहादुरगढ़ में सब्जी मण्डियां कार्य कर रही हैं। जहां तक चारा मण्डी का सवाल है, मैं इनको कहना चाहूँगा कि यह सवाल तो सिर्फ सब्जी मण्डी के बारे में है यह चारा मण्डी के बारे में अलग से लिखकर दे दें, इसको एग्जामिन करवा लिया जाएगा।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, सवाल के जवाब में मतलौडा का भी जिक्र है वहां की सब्जी मण्डी बनाने का काम वैसे तो युद्ध स्तर पर चल रहा है लेकिन मैं कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि कब तक यह कार्य पूरा हो जाएगा, इसके अलावा मैं इनको बताना चाहूँगा कि मुख्य मंत्री महोदय ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत बाबरपुर में एक नई अनाज मण्डी स्थापित करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के कहने के अनुसार वहां पर जमीन का फाईनल अवार्ड भी हो चुका है और पेमैंट हो चुकी है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस नई अनाज मण्डी को कब तक बना दिया जाएगा?

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित साथी को बताना चाहूँगा कि जिस बात की अनाउंसमैंट आदरणीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की जाती है उसकी सारी कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर एग्जामिन करवाया जाता है इसलिये ये इस बारे में निश्चिंत रहें क्योंकि ये अनाउंसमैंट मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई है।

श्री शशि रंजन परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि पीछे जो उन्होंने हमारे हल्के के बाँद एवं चांग में परचेज सैंटर्ज बनाने की घोषणा की। धनाना में भी गेंहू की

रिकॉर्ड तोड़ परचेज हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से भिवानी में चारा मण्डी बनाने के लिये आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा उसकी आधारशिला रखी गई थी उसका काम भी तेजी से चल रहा है लेकिन जो बौंद और चांग के परचेज सैंटर बनाने की बात कही गई है मैं उस बाबत उनसे कहना चाहूँगा कि उनका फड़ कच्चा है और उनकी चारदीवारी भी नहीं है। जिसकी वजह से वहां पर पशु घूमते रहते हैं जिसकी वजह से वहां पर किसानों को दिक्कत होती है। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहूँगा कि क्या अगली परचेज होने से पहले पहले इन सैंटर्ज की ये फड़ पक्की करवा दी जाएंगी और वहां की चारदीवारी करवा दी जाएगी?

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथी को बताना चाहूँगा कि मार्किटिंग बोर्ड की तरफ से चाहे वह सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे सब्जी मण्डियों के निर्माण की बात हो या चाहे वह अनाज मण्डियों के निर्माण की बात हो, बड़ी तेजी के साथ इन साढ़े तीन सालों में कार्य करवाया गया है इसलिये इनके कार्यों के बारे में हर तरफ से मार्किटिंग बोर्ड की सराहना हो रही है। आदरणीय साथी ने जैसे बौंद एवं चांग के परचेज सैंटरज़ की फड़ को पक्का बनाने एवं चारदीवारी बनाने के बारे में कहा है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि वहां की फड़ को एवं चारदीवारी को भी जल्दी पक्का करवा दिया जाएगा।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या कैथल में भी कोई नयी सब्जी मण्डी बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री अध्यक्ष : बिसला जी, आप भी अपना सवाल पूछ लें, मंत्री जी इकट्ठा ही जवाब दे देंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी से मैं यह जानकारी भी चाहूँगा और निवेदन भी करूंगा कि सरकार की जो ऐग्रीकल्चर के डाइवर्सीफिकेशन की नीति है इस नीति के परिणामस्वरूप होर्टीकल्चर एवं फ्लोरीकल्चर की खेती का क्षेत्र ज्यादा बड़ा है इसकी प्रोडक्शन भी हुई है। दिल्ली के नजदीक का जो क्षेत्र है जैसे हमारे फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुड़गांव वगैरह का वहां मण्डियों में फल फूल इत्यादि की जो प्रोडक्शन आती है उसकी कोल्ड स्टोरेज की फैसेलिटीज न होने की वजह से उस उत्पादन को एक दिन से ज्यादा रखने की क्षमता नहीं है। लोगों की बड़ी भारी मांग है। इसलिये सरकार की तरफ से या मार्किटिंग बोर्ड की तरफ से जहां अच्छी सब्जी मण्डियां हैं वहां पर अगर बहुत बड़े कोल्ड स्टोर न हों तो छोटे-छोटे कोल्ड स्टोरेज हों ताकि गांव का आदमी फल-फूल, सब्जी स्टोर कर ले और अगले दिन दिल्ली या जहां भी मण्डी में उसको अच्छा रेट मिले वहां ले जाये। क्या मंत्री जी इस प्रकार की कोई सुविधा प्रदान करने की कृपा करेंगे?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा अहम् मुद्दा है इस पर मैं चाहूँगा कि इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को विस्तार से सरकार की पॉलिसी से अवगत कराया जाये। यह श्रेय हरियाणा प्रदेश को जाता है। हमने देश को खाद्यान्न के मामले में विकट परिस्थितियों से उबारने में अहम भूमिका निभाई है आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब के काश्तकारों की वजह से आज देश के अंदर 650 लाख मीट्रीक टन खाद्यान्न गोदामों में भरा पड़ा है। जहां हम दूसरे देशों से कटोरा लेकर अन्न की भीख मांगने जाते थे वहीं अब हम दूसरे देशों को अनाज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। केन्द्र सरकार की पॉलिसी के दृष्टिगत अब हम कृषि का विविधीकरण करने जा रहे हैं, डाथवर्सीफिकेशन करने जा रहे हैं इसके लिये जरूरी है कि खाद्यान्न की बजाय हम सब्जियों को, फलों को, डेयरी को और फूलों की खेती को बढ़ावा दें। इसके लिये सरकार

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

ने हर स्तर पर प्रयास किये हैं और उनमें बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का उत्पादन समय से दूसरे मुल्कों में जा सके उसके लिये हमने दो ड्राई पोर्ट हरियाणा प्रदेश में स्थापित किये हैं एक तो इरसरू में है और दूसरा रेवाड़ी में है उसका अभी उद्घाटन करवाया है इसके साथ ही फल, फूल और सब्जी ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत जल्द उपयुक्त वातावरण न मिले तो खराब हो जाती हैं इसके लिये राई में हमने इसी एक मार्च को 80 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट स्थापित किया है। वहां पर कोल्ड सैंटर की स्थापना की है। उस कोल्ड सैंटर के कारण फल, फूल एवं सब्जी का समय के अनुसार एक्सपोर्ट ही नहीं होगा बल्कि एक तोला भी चीज वेस्ट न हो इसके लिये हर चीज हिसाब से छांटकर दी जाएगी। किस चीज को कैसा कलाइमेट चाहिए उसके हिसाब से उसे उसी टेम्परेचर पर रखेंगे। मिसाल के तौर पर आलू में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और फूल में और सब्जी में कम टेम्परेचर चाहिए उसके दृष्टिगत इस प्रकार का सिस्टम बनाया गया है। हम चाहते हैं कि फल, फूल और सब्जियों के उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके। हमें यह भी मानकर चलना चाहिए कि जब परिवार बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से जोत घटेगी। घटी हुई जोत को पूरा करने के लिये हमें इस तरफ प्रयास करने पड़ेंगे। इसके लिये सरकार प्रयासरत है। इस सदन के सम्मानित सदस्यों की तरफ से कभी भी किसी भी समय इस प्रकार के सुझाव सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनकी वजह से प्रदेश के कृषकों को लाभ मिलेगा उसके लिये हम हर प्रकार के अखराजात को बढ़ावा देने के लिये तैयार हैं ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। आज हरियाणा देश का एक अग्रणी प्रदेश है।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

———

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Declaration Of Palwal as District

* 1335. **Shri Udai Bhan :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under considration of the Government to declare Palwal as district by including the Palwal, Hathin and Hodel Sub-Divisions ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

———

Improvement in Breed of Milch Animals

* **1365 Shri Suraj Mal :** Will the Minister of State for Animal Husbandry

be pleased to State—

(a) Whether any step has been taken by the State Government to improve the breed of the milch animals; and

(b) if so, the details thereof ?

पशुपालन राज्य मन्त्री (चौ० मोहम्मद इलियास) :

(क) जी हां, श्रीमान्

(ख) दुधारू पशु विशेष रूप से विश्व विख्यात 'मुर्राह' नस्ल की भैसों तथा देशी नस्ल की गायों, जैसे कि 'साहीवाल' तथा 'हरियाना' के अनुवांशिक स्टाक में सुधार लाने के लिए सरकार ने एक अधिनियम 'हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशु पालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिक्षण तथा परिवर्धन) अधिनियम, 2001' बनाया तथा इस अधिनियम के तहत गठित हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड तथा विभागीय तन्त्र मुस्तैदी से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य, संक्रामक रोगों की रोकथाम, अच्छे दुधारू पशुओं को इनाम देने तथा अधिक दूध देने वाली भैंसों के कटड़ों का चयन करने में कार्यरत है ताकि अनुवांशिक स्टाक का ऊंची सीमा तक सुधार किया जा सके।

———

Improvement in Quality of Power

*** 1329. Shri Moola Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state the steps taken or proposed to be taken to improve the quality of power supply in district Mahendergarh, if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जिला महेन्द्रगढ़ में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 5 नये उपकेन्द्र जैसे कि महेन्द्रगढ़ में एक 220 के०वी० उपकेन्द्र मुंडियाखेड़ा तथा सतनाली में 132 के०वी० उपकेन्द्रों तथा बावनिया तथा डबलाना में 33 के०वी० उपकेन्द्रों को 2660 लाख रुपए की लागत से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अर्थात् जुलाई 1999 से चालू किया गया है। इसके अतिरिक्त 8 नं० वर्तमान उपकेन्द्रों जैसे कि नारनौल में 220 के०वी० उपकेन्द्र अटेली, महेन्द्रगढ़, कनीनाखास तथा नांगल चौधरी में 132 के०वी० उपकेन्द्रों तथा कॉटी, धानी भटोटा एवं गढ़ी महेसर में 33 के०वी० उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई है।

इसके साथ ही साथ 8 नं० 11 के०वी० ओवरलोडिड फीडरों को 218 लाख रुपए की लागत से 17 नं० फीडरों में द्विभाजित किया गया है। अन्य 12 नं० 11 के०वी० फीडरों का पुनर्वास कार्य इन फीडरों को 33 नं० फीडरों में द्विभाजित करने के लिए प्रारम्भ किया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त महेन्द्रगढ़ तथा नारनौल में वर्तमान 220 के०वी० उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि करने तथा 1058 लाख रुपए की लागत से 220 के०वी० दादरी-महेन्द्रगढ़ एस/सी लाइन का निर्माण करने का प्रस्ताव है। ये कार्य दिनांक 31-3-2003 तक पूर्ण होने सम्भावित है।

———

Burn out rate of Transformers

*** 1317. Shri Balwant Singh Maina :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the State Govt. has taken any concrete steps to arrest the burn out rate of transformers, if so, the results thereof for the last three years ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हाँ, श्रीमान् जी। विभिन्न कदम उठाये जाने के परिणामस्वरूप राज्य में वितरण ट्रान्सफार्मरों की क्षतिग्रस्त दर वर्ष 1999-2000 में 23.27 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2002-2003 (दिसम्बर तक) में 11.90 प्रतिशत हो गई है।

C.B.S.E. Recognised School run on the Land Leased to Vidya Niketan, Faridabad

*** 1367. Shri Krishan Pal :** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether any school recognised by C.B.S.E. is also being run on the land leased to the Vidya Niketan Senior Secondary School, N.I.T. Faridabad which is recognised by the Haryana Govt ;

(b) if so whether it is legal ; and

(c) If not, the action taken by the department so far against the said school ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) :

(क) हाँ, श्रीमान् जी।

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है।

(ग) जाँच पूर्ण होने उपरान्त इस मामले में आगे कारवाई की जाएगी।

Construction of Incomplete Roads

*** 1347. Rao Narender Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the following incomplete roads are likely to be completed :—

1. from Saluni to Guwani (Block Ately) district Mahendergarh ;
2. from Bhungarka to Dhani Khatian (Block Nangal Chaudhry) district Mahendergarh ;
3. from Mandhana to Khanpur (Block Nangal Chaudhry) district Mahendergarh ;
4. from Badkoda to Kutuba pur (Block Ateli) ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : इन चार सड़कों में से क्रम संख्या 1, 2 व 4 पर अंकित तीनों सड़कें सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत ली गई थीं, जो केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना थी व अब इस योजना को बन्द कर दिया गया है। क्रम संख्या 3 व 4 पर जो सड़कें मढाना से खानपुर व बडकौदा से कुतबापुर हैं, उनका कार्य मार्किटिंग बोर्ड द्वारा 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के प्रथम चरण के अन्तर्गत पूर्ण किया जा रहा है। क्रम संख्या 1 एवं 2 की सड़कें भी शीघ्र पूर्ण करने हेतु विचाराधीन हैं।

Tourist Complexes in Jhajjar

*** 1332. Shri Daryao Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Tourist Complex in Jhajjar ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जी नहीं, श्रीमान्।

Improvement in Power Availability

*** 1363. Shri Naphe Singh Jundla :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there has been any improvement in power availability in the State during the tenure of the present Government ; if so, the details of power availability in the State at present as well as the availability in the year 1998-99 both for the State as a whole and for the rural sector ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हाँ श्रीमान्, वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य में बिजली की उपलब्धता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। वर्ष 1998-99 से अब तक राज्य में औसत बिजली उपलब्धता तथा ग्रामीण क्षेत्र को आपूर्ति की गई बिजली की स्थिति निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	राज्य में बिजली उपलब्धता (यूनिट प्रतिदिन लाख में)	ग्रामीण क्षेत्र को आपूर्ति की गई बिजली (यूनिट प्रतिदिन लाख में)
1998-1999	367	184
1999-2000	415	220
2000-2001	447	234
2001-2002	475	244
2002-2003 (जनवरी 2003 तक)	525	272
वर्ष 1998-99 से वृद्धि	43%	48%

Use of Yamuna Water

*** 1354. Shri Bhag Singh Chhattar :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the use of water of Yamuna River during rainy season; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हाँ, श्रीमान् जी! हथनीकुण्ड बैराज से नीचे की ओर पानी लाने वाली प्रणाली की क्षमता बढ़ाई जा रही है।

Restoration of Capacity of Hansi Branch

*** 1371. Shri Shashi Parmar :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to restore the capacity of Hansi Branch, which supplies about 70% of Yamuna Water in WJC Command area; if so, the detail thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हाँ, श्रीमान् जी! हांसी ब्रान्च के तटबन्धों को मजबूत करने व लाईनिंग की मुरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

Providing of Water/Sewerage Projects

*** 1384. Shri Balwant Singh Sadhaura :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether any project for providing of water and sewarage for National Capital Regions Towns of Haryana State has been approved by the Government of India during the year 2002-2003 ; and

(b) if so , the details of the amount earmarked/released for the above said project togetherwith the time by which the project is likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) श्रीमान् जी, हाँ।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत पांच शहरों क्रमश: सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रिवाड़ी, गुड़गांव में जल वितरण और मलनिकास में बढ़ौतरी एवं विस्तार हेतु 7154.56 लाख रुपये की परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वर्ष 2002-2003 के दौरान स्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा 980.00 लाख रुपये की पहली किश्त जारी कर दी गई है। वर्ष 2002-2003 के लिए राज्य सरकार के बजट में 100.00 लाख रुपये अंकित किये गये हैं। यह परियोजना लगभग 4 वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

NABARD Loan for Water Supply in Rural Areas

*** 1375. Shri Bhagi Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any loan has been sanctioned by NABARD for augmenting drinking water supply scheme in rural areas of the State during the year 2002-2003; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जी हाँ, श्रीमान् । वर्ष 2002-2203 के दौरान, नाबार्ड ने 170 गांवों में जलापूर्ति में बढ़ौत्तरी के लिए 49.17 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। यह गांव जिला फतेहाबाद, जीन्द, पंचकूला और सिरसा में पड़ते हैं।

Improvement in Water Supply in Mewat Area

*** 1377. Shri Bhagwan Sahai Rawat :** Will the Chief Minister be pleased to state the steps taken or proposed to be taken to improve water supply in Mewat Area on a sustainable basis ; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) श्रीमान् जी, मेवात क्षेत्र में जलापूर्ति के सुधार के लिए पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए गए है :—

1.	लगाए गए ट्यूबवैल	200 (नम्बर)
2.	बुस्टिंग स्टेशनों का निर्माण	48 (नम्बर)

3.	बिछाई गई पाईप लाईन	422 किलोमीटर
4.	डीसैलीनेशन प्लांट	3 (नम्बर)
5.	लाभान्वित गांव	223 (नम्बर)

6. अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला के नीचे गांव बारोजी में भूजल की कृत्रिम रिचार्जिंग।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में, उपरोक्त कार्यों पर 1896.02 लाख रुपये खर्च किए गए।

(ख) मेवात क्षेत्र में पोषणीय आधार पर जल आपूर्ति में सुधार के लिए निम्नलिखित योजनाएं तकनीकी फिजीबिलिटी स्टडी के लिए सरकार के विचारधीन हैं।

1. यमुना नदी के साथ रैनी वैल्ज का निर्माण करना तथा मीठे पानी की पाईपों द्वारा, मध्याविद बुस्टिंग स्टेशन बनाकर व वितरण पाईप लगाकर मेवात क्षेत्र में लाना।

2. अरावरली पहाड़ियों की श्रृंखला के नीचे वर्तमान पानी के स्रोतों पर भूजल की कृत्रिम रिचार्जिंग के लिए कार्य करना।

Number of Posts of Professors etc. Lying Vacant

1385. Shri Shadi Lal Batra : Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) the number of sanctioned posts of Professors, Assistant Professors, Readers and Lecturers in the Department of Cardiac Surgery, PGIMS, Rohtak at present ; and

(b) whether any posts out of those referred to in part 'a' above are lying vacant, if so, since when ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० एम०एल० रंगा) :

(क)	क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
	1.	प्रोफैसर	1
	2.	सहायक प्रोफैसर/ रीडर/प्राध्यापक	2

(ख)	क्रमांक	पद का नाम	रिक्त पड़े पदों की संख्या
	1.	प्रोफैसर	1 (जून 1988 से रिक्त)
	2.	सहायक प्रोफैसर/ रीडर/प्राध्यापक	1 (जून 2001 से रिक्त)

Sports Stadium, Sonepat

*** 1412. Shri Dev Raj Dewan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Sports Stadium in Sonepat ; and

[Shri Dev Raj Dewan]

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) श्रीमान् जी, नहीं।

(ख) सुभाष स्टेडियम सोनीपत का निर्माण भौहाना रोड पर करवाया गया है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Un-employed Graduates in the State

134. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) districtwise number of un-employed graduates in the State at present ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to give any compensation / unemployed allowance to the aforesaid un-employed graduates ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) 31-12-2002 को राज्य के रोज़गार कार्यालयों में दर्ज बेरोज़गार स्नातकों की जिलावार संख्या निम्नलिखित है :—

जिला	स्नातक	स्नातकोत्तर	कुल
अम्बाला	6732	1012	7744
पंचकुला	2374	340	2714
यमुनानगर	5619	894	6513
कुरुक्षेत्र	5272	830	6102
कैथल	3422	553	3975
करनाल	8796	1438	10234
पानीपत	3107	469	3576
रोहतक	5430	924	6354
झज्जर	3566	496	4062
सोनीपत	5648	646	6294
जीन्द	3673	600	4273
भिवानी	6619	908	7527
गुड़गांव	6969	939	7908

फरीदाबाद	6345	1096	7441
महेन्द्रगढ़	3099	559	3658
रिवाड़ी	4354	546	4900
हिसार	5715	635	6350
फतेहाबाद	1917	274	2191
सिरसा	3710	574	4284
कुल योग	92367	13733	106100

(ख) हरियाणा राज्य के निवासी स्नातक / स्नातकोत्तर पात्र प्रार्थी जो राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं, तथा जो रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा कार्यान्वित 'बेरोजगारी भत्ता योजना' की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, को 100/- रुपये प्रति मास की दर से बेरोजगारी भत्ता दिनांक 1-11-1988 से वितरित किया जा रहा है।

Providing of Electricity Meters free of cost

135. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there is a policy of the Haryana Vidyut Parsaran Nigam or any of its company to provide Electronic/Semi electronic meters or power meters free of cost to the consumers in the State; if so, the amount involved therein ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : नहीं, श्रीमान् जी।

Amount earmarked by HSAMB for Roads

136. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Agriculture be pleased to state the district-wise details of the amount earmarked by Haryana State Agricultural Marketing Board for the construction of roads in the State during the year 2001-2002 ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य में वर्ष 2001-2002 में सड़कों के निर्माण के लिए की गई निर्धारित राशि का जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

क्र०सं०	जिले का नाम	राशि (रुपये लाखों में)
1.	अम्बाला	286.50
2.	भिवानी	190.00
3.	फरीदाबाद	370.45
4.	फतेहाबाद	442.00
5.	गुड़गांव	127.50

[सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू]

6.	हिसार	320.00
7.	जीन्द	548.50
8.	झज्जर	080.00
9.	कैथल	477.00
10.	करनाल	733.50
11.	कुरुक्षेत्र	900.00
12.	महेन्द्रगढ़	198.40
13.	पानीपत	335.00
14.	पंचकूला	050.00
15.	रेवाड़ी	070.00
16.	रोहतक	222.00
17.	सिरसा	1503.35
18.	सोनीपत	419.00
19.	यमुनानगर	176.80
	कुल योग	7450.00

Distribution of Seeds free of cost

137. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether it is a fact that seeds have been distributed to the farmers free of cost on account of drought in the State during the year 2001-2002; if so, the district-wise details thereof ?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : जी नहीं। वर्ष 2001-2002 में राज्य में कोई सूखा नहीं था, अत: उक्त वर्ष में किसानों को बीजों का नि:शुल्क वितरण नहीं किया गया।

Loan Obtained from HUDCO

151. Shri Ram Kishan Fauji : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the amount of loan obtained by the Haryana Government from HUDCO for repairing of roads on 31.03.1999 and 31.01.2003 ; and

(b) whether the aforesaid amount has been incurred in each district of the State ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) दिसम्बर, 2000 से जनवरी, 2003 तक 231.60 करोड़ रुपये की राशि का ऋण हुडको से लिया जा चुका है। फिर भी 31.3.1999 और 31.1.2003 को हुडको से कोई ऋण नहीं लिया गया है।

(ख) ऋण का उपयोग राज्य राजमार्गों/मुख्य जिला सड़कों/अन्य जिला सड़कों के सुधार के लिए सभी जिलों में किया गया है।

स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं/वाक आउट

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी ने एस०वाई०एल० कैनाल की कम्पलीशन के मुद्दे पर डिस्कशन के लिए एक एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है उसके बारे में आपने क्या फैसला किया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : वह कमैंट्स के लिए सरकार को भेजा हुआ है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. कैनाल का मामला एक अहम् मामला है और एस०वाई०एल० प्रदेश के लोगों की जीवन रेखा है क्या सरकार इतनी कमजोर या सुस्त है कि उस पर डिस्कशन करवाने के लिए तैयार नहीं है? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : वह मामला विचाराधीन है, आप सभी सदस्य अपनी सीटों पर बैठ जायें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को तो आपको प्रायरिटी पर लेना चाहिए। यह नहर पूरे प्रदेश की जीवन रेखा है।

श्री अध्यक्ष : एस०वाई०एल० के मुद्दे पर सभी सदस्य काफी बोल चुके हैं। सरकार भी इसका जवाब देगी।

चौधरी भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मसला है। (विघ्न) यह एक अहम मसला है, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सरकार एस०वाई०एल०के मुद्दे पर इतना समय लेती है तो वह सरकार लोगों का क्या भला करेगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : वह कमैंट्स के लिए सरकार को भेजा हुआ है। (विघ्न) हुड्डा साहब, आप बैठें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब दे अगर सरकार इतना समय लेगी तो कैसे होगा। (विघ्न)

चौधरी भजनलाल : स्पीकर महोदय, हम अर्ज कर रहे हैं सारा हाउस इसके प्रति काफी चिन्तित है।

कैप्टन अजय सिंह : स्पीकर साहब, मेरा एक काल अटैंशन मोशन सप्लाई ऑफ पावर के बारे में था, उसका क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष : आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो बिजली की सप्लाई के बारे में था वह 10 तारीख के लिए एडमिट कर लिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सारा काम छोड़ कर एस०वाई०एल० कैनाल की कम्पलिशन के मुद्दे को डिस्कशन के लिए टेक अप करना चाहिए।

चौधरी जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर तो लीपापोती हो रही हैं।

Mr. Speaker : That matter is under considration. प्लीज, आप सब बैठ जाइये।

राव इन्द्रजीत सिंह : यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमें सदन से वाक आउट करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री (ओम प्रकाश चौटाला) : राव साहब, आप इतनी जल्दी वाक आउट करने की क्यों सोच रहें हैं। क्या आप एक सोच लेकर ही हाउस में आते हैं कि वाक आउट करना है।

चौधरी भजन लाल : आपको जवाब देना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप सुनिए, एस०वाई०एल० नहर सारे हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा है। केवल हम लोगों की ही नहीं प्रदेश के दो करोड़ दस लाख लोगों की भावनाओं के साथ ही जीवन भी जुड़ा हुआ है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा हो सके। मैं सदन की जानकारी के लिए कहना चाहूँगा कि इस मामले पर इस सत्र से पहले भी राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान और उससे पहले काफी चर्चा हो चुकी है। यह मामला एडजर्नमैंट मोशन के मुद्दे में नहीं आता जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करके उस पर डिस्कशन की जाए। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। मैं यह बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और केन्द्र की सरकार को 15 दिन का नोटिस भी दिया हुआ है कि आप इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करें। हालांकि पंजाब सरकार के वकील श्री नारोमन ने तो यहां तक प्रयास किया था कि इन दोनों मुद्दों को तलब किया जाये लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात न मानकर 15 दिन के अन्दर जवाब मांगा है। यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूलिंग दी जा चुकी है। फिर भी आप यह मुद्दा उठा रहे हैं। हुड्डा साहब, आपने अपनी पार्टी मीटिंग में यह कहा था कि चौधरी भजन लाल जी 1982 में कागजी मुख्य मंत्री थे। (विघ्न)

आपकी तो आपस में सरवाईवल की लड़ाई है आपको एस०वाई०एल० से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष का नेता कांग्रेस पार्टी के प्रैजीडैंट को कहता है कि आप 1982 में कागजी मुख्य मन्त्री थे फिर भी उस पर चर्चा करते हो, कुछ तो सोचा करो। (शोर) राव वीरेन्द्र सिंह का बेटा सदन में गलत ब्यानी करे यह ठीक नहीं लगता। राव इन्द्रजीत सिंह जी, आप नेम ले कर कहो कि ऐसा नहीं हुआ। आप तो भले आदमी हैं। (शोर)

Mr. Speaker : In rule 68 (III) of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, it is mentioned :—

"(III) the motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence."

इस प्रकार के मुद्दे गवर्नमैंट को कमैंट्स के लिए भेजे जाते हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : भजन लाल जी, आपको तो खबरें छपवानी होती हैं, वाक आउट की कोई खबर नहीं होती, खबर होती है सदन के आधार पर प्रेरित बात की जाए जिसको लोग पढ़ कर कहें कि इनके सामने हरियाणा का हित सर्वोपरि है। (शोर) अध्यक्ष महोदय, इनको आप समझाएं, वीरेन्द्र सिंह का बेटा गलत ब्यानी कर रहा है। (शोर)

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा। (शोर एवं विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : वाक आउट भी कोई समाचार होता है, ये तो फजीहतें होती हैं। रोज वाक आउट का मन बनाकर आते हैं। आप यहां लोगों के हित की बात करो। कोई रचनात्मक

सुझाव दो, हैल्दी क्रिटिसिज्म करो। अभी आप लोगों को विपक्ष की भूमिका निभाने में बड़ा समय लगेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाकआउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के श्री भजन लाल को छोड़कर उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप वाक आउट भी अधूरा करते हो,भजन लाल जी बैठे हैं और बाकी सदस्य वाक आउट कर रहे हैं।

चौधरी भजनलाल : आप रास्ते पर आ जाओ, इसलिए मैं यहां पर बैठा हूँ।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : हमने पूरी छूट दी है, पहले भी हाथ खड़े करवाए थे और अब फिर खड़े करवाएंगे। मैं आप को वादा करता हूँ कि जब मैं 10 तारीख को जवाब दूंगा तो मैं आपको सारे हालात की जानकारी दूंगा। आप रुकोगे तो। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजनलाल : मैं पक्का वादा करता हूँ कि रुकूंगा। स्पीकर साहब और मुख्य मंत्री महोदय दोनों बैठे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कल परसों 8 और 9 तारीख की छुट्टी है, 15 और 16 की भी दो दिन की छुट्टी है। सवाल यह है कि सोमवार को सैशन 9.30 के बजाय 2.00 बजे रखा जाए क्योंकि मैम्बर्ज ने बहुत दूर दूर से आना होता है। इस हिसाब से तो मैम्बर्ज को जाने की जरूरत ही क्या रहेगी।

श्री अध्यक्ष : जाने की जरूरत ही नहीं है। टी०ए० भी नहीं लगेगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में जो बातें तय हो गईं और हाउस से भी उसकी अनुमति मिल गई उसके बाद उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यदि विपक्ष के पास कहने के लिए मुद्दे होंगे तो हाउस का समय और बढ़ाया जा सकता है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कल 1.30 बजे सैशन समाप्त होना था लेकिन चार बजे तक मैंबरों को यहां बैठाकर रखा। इस तरह नहीं होना चाहिए था। हम चाहते हैं कि सोमवार को सैशन सुबह 9.30 बजे की बजाय यदि आप 2.00 बजे नहीं करना चाहते तो इसे 11.30 बजे का कर लिया जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधारी भजन लाल जी, हमने तो सोमवार को 9.30 बजे का समय इसलिए रखा है कि मैंबरों को अपनी बात ज्यादा से ज्यादा कहने का अवसर मिले। आपको पूरा समय दिया जाता है तब भी आप शिकायत करते हैं कि आपको बोलने का समय नहीं मिला। 9.30 बजे इसीलिए सोमवार को सैशन रखा है ताकि आपको और अधिक समय बोलने के लिए दिया जाये और आप शिकायत न करें। सोमवार को सैशन 9.30 बजे ही होगा यह तय हो गया है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यदि समय तय हो गया है तो उसे दोबारा बदला भी जा सकता है। यदि आप समय नहीं बदलते तो हम इसके विरोध में वाक आउट करते हैं।

(इस समय इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भजन लाल सदन से वाक आउट कर गये।)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, चौधरी भजन लाल जी इसलिए वाक आउट करके सदन से बाहर गये हैं कि आपने सोमवार को सैशन का समय 9.30 बजे की बजाय 11.30 बजे

[प्रो० सम्पत सिंह]

नहीं किया। (हंसी) स्पीकर सर, यह तो आपकी और सदन के नेता की फ्राखदिली है कि आप लोग समय का ज्यादा से ज्यादा यूटीलाईज करना चाहते हैं। विपक्ष तो अधिक समय की मांग किया करता है लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहां पर विपक्ष समय कम करने की बात कर रहा है। पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि कल आप तो हाउस का समय 1.30 बजे बाद एक्सटैंड कर रहे थे और विपक्ष के साथी इसका विरोध कर रहे थे और एक एक करके सदन से बाहर जा रहे थे। आखिर में विपक्ष के दो ही सदस्य बचे थे और वे दो भी सैशन समाप्त होने से पहले ही चले गये थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये लोग अपोजीशन की भूमिका के लायक ही नहीं हैं। इनको पता ही नहीं है कि अपोजीशन की भूमिका कैसे निभाई जाती है। स्पीकर सर, आपने सोमवार को सैशन 9.30 बजे को इसलिए किया है कि सभी सदस्यों को अधिक से अधिक समय बोलने के लिए मिले और सभी सदस्य यहां सामाजिक हित की बात करें और दूसरे मुद्दों के बारें में अपनी बात कहें। विपक्ष के साथी नहीं बोलना चाहते तो इन्हें चुप रहना चाहिए, दूसरे मैंबर भी हैं जिन्हें अपनी बातें कहनी हैं। विपक्ष के भाई तो अपनी ड्यूटी के प्रति सीरियस हैं नहीं लेकिन दूसरे सदस्य तो हैं। स्पीकर सर, विपक्ष के भाई तो सदन से बाहर जाकर ही अपने ब्यान देते हैं, पिछली बार भी ये यहां हाउस में तो बिल्ज के बारे में नहीं बोले और बाहर जाकर ब्यान देते रहे। ये बाहर जाकर ब्यान इसलिए देते हैं क्योंकि विधान सभा में तो फैक्टस एंड फिगर्ज के साथ बोलना पड़ता है और फैक्टस एंड फिगर्ज के बारे में इनकी जानकारी है नहीं। स्पीकर सर, विपक्ष के भाइयों को जनता की भलाई से कुछ लेना देना नहीं है ये तो सिर्फ अपना राजनैतिक फायदा देखते हैं। जहां तक मोशन की बात है, आपने यह सरकार के पास कोमैंटस के लिए भेज दिया था और सरकार ने अपना जवाब आज भेज दिया है, शायद आपको मिल भी गया होगा। अब आप अपना फैसला इस पर दे दें।

श्री अध्यक्ष : इस तरह के मोशन अध्यक्ष के विवेक पर होते हैं, फिर भी मैंने यह मोशन सरकार के पास सरकार के कोमैंटस के लिए भेजा, सरकार का जवाब आ गया है और इस पर काफी चर्चा भी हो चुकी है। (विघ्न) कौल एंड शकधर में क्लियरली लिखा हुआ है कि Speaker may, in a proper case, disallow such a motion. The refusal to give consent is in the absolute discretion of the Speaker and he is not bound to give any reason. तो भी इसको मैंने डिसअलाउ करने से पहले सरकार के कोमैंटस मांगे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, चेयर की इजाजत के बगैर बोल रहे हैं इसलिए इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। (शोर एवं व्यवधान) नो-नो ऐसी कोई बात नहीं है। दलाल साहब, अखबार में जो छपा है उसको जो पढ़ना चाहेगा वह पढ़ लेगा, उस बारे यहां कोई चर्चा नहीं होगी। दलाल साहब, प्लीज आप बैठें आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही।

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, अनेकों बार हाउस में इस बारे में चर्चा हो चुकी है कि किसी भी अखबार में लिखे हुए के बारे में यहां हाउस में चर्चा नहीं होगी। इस बारे में इनके समय में भी चर्चा हुई थी और उससे पहले भी हुई थी (शोर एवं व्यवधान) फिर ये अब इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं?

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे डिफरैन्ट पार्टी के मैम्बरों की लिस्ट प्राप्त हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि सभी को उचित समय मिल सके। साथ ही मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि सभी साथी समय का ध्यान रखते हुए डिस्कशन में ठीक तरीके से भाग लें और अपने समय का ध्यान रखें। अब मैं राजिन्द्र सिंह बिसला को डिस्कशन करने के लिए समय देता हूँ।

श्री राजिन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हमारे साथी विधायक श्री उदय भान जी ने प्रस्तुत किया और उसका अनुमोदन श्री रामबीर जी ने किया। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए इसका समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण अपने आप में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और भविष्य की नीतियों और कार्यक्रमों और उसके साथ-साथ चुनौतियों के बारे में प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित करता है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में भी और बाहर भी एस०वाई०एल० पर समय-समय पर चर्चा होती रहती है। आप देख रहे हैं कि विधान सभा का कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन एस०वाई०एल० जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न हुई हो। अभी 15 जनवरी 2002 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय में पंजाब सरकार को इस लिंक नहर का पूर्ण रूप से निर्माण करने के लिए एक वर्ष की अवधि दी गई थी और इसके संबंध में आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में सभी पोलिटिकल पार्टीज के सम्मानित नेतागणों का सर्वदलीय मीटिंगों का आयोजन हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी इस बारे में सभी लोग मिले हैं। मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित साथियों से और विशेषकर सभी राजनैतिक दलों के जो सीनियर पदाधिकारी हैं (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप अपनी सीट पर जाएं। आपने कोई बात करनी है तो आप लोबी में जा कर बात करें। (विघ्न) आप लीडर हो या डिप्टी लीडर हो इसका प्रश्न नहीं है। आप अपनी सीट पर जाओ। यहां पर डिस्कशन मत कीजिए। ऐसी डिस्कशन करने से सभा में शोर होता है। चौधरी भजन लाल जी, आप वहां लोबी में जाकर बात कर लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरे कानों में आवाज आई और मुझे शोर सुना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोबी में जा कर बात करें। बिसला जी आप कन्टीन्यू करें।

श्री राजिन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि यह मुद्दा न केवल सत्ता पक्ष के साथियों से जुड़ा हुआ है बल्कि हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मामले में जितना सदन के नेता का दायित्व है मैं समझता हूँ कि उससे कहीं अधिक जिम्मेवारी आदरणीय चौधरी भजन लाल जी की, हुड्डा साहब की और हमारे जो दूसरे नेता हैं उनकी भी बनती है। हरियाणा प्रदेश के लिए हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मामले में इस सदन के नेता का जितना दायित्व है मैं समझता हूँ कि उससे कहीं आगे जा कर ज्यादा जिम्मेदारी आदरणीय चौधरी भजन लाल जी, हुड्डा साहब और हमारे जो दूसरे नेता हैं उनकी भी बनती है बड़ा भारी उत्तरदायित्व उनका भी बनता है। कई बार जब सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है तो वह चर्चा बढ़ते-बढ़ते हमारे उद्देश्य से बाहर भी भटक जाती है। एस०वाई०एल० अतिशीघ्र बने इसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी अपने पद और गरिमा के हिसाब से प्रयास करें और जो दूसरे सम्मानित नेता आदरणीय चौधरी भजन लाल जी, हुड्डा साहब

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

भी अपने स्तर पर प्रयास करें और अपने केन्द्र के जो नेता हैं, इनकी हाई कमाण्ड हैं या दूसरे नेता हैं उनसे मिल कर बात करें और जितनी जल्दी यह नहर बन सके उसके लिए अपने ढंग से भी प्रयास करें। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग राजनीति से ऊपर उठ कर अगर पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम उन्हें प्रभावित करके इस नहर को बनवाने में कामयाब होंगे। एस०वाई०एल० की लिंक नहर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अतिशीघ्र पूरी होगी और हरियाणा के लोगों की इच्छा के अनुसार जल्दी ही उसमें पानी भी आएगा। जब इस नहर का पानी हरियाणा में आएगा तो जो दक्षिणी हरियाणा है जब उसको पानी मिलेगा तो दक्षिणी हरियाणा के साथ-साथ हमारा जो फरीदाबाद जिला है उसमें भी इस तरीके की व्यवस्था की जाए कि पानी हमें भी मिल सके। इसके साथ ही साथ गुड़गांव में गहलोत जी के क्षेत्र में तथा इसके साथ ही साथ मेवात और फरीदाबाद जिले में भी पानी की कमी है इस नहर का पानी आने से उसको यहां पर जोड़ दिया जाए ताकि इस इलाके में भी पानी की कोई कमी न रहे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सभी राजनीतिक दलों के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उन सभी को इस एस०वाई०एल० के मामले में बहुत ही संयम और गम्भीरता का परिचय देना चाहिए। हरियाणा प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से एक बहुत ही छोटा प्रदेश है लेकिन इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसकी देश के मानचित्र पर जो ज्योग्रोफिकल सिचुएशन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि वैदिक काल से ही हमारा यह क्षेत्र राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। हम सब गौरवशाली हैं कि कुरुक्षेत्र की पावन धरती से भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भगवद गीता का अमर सन्देश समस्त मानव जाति को दिया। पानीपत के मैदान में हुई तीसरी लड़ाई की राजनीति में ऐतिहासिक निर्णायक भूमिका रही है। उस समय राजनीतिक हिसाब से इस लड़ाई ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की धरती का यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस धरती पर स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जैसा कर्मठ, निष्ठावान और कमेरे वर्ग का नेता रहा जिसने सब की भलाई के कार्य किए। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** यहीं पर उन्होंने संघर्ष किया और अपने आवाहन पर समस्त हरियाणा की जनता की 36 बिरादरियों को साथ ले कर देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने प्रधान मंत्री जैसे पद की कुर्सी पर स्वयं न बैठ कर और अपने निजि स्वार्थों को त्याग कर दूसरे लोगों को बढ़ावा दिया। ऐसे प्रदेश के हम रहने वाले हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रदेश में हम रह रहे हैं। इस प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रगति के लिए हर पार्टी का, हर नेतागण का और हर एम०एल०ए० का बराबर का उत्तरदायित्व बनता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा की एक भौगोलिक स्थिति है। हमारे प्रदेश का जो कण-कण है उसमें एक जुझारूपन है, वीरता है, ऐसी बात करते हुए हम सब गौरान्वित महसूस करते हैं। आजादी के बाद देश की अखण्डता के लिए देश की रक्षा के लिए हमारे प्रदेश के शूरवीर नौजवानों ने हंसते-हंसते जान न्यौछावर की है। उन्होंने हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने भारत माता के लिए जान दी है। आज हमारा पड़ौसी देश आतंकवाद का केन्द्र है। वह हमारे देश में नुक्सान पहुंचाने के लिए हीन भावना से कार्य करता है। हर रोज बोर्डर पर किसी न किसी तरीके से टैन्शन क्रिएट करता रहता है। उसकी इन हरकतों की वजह से पिछले दिनों कारगिल की लड़ाई हुई। वहां पर लड़ते हुए हरियाणा के नौजवानों ने जान न्यौछावर की है। सबसे ज्यादा उस लड़ाई में हमारे प्रदेश के नौजवान शहीद हुए हैं। कोई जिला, कोई विधान सभा क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां पर हमारे लड़ाके शूरवीरों की डैड बॉडीज़ न आई हों। सभी ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने सीनों पर गोलियां खाई हैं। ऐसे

प्रदेश को सुदृढ़, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सभी राजनैतिक लोगों के साथ-साथ प्रदेश की जनता की भी जिम्मेवारी बनती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल करते हुए कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिसला जी, आप समय का भी ध्यान रखें। आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गए हैं। मेरे पास 21 सदस्यों की लिस्ट है जिन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करनी है। इसलिए आप समय का ध्यान रखें। (विघ्न)

श्री राजिन्द्र सिंह बिसला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि जब आप समय सीमा निर्धारित करते हैं तो निर्दलीय विधायकों के समय में कटौती न किया करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूँ कि किसी समाज की सम्पन्नता और प्रगति का आधार धर्म है। महर्षि दयानन्द जी ने आर्य समाज की स्थापना एक मापदण्ड को मानते हुए की है। जिस समाज में महिला सुखी है, हमारी माताएं, बहनें और बेटियां सुखी हैं और हंसती खेलती हुई अपनी गृहस्थी चलाती हैं, वह परिवार सुखी रहता है। लेकिन जिस घर में महिलाएं दु:खी हैं, माताएं, बहनें और बेटियां दु:खी हैं वहां पर गृहस्थी ठीक नहीं चल पाती है। मैं अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं तथा दूसरे प्रदेशों में हमारी नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में स्त्री-पुरुष के अनुपात में बहुत ज्यादा फर्क था इसलिए इसी फर्क को ठीक रखने के लिए एवं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए देवीरुपक योजना चलाई गयी। कन्यादान और महिला सशक्तिकरण जैसे बहुत अच्छे कार्यक्रम और नीतियां इस सरकार ने बनायी हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सदन में, सदन से बाहर प्रदेश में और प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों में भी 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम की सभी पार्टियों और लोगों ने बड़ी भारी प्रशंसा की है। मैं समझता हूँ 'डि-सैंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर टू आर्डनरी मैन' यह सरकार इसकी जीती जागती मिसाल है। प्रथम चरण में सारे हरियाणा में 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत 920 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के काम हुए हैं। दूसरे चरण में 956 करोड़ रुपये के विकास के काम हुए हैं जबकि तीसरा चरण दो अक्टूबर, 2002 से आरंभ हो चुका है। हमारे बल्लभगढ़ क्षेत्र में आदरणीय मुख्य मंत्री जी गए और उन्होंने करोड़ों रुपयों की स्कीम्ज की घोषणा की जैसे सारे शहर के लिए सीवरेज डालना, सारे शहर के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करवाना, लाईट एवं सड़कों को ठीक करना और गलियों को पक्का करना आदि। लोगों ने वहां पर इकट्ठे होकर जो मांगा वह आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने हमें दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से नागरिकों के सुखी जीवन के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली भी उपलब्ध होना अति आवश्यक है। बिजली जैसे गंभीर विषय को हमारी मौजूदा सरकार ने प्राथमिकता दी है और पिछले तीन सालों में बिजली की जैनरेशन के लिए नये-नये सब स्टेशंज आगुमैंटेशन का कार्य किया है। जिन सब स्टेशन की क्षमता कम थी उनको अपग्रेड किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इन सभी प्रयासों का अगले दो सालों में सुखद परिणाम होगा और हमें 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। इसी प्रकार से परिवहन विभाग की बात है, सारे देश में सबसे ज्यादा अच्छी बसिज हरियाणा में दी गयी हैं, साफ-सुथरे ड्राईवर एवं कंडक्टर दिए गए हैं और समय पर बसिज का आना-जाना शुरू किया गया है। इसी कारण हरियाणा की रोडवेज की बसिज को देखकर लोग दूसरी बसिज में बैठना पसन्द नहीं करते। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से शिक्षा

[श्री राजिन्द्र सिंह बिसला]

एवं स्वास्थ्य आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के जो देश हैं उनमें यह प्राथमिकता के विषय हैं। पिछले 55 वर्षों में हमने देखा है कि सरकारी स्कूलों में गांवों के आम आदमी का, किसान का और मजदूर का एवं मध्यम वर्ग का बच्चा ही पढ़ने जाता है। हमने देखा है कि इन स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए टाट भी नहीं होते हैं लेकिन मुख्य मंत्री जी और शिक्षा विभाग इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में छोटे बच्चों के बैठने के लिए डैस्क प्रोवाइड करवाने का फैसला किया है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर गरीब आदमी का बच्चा टाट पर या नीचे बैठता है तो उसमें हीन भावना पैदा हो ही जाती है चाहे वह माँ के पेट से कितना ही इंटैलीजैन्ट पैदा क्यों न हुआ हो। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग भी रंगा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। इसी तरह से खेलकूद के बारे में यहां पर कई सवाल हुए, कई सप्लीमैंट्रीज हुईं। हमारी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। इसी का सुखद परिणाम है कि क्रमश: 11 और 14 पदक राष्ट्रमंडल एवं एशियाई खेलों में हमें मिले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात के लिए और सरकार को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि कई बार हमें प्रदेश के हित में ऐसे कठोर निर्णय लेने ही होते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ता है। हालांकि इन निर्णयों की वजह से कई बार हमारे वोटर हाय तौबा मचाते हैं। मिसाल के तौर पर नगर विकास के लिए कई अच्छे निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पहले फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में लोग घुस नहीं सकते थे। जहां पहले चार-चार गाड़ियां जाती थीं वहां अब लोगों का पैदल जाना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन सरकार द्वारा वहां पर एनक्रोचमैंट हटाने का एक अच्छा निर्णय लिया गया है यह हटना ही चाहिए। मुख्य मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने घोषणा की है और इस बारे में एक नीति बनायी है कि सरकारी जमीन पर जो इन्क्रौचमैंट किया हुआ है अब उन सबको हटाया जाएगा चाहे उसमें कोई भी आदमी हो, कितना ही बड़ा हो। हमारे फरीदाबाद जिले में सैकड़ों एकड़ जमीन पर से इन्क्रौचमैंट हटायी गयी है। मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में हमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए। हमारा दिल्ली के नजदीक का एरिया है अगर ऐसे ही इन्क्रौचमैंट होती रही तो फरीदाबाद, गुड़गांव और बहादुरगढ़ में तो एक इंच जगह भी नहीं बचेगी। दिल्ली के नजदीक होने की वजह से हमारे यहां फ्लोटिंग पौपुलेशन है इसलिए हमें राजनीति से ऊपर उठकर जमीन से अनाधिकृत कब्जे हटाने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पर सदन के सभी सदस्यों ने और विपक्ष के सदस्यों ने भी अपने-अपने विचार रखे हैं। कुल मिलाकर हमारी सरकार इस बारे पूर्ण रूप से वचनबद्ध है कि प्रदेश में बैस्ट लॉ एण्ड ऑर्डर दिया जाए और इसके लिए जो सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन है जो हमारी फोर्सिज हैं, पुलिस है उनको पूरी तरह से आधुनिकीकृत और सुसज्जित किया जाये। उसके लिए सरकार न केवल चिंतित है बल्कि बहुत अच्छे निर्णय भी लिए गए हैं। अभी 3 जून, 2002 को हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भौंडसी में चौधरी देवी लाल पुलिस ट्रेनिंग एवं रिसर्च सैंटर की आधारशिला रखने आए थे। सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है कि इन्होंने वहां इन्टैलीजैंस सैंटर भी खोले हैं। पिछली सरकार के समय में एक लिकर माफिया बन गया था। आज कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बच्चे बेरोजगार न हों। आजकल क्राइम करने वाले कारों में आधुनिक शस्त्रों से लैस होकर मोबाइल लेकर चलते हैं इसलिए पुलिस को भी पूर्ण रूप से आधुनिक बनाया जाना बेहद जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की बहुत सारी उपलब्धिया हैं। आप जानते हैं कि हमारा देश, हमारा समाज बहुजातीय और बहुभाषीय है यहां अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। धार्मिक उन्माद की कीमत अगर दुनिया में किसी देश ने सबसे ज्यादा झेली है

तो वह हमारे भारत देश ने झेली है। हमारे देश का विभाजन हुआ, भाई भाई लड़े, बंटवारा हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की हजार भाषायें बोली जाती हैं और कई हजार जातियां हैं लेकिन इन बातों के ऊपर बंटना नहीं चाहिए परिवार की तरह रहना चाहिए। हमारे पड़ौसी देश, जो इस ऋषि मुनियों की पावन धरती को तोड़ना चाहते हैं उनको ऐसा कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। (विघ्न) सब जगह हरियाणा प्रदेश जैसा महौल हो। यह सरकार 36 बिरादरियों को साथ लेकर चल रही है इसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी बधाई के पात्र हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां फलां बिरादरी का मुख्य मंत्री आ जाए तो दूसरी बिरादरी के अधिकारी वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं लेकिन हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहां का बहुत अच्छा महौल है तभी बहुत ज्यादा आर्थिक उन्नति हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत धन्यावाद। इन शब्दों के साथ श्री उदय भान जी ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : अब श्री शादी लाल बत्तरा जी बोलेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों से गुजारिश करूँगा कि सभी सदस्यों को ऐकोमोडेट किया जाएगा लेकिन वे अपनी समय सीमा का ध्यान रखते हुए ही बोलें।

श्री शादी लाल बत्तरा (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। 5 मार्च को राज्यपाल महोदय जब अभिभाषण दे रहे थे तो मैं सोच रहा था कि अभिभाषण में अगर 50 प्रतिशत भी सच्चाई हुई तो हरियाणा में राम राज्य है, सतयुग है। लेकिन जब देखा कि यह तो सपने की बात कर रहे हैं असलियत की बात नहीं कर रहे थे। किन्हीं हालात में देख लें। रोटी, कपड़ा और मकान आदमी की सबसे बुनियादी जरुरतों में आते हैं। सरकार ने इतनी योजनाएं अनाउंस की हैं जो विकास योजनाएं कही जाती हैं लेकिन वे विकास योजनाएं बाद में विनाश योजनाएं बन जाती हैं। आज हम देखते हैं कि हरियाणा में 30-40 पुरानी कालोनियां जो शहरों में बसी हुई थी और वे लोग कमेटी को टैक्स दे रहे थे और वे बिजली, पानी, सीवर की फैसीलिटी ले रहे थे। रोड़ की फैसीलिटी भी थी लेकिन उनको बिना नोटिस दिए ही उन मकानों को गिरा दिया गया और जब कारण पूछा तो बताया गया कि इंक्रोचमैंट हुआ है। इंक्रोचमैंट कब हुआ वह किस प्रकार हुआ और अगर इंक्रोचमैंट भी है तो उनका पौजैशन इतना लम्बा हो गया था कि उस भूमि पर उनका वेल्यूऐबल राईट अप्रूव हो चुका था। लेकिन बिना नोटिस दिए, बिना कारवई किए, बिना आदेश दिए वे मकान गिरा दिए गये। मकान गिरने के बाद उन बेचारों की कितनी दुर्गति हुई वो बच्चे जो शिक्षा के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। परीक्षाएं सिर पर थीं उनका कितना नुकसान हुआ है यह गिनती में नहीं आ सकता। अगर ऐसी ही विकास योजनाएं हैं जिसमें हमारे कुछ भाई घर से बेघर हो जाएं तो हम उसको विकास किस प्रकार कह सकते हैं। सड़कों के क्षेत्र में हम देखें तो ये कहते हैं कि हमने सड़को का जाल बिछा दिया, नई सड़कें बिछाई हैं। लेकिन जो पुरानी सड़कें थीं उनकी मेनटीनैंस कितनी हुई। पिछले सैशन में मैंने एक प्रश्न उठाया था। मुझे आश्वासन दिया गया था कि रोहतक की सड़कें सितम्बर, 2002 तक मुकम्मल हो जायेंगी और ठीक हो जायेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कहता हूँ कि झज्जर रोड़ पर जो काठमण्डी है, काठमण्डी की सड़क कंकरीट की बन रही थी लेकिन इस सरकार के आने के बाद वह सड़क वहीं रुक गई और आज भी वहीं रुकी हुई है इसकी एक साईड बनी हुई है और एक साईड नीची है और दोनों किनारों के लैवल में डेढ़ फुट का फर्क है। उस सड़क की एक दिशा में ही जाया जा सकता है उसी रोड़ पर आ सकते हैं। बाकी जो पड़ी है उस पर बारिश का पानी रुक जाता है तब यातायात रुक जाता है, जाम भी लगा

[श्री शादी लाल बतरा]

रहता है। इसी प्रकार लेबर चौक से अगर हम जगदीश कालौनी की तरफ जायें वह 60 फीट चौड़ी सड़क थी लेकिन आज उस पर हम जा नहीं सकते, वाहन तो जाने की बात दूर रही पैदल भी जाना वहां मुश्किल हो जाता है। खासकर बारिश के दिनों में वहां पानी ही पानी भर जाता है। तो यह विकास की योजनाएं किस प्रकार हैं। फिर हम देखते हैं शिक्षा के लिए महामहिम ने कहा कि नई यूनिवर्सिटी बन रही हैं। नये कॉलेजिज और नये स्कूल खुल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो पुरानी यूनिवर्सिटी है उनका क्या हाल है। एम०डी० यूनिवर्सिटी, रोहतक को बने हुए कई साल हो गये लेकिन वहां आज कितने पद खाली पड़े हैं, जो सैंक्शंड पोस्ट हैं वे खाली पड़ी हैं। वे भरी नहीं जा रही हैं। इसके कारण के लिए न तो सरकार अपना कोई ब्यान देती है न बताती है कि किन कारणों से ये पोस्टें नहीं भरी जा रहीं। क्या फाईनैंस की वजह है, या अच्छे लैक्चरर मिलते नहीं। पिछले 5 सालों में वहां कोई भर्ती नहीं हुई है और एक पोस्ट जो दो महीने पहले सैंक्शन हुई थी, इन्टरव्यू हुआ, उस इन्टरव्यू में उपाध्यक्ष महोदय एक्सपर्ट ने ओपीनियन खिलाफ दी थी, हैड ऑफ दि डिपार्टमैंट ने अपनी ओपीनियन खिलाफ दी और दूसरे जो थे उन्होंने अपनी ओपीनियन खिलाफ दे दी लेकिन उसकी नियुक्ति हो गई। क्या यह गुणों के आधार पर नियुक्ति हो रही हैं या सिर्फ मुँह दिखावे के आधार पर नियुक्ति हो रही हैं। कॉलेजिज में देखें कि सिंगल हैंड डिपार्टमेंट है। उस पद से अगर लैक्चरर चला जाता है तो उसके स्थान पर नियुक्ति नहीं होती उसके कारण बच्चों को कितना नुकसान होता है। उनके लिए क्या कार्यवाही होनी चाहिये यह तो सरकार को सोचना चाहिए। अगर यह सरकार समय रहते इस बारे में नहीं सोचती है तो शिक्षा के प्रति जो योजनाएं हैं वे प्रदेश को विकास की तरफ नहीं ले जायेंगी। बल्कि विनाश की ओर ले जायेगी। शिक्षा हर नौजवान की, देश की मूलभूत जरूरत है और विकास के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है जिसके लिए हर प्रकार की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन शिक्षा के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं है। अगर स्वास्थ्य की तरफ देखें तो स्वास्थ्य के बारे में आज मेरा एक प्रश्न था कि रोहतक में मैडीकल कॉलेज में कॉर्डिक सर्जरी में कितने प्रोफैसर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 1988 से प्रोफैसर की वैकेंसी खाली पड़ी है। सरकार ने लाखों रुपये लगाकर वहां कॉर्डिक ओपेरेशन करने के लिए सुविधा तो बना दी लेकिन वहां प्रोफैसर नहीं तो वह जो इक्विपमेंट लिए गये वे किस लिए लिये गये क्या अपने आप ऑपरेशन हो जायेंगे। 3 जनवरी को ट्रिब्यून में एक खबर छपी थी कि एक धीमान नाम का व्यक्ति वहां ऑपरेशन कराने गया और ऑपरेशन टेबल पर उसकी डैथ हो गई, डैथ के कारण क्या थे आज तक कोई जांच नहीं हुई। डैथ का कारण एक ही था कि वे इस योग्य ही नहीं थे कि उनका हार्ट का ओपरेशन रोहतक में हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हम क्लेम करते हैं कि हमने बिल्डिंग बना दी, एक तरफ हम क्लेम करते हैं कि हमने लाखों रुपया लगा दिया, हमने सीटी स्कैन लगा दी, एम०आर०आई० कर रहे हैं लेकिन उसको चलाने के लिए योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं हो रही है, क्या योग्य व्यक्ति मिलते नहीं, या फिर टर्म्ज एण्ड कंडीशंज ऐसी हैं कि योग्य व्यक्ति आना नहीं चाहते। इसका एक फैसला करना चाहिए। सरकार इस बारे में चिंता नहीं कर रही, हम विकास के लिए बात कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि हमें स्वच्छ जल मिले और इसके लिए सीवरेज सिस्टम ठीक होना चाहिए। आज रोहतक में पचासों कालोनियां हैं जिनको बने हुए आज 50 साल से ऊपर का समय हो गया है, वहां साफ पानी की एवेलेबिलिटी नहीं है, वहां के लोगों को आज तक साफ पानी नहीं मिला, वहां लाइनें नहीं बिछी हुई हैं। करतारपुरा एक ऐसा एरिया है जो इन्दिरा कालोनी के साथ लगता है, उसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं और सुविधा किसने देनी है, वह सुविधा सरकार ने देनी है लेकिन सरकार इस पर चुप है। अगर पानी नहीं मिला, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है और दूसरी सुविधाएं नहीं मिली तो हम किस प्रकार

से विकास कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बत्तरा जी, आप ब्रीफ करें। फिर मांगे राम जी समय की बात करेंगे, सभी को एडजस्ट करना है। (शोर)

श्री शादी लाल बत्तरा : उपाध्यक्ष महोदय, जब हम चहुंमुखी विकास की बात करते हैं तो हमें सोचना होगा कि हम किस प्रकार से विकास चाहते हैं और वह विकास जो हम कर रहे हैं उसमें लोगों की भावनाएं और जरूरीयात कैसे जुड़ी हुई हैं। अगर लोग इसको विकास नहीं मान रहे तो हमें यह सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अभिभाषण सुनने से या पेपर पर रिपोर्ट आने से बात नहीं बनती, उसको प्रैक्टिकली कैसे लिया जाए, उसको क्या शेप दी जाए इसके लिए हमें सोचना होगा। जहां तक शिक्षा की बात हम कर रहे थे, आज से 14 साल पहले यूनिवर्सिटी में मैरिट प्रमोशन स्कीम आई थी, जो लैक्चरार 8 साल तक सेवा कर चुके, उनको रीडर और जो 8 साल तक रीडर की सेवा कर चुके, उनको प्रोफैसर प्रमोट कर दिया गया। यह स्कीम 14 साल पहले आई थी और उस स्कीम का विरोध किया जा रहा था। उस वक्त हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने भी प्रोटैस्ट किया था, विधान सभा में भी किया था और विधान सभा के बाहर भी किया था। वह सरकार चली गई और आज यह सरकार आ गई तो मुख्य मंत्री ने वही चीज जिसका ये विरोध कर रहे हैं और इसकी मांग कर रहे थे, वह आज तक पूरी नहीं की, आज ई०सी० में लैक्चरार की रिप्रैजैंटेशन नहीं है वहां 14 साल पहले जो लैक्चरार प्रमोट हुए थे, वे आज डिमोट हो गए हैं, 14 साल तक कोई प्रोफैसर बना रहा, कोई रीडर बना रहा और वे बढ़ी हुई तनख्वाह लेते रहे, आज वे बेघर हो गए हैं। उनकी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस खतरे में पड़ गई है। उपाध्यक्ष महोदय, वे हाई कोर्ट में चले गए हैं तो क्या यही हमारा विकास है कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको हम मजबूर कर दें कि अगर उन्होंने इंसाफ लेना है तो वे हाई कार्ट में जाएं। यह प्रजातंत्र है, चुनी हुई सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती और हर बात का समाधान कराने के लिए अगर हम हाई कोर्ट में जाएं तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह विकास की निशानी नहीं हैं बल्कि विनाश की निशानी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि एम०डी० यूनिवर्सिटी में 14 साल बाद जो लैक्चरार डिमोट हुए हैं उनकी कोई गलती नहीं है, वे कानून के मुताबिक ही प्रमोट हुए थे। उनके ई०सी० ने एप्रूवल भी दे रखी थी। उनकी डिमोशन न करके उनको बहाल किया जाए, उनको हाई कोर्ट के चक्कर लगाने से या लिटीगेशन में खर्च करने से बचाया जाए तो ठीक रहेगा। अभी यहां ट्रोमा सैंटर की बात हो रही थी कि हम चारों तरफ ट्रोमा सैंटर खोल रहे हैं। ट्रोमा सैंटर रोहतक में भी बना था, बिल्डिंग भी बन गई थी, पैसा भी खर्च हो गया था लेकिन रोहतक के लोगों की बदकिस्मती से वह सैंटर शुरू नहीं हो पाया। वह ट्रोमा सैंटर मैडीकल कॉलेज से ऐसा कनैक्टिड नहीं है क्योंकि वहां से कोई पेशैंट सीटी स्कैन के लिए, एक्सरे के लिए आना चाहे तो वहां कोई कवर्ड जगह नहीं है उनको धूप या बारिश से होकर आना पड़ता है। वह ट्रोमा सैंटर ट्रोमा सैंटर न बनकर सर्जरी का डिपार्टमैंट बना दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार एक तरफ तो हाई वेज पर ट्रोमा सैंटर खोलकर लोगों की लाईफ सेव करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ जहां रोहतक में ट्रोमा सैंटर बना हुआ है जिस पर काफी पैसा खर्च हो गया है। रोहतक वालों का क्या कसूर है कि उस ट्रोमा सैंटर की बिल्डिंग में ट्रोमा सैंटर न खोलकर वह बिल्डिंग एक ऐसे विभाग को दे दी जिसकी उस की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बारे मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार की इस तरह की

[श्री शादी लाल बत्तरा]

पॉलिसी लोगों के हित की पॉलिसी नहीं है, ऐसा करने से हरियाणा के लोगों का विकास नहीं होगा। सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे हरियाणा के लोगों का विकास हो और लोगों को लगे कि यह उनकी सरकार है और उनके लिए काम कर रही है लेकिन सरकार की भेदभाव की नीतियों के कारण आज लोगों में सरकार के प्रति बिल्कुल विश्वास नहीं है। इस भेदभाव के कारण आज लोगों में सरकार के प्रति बहुत रोष है। पिछले दिनों मुख्य मंत्री जी 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में रोहतक गये थे वहां मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही जो बहुत गलत थी। पता नहीं मुख्य मंत्री जी ने यह मजाक में कहा, मखौल में कहा या सीरियसली कहा कि रोहतक वालों ने हमारे साथ क्या किया है, हम आप का विकास क्यों करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि ये सारे हरियाणा के मुख्य मंत्री हैं, किसी ने इनको वोट दिया या नहीं दिया, किसी ने कुछ किया या नहीं किया अब ये हमारी आशाओं के केन्द्र बिन्दु हैं इसलिए हमारी आशाओं को पूरा करें और लोगों की समस्याओं को दूर करें। रोहतक वालों को भी उतना ही सहयोग दें जितना की हरियाणा के दूसरे हिस्सों को दे रहे हैं। रोहतक में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं जिनको दूर करना बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : बत्तरा जी, आप वाईंड अप करें, अपनी बातें दोबारा रिपीट न करें। आप दो मिनट में वाईंड अप करें।

श्री शादी लाल बत्तरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिपीट नहीं कर रहा। मैं रोहतक को रिप्रैजैंट करता हूँ और रोहतक की समस्याओं के बारे में बता रहा हूँ कि तीन साल से रोहतक के लोगों की जो समस्याएं हैं वे ज्यों की त्यों हैं। यह मैं मानता हूँ कि वहां पर चौराहों और पार्कों को तोड़कर सौंदर्यकरण किया जा रहा है और स्टेच्यू लगाये जा रहे हैं लेकिन जब लोगों को पेट भरने के लिए रोटी ही नहीं मिलेगी तो सौंदर्यकरण का क्या फायदा। रोहतक के अंदर पिछले 40-50 सालों से जो दुकानें दुकानदारों के पास हैं और दुकानदार अपनी रोजी रोटी उन्हीं दुकानों से कमाते हैं उन दुकानों का डिमोलिशन किया जा रहा है। कहते हैं सड़कें चौड़ी करेंगे, सड़कें चौड़ी करें ठीक है। लेकिन जब पिछले 40-50 साल से उन दुकानों पर उनका कब्जा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वे दुकानदार कहां जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बत्तरा जी, आपने इन्क्रोचमैंट से बोलना शुरू किया था और फिर उसे दोहरा रहे हैं।

श्री शादी लाल बत्तरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोहरा नहीं रहा बल्कि यह मामला सौंदर्यकरण से जुड़ा हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि किसी की रोजी-रोटी को छीनकर सौंदर्यकरण किया जायेगा तो उस का क्या लाभ है? रोहतक के अन्दर मैडीकल कॉलेज मोड़ पर दो-तीन साल पहले सरस्वती की मूर्ति लगाई गई थी लेकिन अब उसको हटा दिया गया है, हमें तो पता नहीं वह क्यों हटाई गई है और उसकी जगह वहां क्या लगेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि क्या सरकार की पालिसीज दो या तीन साल के लिए होती हैं। इसी तरह भिवानी स्टैंड पर एक फुटपाथ बनाया गया था, वह भी तोड़ दिया गया। वहां पर एक शिव मंदिर भी बनाया गया था जिसका शिलान्यास और उद्घाटन उपायुक्त महोदय ने किया था, उसको भी आज हटाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की पालिसीज शोर्ट टर्म नहीं होनी चाहिएं, लौंग टर्म होनी चाहिएं।

श्री उपाध्यक्ष : बत्तरा जी, आप वाईंड अप करें। आपको बोलते हुए 22 मिनट हो गये हैं।

श्री शादी लाल बत्तरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार जो भी प्लानिंग करे वह लौंग टर्म प्लानिंग करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो-तीन साल पहले कोई चीज बनवा दो और फिर उसको तोड़कर कुछ और बना दें। इससे जनता का पैसा भी जाया होगा और अधिक विकास भी नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री लच्छमन दास अरोड़ा (सिरसा) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया। हाउस में राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण पढ़ा मैं समझता हूँ कि यह सरकार का बनाया हुआ एक अभिभाषण होता है। यह प्रथा चली आ रही है कि हर साल राज्यपाल महोदय, हाउस में सरकार ने उनको जो अभिभाषण बना कर दिया होता है वह वे यहां बोलते हैं। इसमें काफी कुछ असत्य होता है और कुछ सत्य होता है। इस बारे में मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह जो हाउस में महामहिम राज्यपाल महोदय, ने अपने अभिभाषण में पढ़ा है उसमें उन्होंने जो गलत था उसको इग्नोर कर दिया और आगे चलते गए और उनको जो सही लगा उसको पढ़ा। मेरे सीनियर साथियों ने बहुत विस्तार से अभिभाषण पर बोलते हुए अपने विचार दिए, मैं उस विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं एस०वाई०एल० पर ज्यादा विस्तार से नहीं बोलना चाहता क्योंकि हर साथी ने एस०वाई०एल० पर बात की है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय, को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एस०वाई०एल० मुद्दे पर खास ध्यान दिया है। मैं अपने हल्के की समस्याओं की तरफ ही सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं इधर-उधर की बातों पर ज्यादा समय गंवाना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : ये मान रहे हैं कि एस०वाई०एल० पर छिक कर डिस्कशन हो चुकी है।

श्री लच्छमन दास अरोड़ा : एस०वाई०एल०के बारे में मेरा कहना है कि इस पर काफी बहस हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि एस०वाई०एल० का पानी हरियाणा के अन्दर आना चाहिए।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : इन्होंने बाकायदा राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण का धन्यवाद किया है तो इसका मतलब है कि इनकी तरफ से सरकार का भी धन्यवाद हो गया।

श्री लच्छमन दास अरोड़ा : सरकार जो तैयार करके देती है वह उन्होंने पढ़ा है। यह कोई आपकी सरकार की बात नहीं है यह हर सरकार के समय में ऐसा ही होता है।

प्रो० सम्पत सिंह : अरोड़ा साहब, आप बहुत समझदार हैं और बहुत सयाने हैं, बुद्धिजीवी हैं और इनके सुझाव बहुत अच्छे हैं। ये हुड्डा साहब के ग्रुप के नहीं हैं।

श्री लच्छमन दास अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की बात करना चाहूँगा। जहां तक सिरसा शहर का सवाल है, उसमें डिवैल्पमेंट की झड़ी लगा रखी है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। वहां पर हर इशू पर डिवैल्पमैंट हो रही है। जैसे कि सड़कें हैं, बिल्डिंगज हैं उन पर जो काम हो रहा है वह ठीक नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता कि सी०एम० साहब को इस बात का पता हो कि कामों को जिनसे करवाया जा रहा है उनको बगैर टैण्डर के और बगैर कुटेशन के काम दे दिया जाता है। जिनको काम देना होता है उनकी एक लिस्ट बन जाती है कि यह काम उसको दे दो और वह काम उसको दे दो। जो पुराने कान्ट्रैक्टर थे या जो ठेकेदार थे उनको किसी को भी ठेका नहीं दिया गया बल्कि नए लोगों को ठेका दिया जाता है और आगे वे ठेके को सब-लैट कर देते हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : क्या शराब के ठेके दिए जाते हैं। किस जगह पर ठेके ठीक नहीं दिए जा रहे।

श्री लच्छमन दास अरोड़ा : मुझे हर जगह का पता नहीं है। मैं तो अपने सिरसा जिले की बात करता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि सड़कों पर खूब जोर सरकार ने लगा रखा है। इस बारे में मेरा कहना है कि सड़कें बनती जा रही हैं और पीछे टूटती जा रही हैं। वहां पर जो मैटीरियल लगाया जा रहा है उस पर कोई चैक नहीं है, यह बात सरकार के नोटिस में है या नहीं इस बारे में मुझे नहीं पता। यहां पर सड़कों, बाई-पास और ओवर ब्रिज बनाने की भी चर्चा चली लेकिन यह उम्मीद नहीं कि ये कब बनेगी। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि सिरसा में रेलवे क्रासिंग जब ट्रेन आने की वजह से बंद होता है तो वहां पर बहुत भारी भीड़ हो जाती है और वहां से निकलने के लिए लोगों को घण्टों लग जाते हैं, इससे लोगों को बड़ी मुश्किल होती है। हमने इस बारे में पहले भी एक प्रपोजल दे रखी है और मैं अब फिर मुख्य मंत्री महोदय से यह रिक्वैस्ट करना चाहता हूँ कि वहां पर बरनाला रोड से सिरसा रेलवे क्रासिंग और उससे आगे ट्रक यूनियन के फाटक तक जो दो किलोमीटर का टुकड़ा है अगर वह बन जाये तो उस रोड़ से लाईट व्हीकल्ज निकल सकते हैं जिससे मेन रोड पर ट्रैफिक का कम जोर होगा। यानि न्यू टाउन एरिया का ट्रैफिक सारा इधर से निकल सकता है। अत: मेरी मांग है कि इस रोड को व ओवर ब्रिज को जल्दी से जल्दी बनाया जाये। अब रेनी सीजन आने वाला हैं। हमने पहले घग्घर पर बांध बनाने के लिए काम शुरु किया था। मुझे नहीं पता कि काम को क्यों रोक दिया गया। अगर बरसात के समय में वहां पर बाढ़ आ जाती है तो वहां पर 14 गांवों का बहुत बुरा हाल होगा। इसी प्रकार से वहां पर जो इन 14 गांवों के लिए रिंग बांध बनने थे उनका काम भी आधा छोड़ा हुआ है। यदि इन गांवों के ये रिंग बांध नहीं बने तो ये गांव रेनी सीजन में डूब जायेंगे और न फिर वहां से पानी निकल पायेगा जिस कारण से उन लोगों का बहुत बुरा हाल और नुकसान हो जायेगा। अत: मेरी सरकार से यह विनती है कि वहां पर जो बांध बनाया जाना है उसको पूरा किया जाये नहीं तो ये 14 गांव तबाह हो जाएंगे। इसी प्रकार से वहां पर एक श्मशान भूमि की रोड है उसकी भी बुरी हालत है। मैं चाहता हूँ कि रोड की पुख्ता हालत की जाये ताकि लोगों को शमशान जाने के लिए दो किलोमीटर का लम्बा चक्कर न काटना पड़े। अत: मेरी मांग है कि सरकार इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाने की कृपा करे। अन्त में मैं ज्यादा न कहते हुए जो कार्य मैंने सरकार के नोटिस में लाये हैं, उनको पूरा करने की कृपा करे। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

राव धर्मपाल (सोहना) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 5 मार्च को महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ कर सुनाया है, मैं उस पर चर्चा करने के लिए उठा हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज सैशन का तीसरा दिन है और गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए हर पार्टी के वक्ता ने एस०वाई०एल० का मुद्दा उठाया है। मैं समझता हूँ कि एस०वाई०एल० का मुद्दा हरियाणा प्रदेश के लिए जीवन रेखा तो है ही उसकी आवश्यकता भी बहुत ज्यादा है। विभिन्न पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर दोषारोपण किये हैं और कहा है कि मैंने इसका इतना काम किया और मैंने इसका इतना काम किया। यहां पर बैठे-बैठे मैं यह सोच रहा था कि कुछ लोग हैं जिन्हें इसके वर्तमान में फायदा है इसमें हरियाणा का जो हिस्सा है उसमें वह अपनी-अपनी भाप निकालना नहीं चाहते हैं मैं इतना जरूर कहूँगा कि इसका अगर कहीं सब से ज्यादा लाभ हो सकता है तो वह दक्षिणी हरियाणा को हो सकता है। बिसला साहब कह रहे थे बल्लभगढ़, गुड़गांव, सोहना, पटौदी, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़ क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर सभी साथियों को मिल कर इसके लिए प्रयत्न करने चाहिएं अगर यह पानी मिल

जाता है तो हमारा हरियाणा प्रदेश विशेष तौर पर दक्षिणी हरियाणा सुख की सांस लेगा और विकास की तरफ चलेगा इसके लिए पानी का बंटवारा भी एक समान होना चाहिए और सब को बराबर पानी का हिस्सा मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शिक्षा के बारे में बात आई है। शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जो नीति है उसमें जो रैशनेलाईजेशन का मामला चल रहा है और जो चर्चा है मैं समझता हूँ कि उस पर सरकार को विचार करना चाहिए क्योंकि जैसे कि इसमें जाहिर है कि सरकार की मन्शा अध्यपाकों की संख्या कम करने की है। स्कूलों के 40 से 60 और कॉलेजों के 60 से 80 बच्चों के लिए एक सैक्शन करना या एक कमरा करना भी सम्भव नहीं हो पाएगा। एक सैक्शन में या एक कमरे में 60 अथवा 80 विद्यार्थियों के लिए बैठ पाना भी सम्भव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करके इस नीति को सही ढंग से लागू करे। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात बिजली की आई। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जैसे आंकड़े दिए गए हैं कि 20 अगस्त 2002 को 698 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध करवाई गई है जो कि एक रिकार्ड है। यह रिकार्ड तो बहुत अच्छा है। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि 41 प्रतिशत बिजली किसानों को उपलब्ध करवाई गई है। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता में ऐसा नहीं है और आज भी किसान के लिए बिजली नहीं हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। वहां पर एक दिन तो रात को और एक दिन सुबह बिजली आती है। जब सुबह बिजली आती है तो वह भी ट्रिप कर जाती है। यह तो भगवान का शुक्र है कि बरसात हो गई नहीं तो किसान बर्बाद हो जाता। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि किसानों को पूरी बिजली मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं उद्योगों के बारे में कहना चाहूँगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह दर्शाया गया है कि 140 मध्यम दर्जे के उद्योग लगे हैं और उनमें 1 लाख 54 हजार नौजवानों को रोजगार मिला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि इनमें कितने हरियाणा के और कितने बाहर के नौजवान हैं? उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जिन लड़कों ने आई०टी०आई० और दूसरी टैक्नीकल डिग्रियां प्राप्त की हुई हैं वे बेकार घूम रहे हैं। हमारे लड़के जब इन इन्डस्ट्रीज में इन्टरव्यू के लिए जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि कहां का रहने वाला है। जब वह यह बताता है कि मैं मानेसर, मडास, जाडस वगैरह का रहने वाला हूँ तो उसको कहा जाता है कि अभी जाओ बाद में देखेंगे। अगर उनकी जगह पर कनार्टक, बंगाल और मद्रास का कोई लड़का आता है तो उसको भर्ती कर लिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आगे जो भी उद्योगों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाए उसमें ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिस किसान की भूमि अधिग्रहण की जाए उसको या उसके परिवार के किसी एक सदस्य को वहां पर लगने वाली फैक्टरी में उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए क्योंकि जिस किसान की भूमि अधिग्रहण की जाती है उसके पास उस जमीन के अलावा आमदनी का और कोई साधन नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपाल जी, आप तो मंत्री रहे हैं आप कोई सुझाव दें।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कांग्रेस की सरकार के वक्त में ए०डी०सी० की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी तो उसमें इन्डस्ट्रीज के नुमायंदे बुलाए जाते थे और वहीं लड़कों के इन्टरव्यू लेकर नौकरियां दे दी जाती थीं। मेरा निवेदन है कि अगर और कुछ नहीं है तो इस तरह की कार्यवाही फिर से यह सरकार शुरू कर दे तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह बताएं कि उस कमेटी का रिजल्ट कैसा रहा था।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हालात हैं इससे तो अच्छे हालात थे। उपाध्यक्ष

[राव धर्मपाल]

महोदय, दिल्ली की सरकार ने ऐलान किया है कि अगर किसी की कोई जमीन ऐक्वायर की जाएगी तो उसको 23 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। मेरा सरकार को सुझाव है कि गुड़गांव, फरीदाबाद और दूसरे जो जिले दिल्ली के आस पास लगते हैं वहां पर जो जमीन ऐक्वायर की जाए दिल्ली की तरह ही हरियाणा सरकार अधिग्रहण करे उस को भी वही रेट दिए जाने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़कों की बात है, जो नैशनल हाई-वेज और स्टेट हाई-वेज हैं उनकी स्थिति तो ठीक है लेकिन जो ऐप्रोच रोड्ज हैं वे बहुत ही खराब हैं। इस सरकार को उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जहां पर सड़कें इतनी टूटी हुई हैं कि उन पर बसिज भी नहीं जा सकतीं जिसकी वजह से लोगों को खासकर बच्चों एवं लड़कियों को बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, आप ऐसी दो चार सड़कों के नाम बता दें।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, बादशाहपुर से शक्रपुर वाया पलड़ा एक ऐसी रोड है जिसमें मेरे ख्याल से हर दो फुट में एक गड्ढा है। इसी तरह से खैर कितोला से सिकन्दरपुर बड़ा एवं दिल्ली अलवर रोड यानि कि सोहना से गढ़ी बाजीदपुर और अल्लीपुर से रायसीना की रोड की भी ऐसी ही हालत है।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो क्रशर जोन की वजह से है।

राव धर्मपाल : इसी तरह से सोहना से बाडुदा की रोड है ये ऐसी रोडज हैं जिनकी मुरम्मत करना बहुत जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, एक नयी बात का आजकल सामना करना पड़ रहा है। अख़बारों और जनता के बीच में भी यह बात सामने आ रही है। आज गांवों में और शहरों में तोड़ फोड़ चल रही है। शहरों में तो यह पहले भी चलती रही है लेकिन गांवों में अब यह सिलसिला चल रहा है कि जहां सरकारी जमीन पर मकान बनाये हुए हैं वहां पर उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हुड्डा के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वह पहले तो देखते रहते हैं कि बगैर अनुमति के बगैर सरकार की परमिशन के इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगर सरकारी जमीन पर बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ये अधिकारी और कर्मचारी पहले क्यों देखते रहते हैं। जब वह कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है तो फिर हुड्डा की तरफ से लोगों को नोटिस दिए जाते हैं कि आपका यह निर्माण अवैध है इसलिए क्यों न इसको तुरन्त गिरा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, पहले हंसाओ और फिर रुलाओ यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस बात से कोई फायदा नहीं है। अगर उनको पहले ही इस तरह की कंस्ट्रक्शन करने से रोक दिया जाए, पहले ही नोटिस दे दिए जाएं तो फिर इस तरह की इल्लीगल कंस्ट्रक्शन लोग नहीं करेंगे। अगर बाद में उनके मकान वगैरह तोड़े जाते हैं तो इससे लोगों में हाहाकार मचता है जिससे मैं समझता हूँ कि सरकार की बदनामी तो होती है और साथ ही साथ लोगों को भी दुख होता है।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, जो पुरानी सरकारों के वक्त में मकान वगैरह बने हुए हैं उनका क्या होगा? जो इनकी सरकार के वक्त में या दूसरी सरकारों के वक्त में नाजायज मकान बने हुए हैं उनका क्या होगा क्योंकि हमारी सरकारी के वक्त में तो एक इंच भी कहीं पर इस तरह का निर्माण नहीं हुआ है। राव साहब, बताएं कि जो नाजायज निर्माण पहले की सरकारों के वक्त में हुआ है वह तोड़ी जाए या नहीं तोड़ी जाए?

राव धर्मपाल : सर, इस तरह का मसला तो पहले से ही चल रहा है। अगर इल्लीगल है तो आप इस तरह की कंस्ट्रक्शन को मंजूर कर दो।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : कंस्ट्रक्शन कहीं भी हो लेकिन स्टेट के हित में सभी सम्मानित सदस्यों की यह जिम्मेदारी है कि यदि सरकारी जमीन पर किसी व्यक्ति विशेष ने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है या कंस्ट्रक्शन की हुई है तो मैं सदन से यह पूछना चाहूँगा कि क्या वह कब्जा हटाया जाए या नहीं या वह कंस्ट्रक्शन तोड़ी जानी चाहिए या नहीं तोड़ी जानी चाहिए?

चौ० भजन लाल : अगर नाजायज कंस्ट्रक्शन है तो तोड़ी जानी चाहिए। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने नाजायज कंस्ट्रक्शन की हुई है क्या उसके बारे में पूरा सदन इस बात पर सहमत है कि वह तोड़ी जानी चाहिये? (विघ्न) मेरा क्वैश्चन बड़ा पोजिटिव है। इस लिए उसका जवाब निगेटिव में नहीं आना चाहिये। सरकारी भूमि पर चाहे वह किसी भी विभाग की है अगर किसी व्यक्ति विशेष ने उस पर नाजायज कंस्ट्रक्शन की हुई है तो क्या वह तोड़ी जानी चाहिए या नहीं तोड़ी जानी चाहिए?

आवाजें : तोड़ी जानी चाहिएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ठीक है, यह नोट कर लें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है। एक सवाल मुख्य मंत्री जी ने किया है वह पोजिटिव ही है। कई जगह ऐसी सरकारी जमीन भी है जहां लोगों ने बड़ी तादाद में मकान बनाये हुए हैं और जहां पर सरकार ने उनको बिजली के कनैक्शंज, सीवरेज भी दी हुई है और डिवैल्पमैन्ट चार्जिज भी लिए हुए हैं एवं प्लाटस की जायज नाजायज रजिस्ट्री भी की हुई है तो जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ ऐक्शन होना चाहिए और यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि आम आदमी को नुक्सान न हो।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, किस ने कनैक्शन किस हिसाब से लिए हुए हैं यह वह बात नहीं यह अलग बात है। बात बड़ी स्पष्ट सीधी सी है कि अगर सरकारी भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष ने सरकार की अनुमति के बिना जो नाजायज कंस्ट्रक्शन की हुई है वह नाजायज कंस्ट्रक्शन चाहे हमारी सरकार में है, चाहे भजन लाल की सरकार में है, चाहे बंसी लाल की सरकार में है या चाहे किसी भी सरकार में हुई है, वह सारी की सारी तोड़ी जानी चाहिए, सारा सदन इस बात पर सहमत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) आपकी पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। आप तो बहुत सीनियर आदमी हैं मुख्यमंत्री जी ने केवल सरकारी भूमि की बात कही है किसी की पर्सनल लैंड पर बात नहीं कही, आप बैठिए, (शोर एवं व्यवधान) प्लीज टेक यूअर सीट।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए कोई नीति होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गुर्जर साहब, आपका कोई सुझाव है तो आप सरकार को दे देना। आपको बोलने का समय मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को यह रूप नहीं देना चाहता था। मैं यह मानता

[राव धर्मपाल]

हूँ कि जो भी सरकार आई है हर वक्त ऐसा होता रहा है मेरा यह बात कहने का विशेष मकसद यह था कि गांव के लोगों को कंट्रोल्ड एरिया का पता नहीं होता कि उसकी नोटिफिकेशन कब हो गई और उस नोटिफिकेशन का क्या महत्व है। सभी को पता है कि परिवार सबके बढ़ते हैं किसी का एक घर है उसके चार बेटे हैं उसको बाद में चार घर चाहिएं तो वह साथ लगती जमीन पर मकान बना लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके गुड़गांव में गांव झाड़सा है मेरा गांव इस्माइलपुर है जो भी सराउंडिंग गांव हैं हर गांव में यह स्थिति है कंट्रोल्ड एरिया से बाहर जो गांव हैं उनकी कोई बात नहीं है लेकिन जो कंट्रोल्ड एरिया के अंदर गांव हैं उनमें भी उन्हें बढ़ावा देना है उसके गांव वालों के लिए कोई छूट दी जाए। इस बारे में सरकार की कोई स्कीम नहीं है, सैक्टर नहीं है फिर भी उनको गांव में जा करके नोटिस देना, एक आदमी के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। इस पर सरकार विचार करे, यह मेरा निवेदन है साथ ही मैं यह भी आग्रह करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इल्लीगल तरीके से होने से पहले ही उसको रोक दिया जाये जिससे किसी आदमी को महसूस नहीं होगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : सरकार आपकी बात से सहमत है।

राव धर्मपाल : धन्यवाद जी।

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला मेरे इलाके से रिलेटिड है। 1877 की बन्दोबस्त में जो एक्विजीशन हुई थी उसमें ज्यादातर चौधरी भजन लाल जी के समय में एक्विजीशन हुई थी। 1877 की बन्दोबस्त के तहत जो एक्विजीशन हुई है उसमें गांववासियों के बहुत से मकान, घेर, गतवाड़ तथा सामूहिक स्थल आ गये हैं। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जैसा कि चौधरी देवी लाल जी ने भी सर्वे कराया था उसी प्रकार एक सर्वे टीम बनाकर जहां पर गांव की फिरनी बढ़ गई है उन लोगों को न उजाड़ें तथा उन्हें भूमि अधिग्रहण से मुक्त किया जाये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सदन में इस बात का प्रस्ताव लायें क्योंकि यह एक अहम मुद्दा है। मेरा सुझाव यह है कि पिछली सरकारों के समय में जिस जमीन पर कब्जे हुए हैं जिनमें गांव के गांव हैं उन लोगों से पैसे ले लें। अगर उनमें गरीब लोग हैं, हरिजन हैं तो उनसे कम पैसे ले लें और जो ज्यादा पैसे दे सकते हैं उनसे ज्यादा ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, बैठिये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए और सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों की जानकारी के लिए स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जहां कहीं इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुई हैं और जिन्होंने जमीन बेचकर इस प्रकार के मकानात बना दिए हैं कि अगर कहीं किसी जगह पर आग लग जाये तो वहां फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच सकता। इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन को निश्चित रूप से तोड़ा जाना चाहिये। जिस गांव में कन्सोलीडेशन के इस्तेमाल के बाद रास्ते और फिरनी कटे हुए हैं जिसकी वजह से आम रास्ते में कोई रुकावट नहीं है तो सरकार की मंशा उनको तोड़ने की नहीं है। अगर गांव की खुली जगह में जाकर आपने मकान बना लिए हैं और जिनकी वजह से किसी को कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं है। सरकार का यह फैसला है कि पंचायत और डी.सी. आपस में तय करके उससे पैसे लेकर उन पैसों को पंचायत के खाते में बैंक में जमा करायें और आगे के लिए उस व्यक्ति को कोई परेशान न करे इसके लिए उस जमीन की रजिस्ट्री उस व्यक्ति के नाम करवाई जाये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इससे हम ऐफैक्टिड हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, सबसे ज्यादा मैं ऐफैक्टिड था मैंने कह दिया कि चौधरी भजन लाल जी के समय में सबसे ज्यादा भूमि का अधिग्रहण हुआ है उस समय कहीं शमशान घाट, जोहड़, खेल के मैदान, हरिजन बस्तियां, स्कूल नहीं छोड़े गये, मन्दिर नहीं छोड़े। आप बैठें।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जिस गांव में कब्जे के मुताबिक किसी को कोई ऐतराज नहीं है उसका कोई ऐतराज नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें भी एक बात में और पेचीदगी है। कुछ ऐसे गांव हैं जो कंट्रोल्ड ऐरिया में हैं और जहां सैक्टर भी ईयरमार्क हुए हैं लेकिन न तो उनको अण्डर सैक्शन 4 और 6 के तहत नोटिश इशू किया गया है और न ही हुड्डा विभाग की तरफ से कोई पोलिसी या प्लानिंग बनाई गई है। ऐसी जगहों पर ऐसे गांवों को जो किसी प्रकार से शहरों के साथ लगते हैं उनको कैसे छूट देनी चाहिये क्योंकि जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि चकबन्दी 1877 की है। हमारे यहां 1952 में चकबन्दी हुई थी और 1952 के बाद आज 50 साल हो गये हैं, परिवार बंटते बंटते बहुत ज्यादा हो गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली पानी की बात है, बिजली और पानी की हर आदमी को जरूरत होती है। पीने के पानी का सवाल है, पीछे अभी प्रदर्शन हो रहे थे कि गुड़गांव में डेली वेजिज के कर्मचारियों को जो 7-8 या 10-10 साल से काम कर रहे थे, उनको हटाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सैशन में हरियाणा सरकार ने खुद को वचनबद्ध किया था कि हर व्यक्ति को 40 से 70 लीटर तक पीने का पानी उपलब्ध करवाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ और वह सुझाव जनहित में भी होगा, यह जो खासकर गांवों में ट्यूबवैल्ज चल रहे हैं, ये बगैर ओपरेटर्ज के चल रहे हैं। कोई भी आदमी जाता है और स्विच दबा देता है, अगर लाइट 2 फेज में हो तो 5 मिनट में सरकार की 40 हजार की मोटर का सड़ कर धुंआ निकल जाता है। एक-एक ऑपरेटर को 2 या 3 साथ लगते गांवों में लगाया जाए ताकि गांव वाले लोग इन ट्यूबवैल्ज को जाकर न चलाएं और न बंद करें क्योंकि इससे सरकार का नुकसान होता है और उपभोक्ताओं को पीने के पानी से प्यासा रहना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि सरकार को जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार इनको रखे और इनको निकाला न जाए बल्कि इनसे काम लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपाल जी, आप वाइंड अप करें।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, गुड़गांव और उसके आस-पास का इलाका ऐसा है जहां उद्योग भी हैं, गांव के लोगों के पास जमीन वगैरह भी हैं, पैसे की ट्रांजैक्शन काफी रहती है। जहां तक कानून और व्यवस्था की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गुड़गांव में 2 महीने के अन्दर जो लूटमार की घटनाएं हुईं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। 7 जनवरी को सैक्टर-5 के पास डोमीनेंट कर्मचारियों से सवा 6 लाख रुपये लूटे गए।

श्री उपाध्यक्ष : वे सभी अरैस्ट हो गए हैं और पैसा बरामद हो गया है। आपको बधाई देनी चाहिए कि सभी अरैस्ट हो गए हैं और रुपये बरामद हो गए हैं। कल मेरी इसी बारे में भजन लाल जी से बात हुई थी।

राव धर्मपाल : यह बड़ी अच्छी बात है, मैं इसके लिए तारीफ करता हूँ। लेकिन एक बात आप देखिए कि पैसा बरामद होना पब्लिक को पता नहीं लगता, पब्लिक में हाहाकार और दहशत फैल जाती है जब गोलीबारी या छुरेबाजी की कोई घटना हो जाती है, माहौल भयानक रूप धारण

[राव धर्मपाल]

कर लेता है। हरेक आदमी पैसा ले जाते हुए डरता है। 20 जनवरी को नैशनल हाइवे नं० 8 जो दिल्ली से जयपुर रोड़ है वहां सहाय पैट्रोल पम्प से पैसा लूटा गया, 21 जनवरी को स्टेट बैंक से 18 हजार रुपये ले जाती हुई महिला से पैसा लूटा गया। फरवरी में एक व्यापारी की टाटा सुमो 407 को रोड़ पर रोककर गुड़गांव के बाई पास पर एक लाख रुपये छीन लिए गए। फरवरी को हुंडैइ मोटर्स के सामने एक लूटमार की वारदात हुई। 24 फरवरी को नैशनल हाइवे नं० 8 पर हंसालय पैट्रोल पम्प जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय जी करने गए थे वहां से पौने 2 लाख रुपये लूटे गए। 2 महीनों में 6-7 घटनाएं आस पास हो जाना इस बात का सबूत है कि वहां का माहौल बड़ा भयावह हो गया है। हरेक आदमी सोचता है कि बैंक से पैसा लेकर चले तो मैं घर पहुंच पाऊंगा या नहीं। इस पर अभी डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि पैसा बरामद हो गया। लेकिन बात पैसा बरामद होने से नहीं बनती, लूटमार बंद होनी चाहिए और यह सरकार का दायित्व बनता है।

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपाल जी, आपके सोहना की केवल 2-3 घटनाएं थी, उसकी तो मैं नहीं कहता हूँ बाकि गुड़गांव में 90 प्रतिशत इंसीडैंट्स मेरे पास हैं, हम पड़ोसी हैं, आप देख लेना, मैं बधाई दूंगा कि अधिकतर केसिज में दोषी अरैस्ट हो गए हैं। जो हंसालय की पूर्णिमा सेठी का केस है उसमें 50 हजार की लूट हुई है। बैंक वाले केस में 18 हजार की लूट है।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, अखबार में एक लाख 75 हजार छपा था। मैं इन सब बातों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर यह जरूर कहूँगा कि इसमें जो लिखा है वह वास्तविकता नहीं है, वह अपनी मर्जी से लिखा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के सदस्य कैप्टन अजय सिंह को भी तो बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, प्लीज आप बैठें। सबको बोलने का अवसर मिलेगा। यह आपकी प्रॉयोरिटी पर नहीं है कि पहले कौन बोलेगा, यह चेयर की प्रॉयोरिटी है। कैप्टन साहब को भी बोलने का अवसर मिलेगा। हुड्डा साहब, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह मलिक (कैलाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सबसे पहले कृषि के बारे में कहना चाहूँगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा है कि प्रदेश की खुशहाली केवल मात्र ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों की खुशहाली पर निर्भर है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि ग्रामीणों की खुशहाली से ही पूरा प्रदेश खुशहाल रह सकता है लेकिन सोनीपत जिले में खासकर जी.टी. रोड़ के साथ जिन किसानों की जमीन लगती है वह एक्वॉयर की जा रही है। बरही के क्षेत्र में पहले पंचायत की जमीन ऐक्वॉयर की गई है और अब किसानों की जमीन एक्वॉयर की जा रही है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिन किसानों की निजी जमीन एक्वॉयर की जाये उनको उसका उचित मूल्य दिया जाये। दिल्ली के साथ लगते एरियाज में 23 लाख रुपये के करीब प्रति एकड़ के हिसाब से रेट दिया जाता है और हमारे यहां किसानों को 2.30 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार मुआवजा दे रही है। इस कारण से वहां ऐसे हालात पैदा हो गये हैं कि वहां के गांव उठने के कगार पर हैं। क्योंकि 2.30 या 3 लाख रुपये में वहां आस पास के क्षेत्र में दूसरी जमीन किसानों को मिल नहीं

सकती। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंचाई की बात है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा है कि वर्ष 2001-02 के दौरान 21 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई की गई है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कैलाना क्षेत्र के माईनरों में पानी बिल्कुल भी नहीं आया और यदि आप चाहें तो मैं गांवों के नाम भी बता सकता हूँ। राजपुरा माईनर, सव्वा माईनर और पुरखास जो मेरे हल्के का सबसे बड़ा गांव है, इन माईनरों में पानी चलवाने का काम करें ताकि वहां के किसानों को दिक्कत न हो। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली विभाग की बात है, इस बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा है कि चालू वर्ष में 43 प्रतिशत अधिक बिजली दी गई है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यह बात बिल्कुल गलत है। आज के दिन गांवों में जिस समय बिजली की जरूरत सबसे ज्यादा होती है उस समय बिजली बिल्कुल भी नहीं आती। गांवों में बिजली न तो सुबह आती है और रात के समय जब विद्यार्थियों के पढ़ने का समय होता है उस समय भी बिजली नहीं आती। बिजली की तारों का तो बहुत बुरा हाल है। हमारे वहां सभी तारें लूज हैं। कुछ हादसे तो इस कारण हो चुके हैं और यदि उन तारों को ठीक नहीं किया गया तो भविष्य में और हादसे भी हो सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। जहां तक सड़कों की बात है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सड़कों को धमनियां कहा गया है। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे हल्के की सड़कों का बहुत बुरा हाल है और कैलाना क्षेत्र एक ऐसा आदमी है जिसकी धमनियां खराब हो गई हैं और कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि समय रहते मेरे हल्के की धमनियों को ठीक किया जाये। मेरे हल्के की सड़कों को ठीक करवाने के लिए मैंने दो-तीन बार मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और जो सड़कें ठीक होनी थीं उनके नाम भी पत्र में लिखे थे लेकिन दुर्भाग्य से उनका कोई जवाब नहीं आया। पिछली बार विधान सभा सैशन में मुख्यमंत्री जी का लिखित में जवाब आया था कि बरसात का मौसम जाने के बाद वे सड़कें ठीक कर दी जायेंगी लेकिन अब 2003 आ गया लेकिन मेरे हल्के की वे सड़कें जिनका मैंने पत्र में जिक्र किया था, ठीक नहीं हुईं। ये सड़कें गन्नौर से पुगथला और सोनीपत से दुबेटा बाया पुरखास जिनकी बहुत बुरी हालत है। इन सड़कों को ठीक करवाने के लिए सोनीपत और गन्नौर हल्के के गांववासियों ने रास्ता भी रोका, आंदोलन भी किया जिसके कारण लाठियां भी चलीं और कई लोगों पर केस भी बने। इसलिए मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा बल्कि काम करके दिखाना होगा।

अब मैं ग्रामीण विकास की बात करना चाहूँगा। ग्रामीण विकास के बारे में इस अभिभाषण में भी लिखा हुआ है। यह ठीक है कि सरकार ग्रामीण विकास के लिए फण्ड अलॉट कर रही है। ऐसा हम अखबारों में भी पढ़ते हैं और कागजों से भी इस बारे में जानकारी हासिल होती है लेकिन सच्चाई यह है कि गांवों के अन्दर विकास के नाम पर कहीं पैसा नहीं लगता। यह पैसा किस स्तर पर खाया जाता है, इसकी जांच की जाये। गांवों में कोई नाला खोदा जाता है तो उसको बीच में अधूरा छोड़ दिया जाता है। मैंने इस बारे में शिकायत भी की थी। अब मैं बात गोयल साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ। गोयल साहब, गन्नौर के अन्दर फायर ब्रिगेड के लिए एक भवन बनाया जा रहा है। इस भवन में बहुत ही घटिया स्तर का मैटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बारे में मैंने एक पत्र गोयल साहब को लिखा था कि गन्नौर में जो फायर स्टेशन बनाया जा रहा है उसकी देखरेख किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा नहीं की जा रही। वहां पर बहुत ही घटिया स्तर का मैटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। जब मैं वहां पर मौके पर गया तो मुझे भी वहां पर कोई सरकारी अधिकारी नजर नहीं आया। फायर ब्रिगेड लोगों को बचाने के लिए होती है। इसके लिए जैसा भवन बनाया जा रहा

[श्री जितेन्द्र सिंह मलिक]

है उससे वे लोगों को क्या बचाएंगे बल्कि वे खुद ही उस भवन में दब जाएंगे। अत: मैं चाहूँगा कि इस ओर भी ध्यान दिया जाये ताकि वह फायर स्टेशन अच्छा बन सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कानून-व्यवस्था की बात करना चाहता हूँ। किसी भी राज्य की पहली जिम्मेदारी उसकी अपने लोगों के लिए कानून-व्यवस्था की होती है। इस अभिभाषण में सरकार ने लिखा है कि कानून-व्यवस्था पर 51 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। कानून-व्यवस्था पर राव धर्मपाल जी भी बोल रहे थे कि आज फिरौती और अपहरण के मामले पहले से अधिक हुए हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि सोनीपत जिले में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस बारे मे मेरा कहना है कि चोर पकड़ने की बजाय चोर की मां को पकड़ने की कोशिश की जाये, खाली कागजों में खानापूर्ति करने की कोशिश न करें तो अच्छा रहेगा। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसमें कोई भाई यह न सोचे कि मैं विपक्ष के नाते कह रहा हूँ। मैं सारी पार्टियों को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहां पर जहरीला पौधा 93-94 के अन्दर पैदा हुआ। वह आदमी जो पहले स्कूटर ठीक किया करता था, बाद में गलत तरीके से स्मगलिंग करके उसने गलत पैसा कमाया। वहां पर चोरियों का एक बड़ा स्कैण्डल हुआ था, जिसमें एच०सी०एस०, एच०पी०एस० स्तर के कई अधिकारी फंसे थे। वह आदमी इन लोगों के साथ मिलकर समाज को भौण्डा बनाने की कोशिश कर रहा है और कोशिश किन के माध्यम से कर रहा है वह भी सभी को पता है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, यानि चाहे पिछली थी या उससे पिछली थी और चाहे हाल की सरकार है, वह इस तरह के अधिकारियों और नेताओं का संरक्षण करती रही है। उस आदमी का काम पिछली सरकार में भी दारू सप्लाई करने का रहा करता था, उससे पिछली सरकार में भी वह अधिकारियों पर अपना दबाव गलत तरीके से बनवाता था। मैं यह कहने में भी गुरेज नहीं करूंगा कि वेश्यावृत्ति करने वालों को छुड़वाने में भी वह अहम रोल अदा करता है। जो साथी सत्ता पक्ष में बैठे हैं वे उतना काम नहीं करवा सकते जितना यह आदमी करवा कर दिखा देता है। मैं बताना चाहूँगा कि वहां पर रात के समय में वे मुजरा करवाते हैं और उससे आगे क्या होता है वह आप समझ सकते हैं। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि वहां पर नेता भी जाते हैं, डी०आई०जी० स्तर का अधिकारी भी जाता है, आई०पी०एस० और आई०ए०एस० स्तर के अधिकारी भी जाते हैं। मैं आपको एक ताजा उदाहरण इस बारे में बताना चाहूँगा, आप इसको सी०एम० साहब को नोट करवा देना। वहां पर 5-6 महीने पहले जी०टी० रोड पर एक पुलिस अधिकारी ने आवारा किस्म की दो-तीन लड़कियों को पकड़ा और उन के साथ एक आदमी भी था। उस समय उनके पास पैसे बहुत कम थे। जैसा कि पुलिस का आमतौर पर रवैया है कि थोड़ा बहुत ज्यादा मांगा होगा, बाद में उनको छोड़ दिया और उसे कहा कि आगे से तुम नजर नहीं आओगे। इस तरीके से बात हुई और यह बात होने के बाद उस आदमी ने एक आई०ए०एस० अफसर को फोन किया और कहा कि आपके राज में हमारे साथ पुलिस वालों ने ऐसा किया। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप गवर्नर एड्रैस पर बोलें।

श्री जितेन्द्र सिंह मलिक : स्पीकर साहब, मैं गवर्नर एड्रैस पर ही बोल रहा हूँ। मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि किसी एक चोर को पकड़ें और एक को छोड़ें या कातिल को छोड़ें यह ठीक नहीं है। जो भी दोषी हो उसे पकड़ा जाये।

श्री अध्यक्ष : कानून अपना काम करेगा।

श्री जितेन्द्र सिंह मलिक : कानून तो अपना काम जब करेगा जब कोई करवाएगा। जब कोई कानून से काम नहीं करवाएगा तो कानून क्या करेगा। जो मैं कह रहा हूँ वह सच्चाई बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप वाईन्ड अप करें।

श्री जितेन्द्र सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वह सदन का मैम्बर नहीं है, नहीं तो मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इस आई०ए०एस० ऑफिसर ने उस समय हस्तक्षेप किया, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब सोनीपत की बात है या हरियाणा में किसी विशेष मुद्दे की बात है उसमें कुछ कहने में शर्म नहीं है। इसमें चाहे जूडिशिरी हो कोई भी दूसरी चीज इन्वाल्व हो तो कहने में कोई शर्म नहीं है। मैं नाम लेकर भी कह सकता हूँ। यहां तक कि इसमें जज तक शामिल हैं। उस आई०ए०एस० ऑफिसर ने उसकी तीन महीने तक जमानत नहीं होने दी उसके बाद जैसे तैसे करके राजीनामा करके वह केस खारिज हो चुका है। आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि हालात क्या हैं। आप कहने को चाहे कुछ भी बोलते रहें लेकिन आपका नीचे का जो सिस्टम है वह ठीक नहीं है (विघ्न) वह केस डिसमिस हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस तरह की बात पर सही जानकारी हासिल करने के लिए अपना कोई एजैंट लगाए या कोई नेटवर्क बनाए। आपके नीचे जो काम करने वाली एजैंसियां हैं खाली उन्हीं के भेजे हुए जवाबों पर या उनकी रिपोर्ट पर यकीन न करके कुछ ऐसा नेटवर्क बनाएं जो आपको सही जानकारी दे सके। चाहे आप सत्ता पक्ष के एम०एल०एज० को लें या किसी अपने निजी अधिकारी को लगाएं, आपको इस चीज की जांच करवानी चाहिए। (विघ्न) कादियान साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग जुर्म करते हैं 1-2 बिरादरी को छोड़कर बाकी सारे करते हैं। इसमें मेरी बात का आप कुछ बुरा नहीं मानना। इनको छुड़ाने वाले वही लोग हैं, इससे समाज पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। स्पीकर सर, कहना तो नहीं चाहिए कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ लेकिन यहां पर एक रिवाज सा है जबकि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है क्योंकि मेरा जो हक है वह आपने दिया है। (विघ्न) मैं इस अभिभाषण को खाली कागज मानता हूँ इससे फालतू कुछ नहीं मानता।

श्री जगजीत सिंह सांगवान (दादरी) : स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय ने 5 मार्च को बड़े भारी मन से जो अभिभाषण दिया है उस पर बोलने के लिए समय दिया है । बहुत सी ऐसी बातें जिनका गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र नहीं किया है। अगर गवर्नर साहब उन बातों का जिक्र करते या सरकार उन बातों को अभिभाषण में शामिल करती तो इसे एक बहुत अच्छा अभिभाषण कहा जा सकता था लेकिन उन बातों की कमी की वजह से इसके अन्दर वे बातें नहीं हैं जो मैं इसमें शामिल करवाना चाहता था। गवर्नर महोदय के अभिभाषण में वे बातें और होनी चाहिए थीं इन बातों से इस अभिभाषण को और अच्छा बनाया जा सकता था सबसे पहले कृषि के ऊपर गवर्नर महोदय ने कहा। ऐसा है कि यह जो सरकार है यह ग्रामीण लोगों की सरकार है। जहां ग्रामीण लोगों की सरकार होती है, वहां पर गांवों के लोगों को ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन हरियाणा के अन्दर 2-4 प्रतिशत गांवों को छोड़ कर कहीं पर कोई सुविधा नहीं है। विधान सभा की सारे जिलों की एक कमेटी बना कर भेजें, जो इन बात की जांच करे। आप किसी भी गांव की गली में से नहीं गुजर सकते हैं। इतनी बुरी हालत आपके गांवों की है। जहां तक गांव के पानी की निकासी का सवाल है, मुझे नहीं पता आपको यह बात अच्छी लगती है या कि नहीं लेकिन किसी भी गांव में आप जाएं कहीं पर भी पानी की निकासी का प्रबन्ध नहीं है। आप मान लें 2 प्रतिशत ऐसे गांव हैं जहां

[श्री जगजीत सिंह सांगवान]

पानी की निकासी का प्रबन्ध है लेकिन अन्य गांवों में पानी की निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं है। यहां तक कि गांवों में बनी चौपालों की हालत जर्जर है। गांवों में पुराने चौक हुआ करते थे उससे होकर गांव के अन्दर कोई भी जा सकता था लेकिन आज गांव में बाहर से अगर कोई सरकारी अधिकारी या नेता जाता है तो गांव के अन्दर उसके बैठने के लिए कोई जगह तक नहीं है। यह तो गांवों की सरकार का गांवों के प्रति रवैया है। सरकार प्रत्येक गांव का सर्वे करवा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-4 प्रतिशत गांवों पर ही सारा पैसा खर्च कर दिया जाए। कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां पर एम०पी० भी सारा फण्ड खर्च करता है। एम० एल० ए० को तो आप लोगों ने सरपंच से भी नीचे का दर्जा दे रखा है। सरपंच भी गांव में 5 ट्राली मिट्टी की गिरवा सकता है। अगर किसी के यहां ब्याह शादी हो या किसी की मृत्यु हो जाए तो वहां पर तो जाना ही पड़ता है लेकिन इतनी बुरी हालत गलियों की है कि कीचड़ में से होकर जाना पड़ता है। हालांकि लोग शिकायत भी करते हैं लेकिन वे जानते हैं कि एम०एल०ए० बेचारा उनको कुछ दे नहीं सकता है। आज हमारे सत्ता पक्ष के साथी मजबूर हैं लेकिन मन ही मन वे मुझे धन्यवाद दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, ये बोल नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, अधिकारी और मंत्री हर गांव की अन्दर की सड़क और गलियों में जा नहीं सकते तो वहां की असली स्थिति का पता तो लोकल एम०एल०ए०को ही होता है, इसलिए उनकी रिपेयर के लिए एम०एल०एज० को कुछ राशि ऐसी जरूर दी जानी चाहिए ताकि वह इस प्रकार के छोटे-छोटे काम करवा सकें। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए तथा ऐसे अमाउन्ट का प्रावधान करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार हाउस में मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि पीले और हरे कार्ड जो बने हैं उनके बारे में दोबारा से सर्वे करवाया जाएगा। मेरा कहना है कि सम्पन्न लोगों ने जो गरीब लोगों का हक मार रखा है और असल में जो असली हकदार हैं वे इस हक से महरूम है। अगर यह सर्वे दोबारा से अच्छे ढंग से करवाया जाए तो असली हकदार को उसका हक मिल जाएगा। इस तरह की बातें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आनी चाहिए थीं।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में इरीगेशन का भी जिक्र आया है। मैं आप के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि इरीगेशन का जो पैसा है वह सारे का सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, जो पुरानी कैनाल्ज हैं। जैसे लोहारू कैनाल है वहाँ पर जो पम्पिंग सैट है वह बहुत पुराना है वह खराब पड़ा है उस पम्प की पानी उठाने की कैपेसटी पूरी नहीं है और वह आधा पानी ही उठा सकता है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह जो नहरों की सफाई करने की बात की जाती है, यह सिर्फ कागजों में ही की जाती है। अगर मौके पर जाकर देखें तो पता चलेगा कि असल में वहां पर कुछ नहीं किया जाता है। यहां पर सी०पी०एस० महोदय भी बैठे हुए हैं, मेरा इनसे आपके माध्यम से निवेदन है कि ये मौके पर जाकर नहरों और पम्प हाऊसिज का निरीक्षण करें तो पता चलेगा कि असल में क्या हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक पावर की बात है इसका बहुत ही बुरा हाल है। पावर के बारे में 2-3 मोटी किताबें छाप दी हैं लेकिन आज गांवों में बिजली का नामों निशान नहीं है। अगर बिजली आती है तो इतनी कम वोल्टेज आती है कि उससे ज्यादा मोमबत्ती की रोशनी होती है। गांवों में बिजली की तारें और खम्बे टूटे पड़े हुए हैं। लोगों ने घरों की छत्तों पर लकड़ी लगाकर के बिजली की तारों पर से अपने घरों में कुण्डी कनैक्शन लगा रखे हैं। अगर किसी गांव में 3 ट्रांसफार्मर्ज हैं तो वे आए दिन

जलते रहते हैं। ट्रांसफार्मर्ज के बारे में सरकार की पॉलीसी है कि नए ट्रासफार्मर्ज नहीं लगाए जाएंगे। पुराने ट्रासफार्मर्ज ही बदले जाएंगे। आज क्या हो रहा है कि एक गांव का ट्रासफार्मर दूसरे गांव में, दूसरे गांव का ट्रासफार्मर तीसरे गांव में बदल दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में कोई अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में धर्मपाल जी कह कर गए थे कि जितना पानी, बिजली इस बार मिला है और जितनी अच्छी फसल अब की बार हुई है उतनी अच्छी फसल पहले कभी नहीं हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगजीत सिंह सांगवान : जहां तक बी०एंड०आर० की बात है, यह ठीक है कि कुछ सड़कें नयी बन रही हैं और चौड़ी भी बन रही हैं। यह बिल्कुल सही बात है। (विघ्न) मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि दादरी से बहादुरगढ़ तक जो सड़क बनी है वह बीच में सात आठ गांवों जैसे खेड़ी एवं खातीवास के आस पास टूट गयी है। (विघ्न) राठी साहब, मैं आपको बता दूं कि वह सड़क कितनी जगह से टूट गयी है या वह सड़क पूरी नहीं हुई है। इन सात आठ गांवों के आस पास किसी भी जगह पर इस सड़क पर तारकोल नहीं डाली गयी है बल्कि मोबिलऑयल ठेकेदार ने डाल दिया है जिससे वह सड़क काली तो दिखनी शुरू हो जाती है लेकिन एक हफ्ते के अन्दर ही वह टूटनी शुरू हो जाती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, आप बैठें। अब सी०पी०एस० साहब कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, अभी सांगवान साहब ने कहा है कि बनने के बाद एक हफ्ते में ही सड़क टूट जाती है, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई सड़क बनी हो और वह टूट गयी हो तो यह हमे बता दें हम उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं बता देता हूँ। लोहारू से बहादुरगढ़ तक जो सड़क बनी है उस पर डावौंडा गांव के आस-पास झज्जर और बहादुरगढ़ के बीच में पांच किलोमीटर चलने के बाद 15 किलोमीटर तक जो इस सड़क का टुकड़ा है, यह पूरा नहीं बना है, आप चाहे तो इसी वक्त उसकी जांच करवा लें। वहां पर वह सड़क बहुत खराब है। (विघ्न) जिस सड़क के बनाने के ठेकेदार ने पैसे लिए हैं और उस पर लोग चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, गढ्ढों में चल रहे हैं, अपनी गाड़ी को नुक्सान पहुंचा रहे हैं और आम पब्लिक परेशानी में है तो उसकी तो जांच होनी ही चाहिए। हालांकि इसमें मैं सरकार का दोष नहीं मानता। कुछ अधिकारियों ने इसकी निगरानी नहीं की है इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, आप अब बैठें। आपके 6 मिनट बनते थे लेकिन आपको दस मिनट से भी ज्यादा बोलते हुए हो गये हैं।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, दस मिनट तो मेरे इन्होंने ही ले लिए हैं। मैं तो सरकार की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं अच्छी बातें कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपने अच्छे सुझाव दे दिए हैं इसलिए अब आप बैठें।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : जो चीज सुधर सकती है मैं उसके बारे में ही कह रहा हूँ। फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आपके सुजैशंज वैल्यूएबल हैं। अब आप बैठें। अब वीना छिब्बड़ जी बोलेंगी।

श्रीमती वीना छिब्बड़ (अम्बाला शहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूँगी और उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी रहनुमाई में हरियाणा का चहुमुखी विकास हुआ है। हरियणा राज्य छोटा होने के बावजूद प्रगतिशील और कल्याणकारी योजनाओं के लिए विख्यात है। हरियाणा ने हमेंशा देश को एक नयी दिशा दी है। इसलिए हरियाणा के मुख्य मंत्री माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने विकास की चहुं ओर झड़ी लगा दी है। मैं समझती हूँ कि वे पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपना ज्यादा समय अपने दफ्तर में न बैठकर, आराम न करके हरियाणा की सड़कों पर, हरियाणा के जन-जन तक पहुंचने के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान एवं उनके दु:ख दर्द दूर करने के लिए लगाते हैं। उनको आप मोबाईल मुख्य मंत्री कह सकते हैं वे हर समय और हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। माननीय चौधरी देवी लाल जी के सपनों को साकार करते हुए उन्होंने एक कार्यक्रम 'सरकार आपके द्वार' चलाया, देवी लाल जी अपने समय में खुले दरबार लगाया करते थे उसी तरह से यह कार्यक्रम चलाया गया कि उसी स्थान पर लोगों की समस्याएं सुनना और तुरन्त उनका मौके पर निपटान करना यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास है, अनूठा अनुभव है। पिछली सरकारों के समय में लोगों को मुख्य मंत्री के दर्शन करने के लिए कितने-कितने समय तक लाइनों में खड़ा होना पड़ता था लेकिन अब के मुख्य मंत्री जी स्वयं जाकर के लोगों से मिलते हैं उनका दु:ख दर्द सुनते हैं। मुख्य मंत्री जी ने कुछ नयी-नयी योजनाएं बनाई हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक बहुत ही सुंदर स्कीम बनाई गई है, इनकी इस योजना से मुझे वह समय याद आ गया कि पहले 60-60 साल के आदमियों की नसबंदी हो जाया करती थी। कईयों की नयी-नयी शादी होती थी और उनकी जबरदस्ती नसबंदी कर दी जाती थी लेकिन इन्होंने मानसिकता तैयार करने के लिए एक अनूठी योजना 'देवी रूपक' के नाम से लोगों को लाभ देने के लिए बनाई है। (विघ्न) पानी के लिए पूरे हरियाणा के लिए योजनाएं बनाई हैं। इस सरकार ने साढ़े तीन वर्षों के अंदर जितने भी पानी देने के प्रयास किए हैं, उसके लिए पिछली सरकारों को सोचना चाहिए कि वे कितने अधूरे काम छोड़ कर गये थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र अम्बाला शहर के लिए मुख्य मंत्री जी ने करोड़ों रुपये की पानी पहुंचाने की योजनाएं लागू की हैं, उससे इन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरे अम्बाला शहर निर्वाचन क्षेत्र में पहले लोग अपनी बेटियों का रिश्ता नहीं करते थे कि हमारी बेटी को रात-रात को उठकर पानी भरना पड़ेगा। सुबह होते ही पानी के लिए लाईनें लग जाया करती थीं। बच्चे उठते थे, उनको उठकर स्कूल जाना होता था, उनके लिए नहाने के लिए पानी नहीं हुआ करता था लेकिन आज मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से बहुत अधिक पानी वहां हो गया है। पानी की टूटियां खुली रहती हैं, पानी जाया न जाये इसके लिए भी कोई न कोई प्रबन्ध होना चाहिए। मेरे हल्के में 27 गांव हैं उनमें से लहारसा आदि गांवो के लोग पानी के लिए तरसते थे, पिछली सरकारों ने पिछले 50 वर्षों में वहां पानी मुहैया नहीं कराया था, आज उन 27 के 27 गांवों में मुख्य मंत्री जी ने ट्यूबवैल्ज लगवा दिये हैं और लगभग 5 किलोमीटर की पाइप लाइन मेरे हल्के के अंदर बिछाई गई इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट करती हूँ।

अध्यक्ष महोदय, अम्बाला शिक्षा के लिए जाना जाता है, वहां अनेक शिक्षण संस्थायें हैं। टैक्नीकल ऐजूकेशन, बी०एड०व आई०टी०आई० भी हैं। महिलाओं को आगे लाने के लिए उनको नि:शुल्क शिक्षा देने का जो मुख्य मंत्री जी ने काम किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं साथ ही यह भी

अनुरोध करना चाहती हूँ कि अम्बाला शहर में महिला कॉलेज भी बनाया जाए। अम्बाला जिले में तो महिला कॉलेज है लेकिन अंबाला शहर में कोई महिला कॉलेज नहीं है मेरा विनम्र अनुरोध है और उम्मीद है कि मुख्य मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। विपक्षी साथी बिजली के बारे में बहुत शोर मचा रहे थे। बिजली की बढ़ोतरी के लिए इस सरकार ने बहुत काम किया है आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। हमें इस बार गांव में और शहर में पूरी बिजली मिली है और किसी भी बच्चे की पढ़ाई में व्यवधान नहीं पड़ा। किसी कृषि वाले को बिजली की कमी नहीं हुई। जिसका जितना हिस्सा था उसको पूरी बिजली मिली है। इसी का परिणाम है कि इस बार कृषि अच्छी हुई है, अच्छी गेहूँ और अच्छी जीरी हुई है। बाकी कुदरती आपदा आ जाये उसके आगे तो किसी का बस नहीं चल सकता। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने नये सब-स्टेशंज बनाये हैं। आने वाले समय में हमारे प्रदेश में बिजली में इतना सुधार हो जायेगा कि हम दूसरे राज्यों को भी बिजली दे सकेंगे। ऐसी स्थिति हमारे हरियाणा प्रदेश में होने जा रही है। जहां तक सड़कों की बात है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सरकार के समय के अन्दर पूरे हरियाणा के अन्दर सड़कों का जाल बिछाया है और लगभग 4200 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। पुरानी सड़कों की मरम्मत भी हो रही है। मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में और भी सुधार होगा। मैं अपने हल्के की बहुत सी सड़कों के बारे में बताना चाहूँगी। अम्बाला शहर में किसी समय मलकानी कमीशन आया था और उस कमीशन ने अम्बाला शहर को एशिया का सबसे गन्दा शहर घोषित किया था। उस धब्बे को तो हटाने का काम इस सरकार ने किया है लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि उस धब्बे के कुछ निशान अभी भी बाकी है, उनको भी पूरी तरह से मिटा दें तो उनका बड़ा धन्यवाद होगा। जैसे मेरे हल्के के जी०टी० रोड से लेकर बाया घास मण्डी की सड़क है। सर्कुलर रोड से सीधे ही ट्रक अन्दर आ जायेगें। वहां पर बहुत सारे शैलर्ज हैं और लोगों को ट्रकों के आने जाने से कोई तकलीफ नहीं होगी। पोलिटैक्नीक कॉलेज से लेकर हिसार रोड, जगाधरी गेट, सब्जी मण्डी और चौकी नम्बर 4 से हरि पैलेस वाली सड़क की हालत खराब है। इन सड़कों को बनाने के लिए पहले मार्केटिंग बोर्ड और शिवालिक बोर्ड को कुछ ग्रान्ट मिलती थी वह अब बन्द हो गई है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि उस ग्रांट को फिर से शुरू किया जाये और मार्केटिंग बोर्ड को सड़क बनाने का अधिकार दिया जाये। गांव घेल में एक रेलवे फाटक लगता है वहां से अम्बाला मेन लाइन पर घंटों फाटक बन्द रहता है। वहां से किसानों को अपना चारा और अनाज, मण्डी में ले जाने के लिए तकलीफ होती है। इसी प्रकार से लाहड़सा गांव की सड़क कच्ची है उसको बनाया जाये। मण्डौल से नारायणगढ़ रोड पर चण्डीगढ़ मार्ग की सड़क बनाई जाए क्योंकि वहां पर अनाज का गोदाम बन गया है। वहां पर ट्रक ले जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। इसी प्रकार अगर कलरहेड़ी से डोह सड़क बनाई जाती है तो अम्बाला का बहुत शार्ट रास्ता हो जाता है। महिलाओं के मान-सम्मान के लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी हमेशा कोई न कोई योजना लेकर आये हैं। क्योंकि महिलाएं थाने में जाने से कतराती हैं लेकिन अब महिलाएं बेझिझक थाने में जाकर अपनी समस्या को बता सकती हैं क्योंकि महिलाओं के लिए स्पेशल थाना खोलकर उनके लिए बखूबी कार्य किया गया है। किसी को भी साथ लेकर वे थाने में अब सीधी जा सकती हैं। इसी प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी ने महिलाओं के लिए अलग से अस्पताल बनाने की घोषणा की है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। इसी प्रकार कल्पना चावला एवार्ड देने की बात हरियाणा प्रदेश में रखी है उससे हमारे हरियाणा में सुधार होगा। इस अवार्ड ने बच्चियों के अंदर एक उत्साह का संचार किया है कि वे ऐसा काम करें जिससे वे पढ़ाई में अव्वल आएं ताकि उनको यह आवार्ड मिल सके। महिला डेयरी परियोजना शुरू करके सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम किया है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करती हूं। मेरे

[श्रीमती वीना छिब्बर]

हल्के में गांव पंजोखड़ा में 60 लाख रुपये की लागत से पी०एच०सी० बनकर पूरी होने जा रही है उसके लिए मुख्य मंत्री महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही साथ मैं उनके सामने अपनी एक मांग रखूंगी कि अंबाला शहर में कोई आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी नहीं है जैसा कि अभिभाषण में बताया गया कि जड़ी बूटियों की खेती होगी। उनको आगे लाया जायेगा। अंबाला शहर में आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी या कोई अस्पताल जो सरकार दे सके, दे दे तो मैं उसके लिए सरकार का आभार प्रकट करूंगी।

श्री अध्यक्ष : आप वाईड अप करें।

श्रीमती वीना छिब्बर : अम्बाला शहर में जब ओवर ब्रिज बनवाया गया था तो उस समय किसी के दिमाग में यह बात नहीं थी कि रेलवे लाईन के पार इतनी आबादी हो जायेगी। अम्बाला के एक तरफ पंजाब लगता है जो हिसार रोड पर जो पुल बना हुआ है उसके साथ मंडी बनने के कारण वह छोटा पड़ गया है और चारा मंडी होने के कारण वहां ट्रालियाँ लगी रहती हैं। वहां बहुत दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। विधायक लोग व मंत्री लोग वहां से गुजरते हैं इसलिए यह बात उनके ध्यान में जरूर होगी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि हिसार रोड पर जो पुल है उसको चौड़ा कर दिया जाए तो अम्बाला निवासियों और दूसरे आने जाने वाले लोगों को फायदा होगा। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने कृषि क्षेत्र में भी विकास के काम किए हैं। अभी पिछले दिनों पी०ए०सी० के साथ मैं कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में गई थी। उनकी योजनाओं को देखकर हमें बहुत खुशी हुई कि कृषि के लिए कितने काम किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने हमें बताया कि किसानों को यहां आने की जरूरत नहीं वे घर बैठे ही अपनी समस्या का समाधान फोन पर करवा सकते हैं और वहां फोन की व्यवस्था भी है इसे टैली ऐग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। जिससे किसान घर में बैठकर बता सकता है कि उसने ये बीज बोया और उसे यह प्रौब्लम है। उसे वहीं फोन पर उसका समाधान बता दिया जाता है। और जगहों पर भी यह व्यवस्था करने बारे विचार किया जा रहा है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगी। मनोरंजन के क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत काम करवाया है। हिसार में दूरदर्शन केन्द्र बनकर तैयार होने जा रहा है उसकी आधारशिला रखी गई है। इस केन्द्र द्वारा हरियाणा प्रदेश अपनी संस्कृति, अपने रीतिरिवाजों को पूरे भारत वर्ष में बिना किसी का मोहताज हुए दिखा सकेगा। इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगी। मैं एक बार पुनः मुख्य मंत्री महोदय और सरकार का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने प्रदेश में इतने बढ़िया काम करवाए और आगे भी आने वाले समय में ऐसे काम करवाते रहेंगे। मेरे हल्के में जो गन्ने की परेशानी है उसके समाधान के लिए मैं चाहूँगी कि सबको एक समान मूल्य मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार का धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेती हूँ और इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। स्पीकर सर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एस०वाई०एल० के बारे में सबसे पहले लिखा भी गया है और उस बारे सदन में भी काफी चर्चा हो चुकी है। मैं भी सबसे पहले एस०वाई०एल० के बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि एस०वाई०एल०के बारे में सदन को जिस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचे। हमने काम रोको प्रस्ताव भी इसीलिए दिया था कि इस पर पूरी तरह से बहस हो और पूरा सदन एक निष्कर्ष पर पहुंचे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एस०वाई०एल० का मैटर अब सबज्यूडिस मैटर है, यह सबज्यूडिस मैटर नहीं है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्लीयर कट फैसला है कि एक साल

में पंजाब सरकार पंजाब एरिया में एस०वाई०एल०का निर्माण करवायेगी और पंजाब सरकार निर्माण नहीं करवाती है तो केन्द्र सरकार एस०वाई०एल०नहर की खुदाई का काम करवायेगी। अध्यक्ष महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट का क्लीयर कट फैसला है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। पता नहीं मुख्य मंत्री जी ने कैसे कह दिया कि मामला सब्ज्यूडिस है इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री जी ने यह भी कह दिया कि यह मामला खास महत्व का नहीं है इसलिए हमने जो काम रोको प्रस्ताव एस०वाई०एल० के बारे में दिया था वह नहीं आ सकता। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा। डॉक्टर साहब गलत बात कह रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने तो यह कहा था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए सभी मैंबरों ने एस०वाई०एल० के बारे में चर्चा की है, इस बारे में हर मैंबर जितना बोलना चाहता था वह बोला है। इतनी बहस तो इस मोशन के मार्फत भी नहीं हो सकती थी और इस बारे में मुख्यमंत्री जी जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब देंगे तब जवाब आ जायेगा। इसलिए मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इस 'काम रोको प्रस्ताव' का कोई महत्व नहीं है, यह 'काम रोको प्रस्ताव' नहीं बनता। स्पीकर सर, 'काम रोको प्रस्ताव' वह होता है जहां कोई एमरजैंसी आ गई हो या immediate concern का मामला हो। मुख्यमंत्री जी ने तो यह कहा था कि इस पर कल से बहस हो रही है और यह नहर हरियाणा की जनता की लाईफ लाईन है। डॉक्टर साहब को इस तरह गलत बात नहीं कहनी चाहिए।

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * * *

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठिये। चेयर की इजाजत के बगैर जो भी बोल रहे हैं उनकी बात रिकार्ड न की जाये। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप सभी बैठें, आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, आप भी मानते है कि एस०वाई०एल० के न बनने के कारण हरियाणा की जनता के हजारों करोड़ रुपये का नुक्सान हो रहा है और मुख्य मंत्री जी का भी ब्यान आया था कि अब तक हरियाणा की जनता का एस०वाई०एल०नहर न बनने से 10 हजार करोड़ रुपये का नुक्सान हो गया है। जब इतनी अहम् बातें हैं और हरियाणा के लोग अपना जीवन निर्वाह करने के लिए बहुत मुश्किल में हैं, एस०वाई०एल०का पानी न आने के कारण। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने 'काम रोको प्रस्ताव' दिया था और हमारी मंशा यह थी कि एस०वाई०एल०के बारे में सभी की एक पॉलिसी बने। स्पीकर सर, आज सारा हाउस मुख्य मंत्री जी के साथ है, मुख्य मंत्री जी को आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह घोषणा करनी चाहिए कि केन्द्र सरकार एक महीने में एस० वाई० एल० की खुदाई का काम शुरू करवायें वरना हरियाणा की 36 बिरादरी के लोग सड़कों पर आ जायेंगे। तभी एक महीने के अंदर-अंदर नहर का काम शुरू हो सकता है। इसमें बिलकुल डिजायर की बात है, यह बहुत अहम मुद्दा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती वीना छिब्बर : अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्ष के भाई यहां तो बात करते नहीं हैं और सड़कों पर जाकर भाषण देते हैं। जब हाउस टैक्स पर बहस हो रही थी, उस समय भी इन्होंने ऐसा ही किया था।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : इसमें मेरा सुझाव है कि यह नहर बननी चाहिए और इसमें एक स्पैसिफिक घोषणा भी होनी चाहिए और साथ ही साथ एक स्पैसिफिक एक्शन प्लान इसके लिए तैयार होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो यह मामला इसी तरह से उलझता रहेगा। कई मुख्य मंत्री इस कुर्सी पर आए और कई चले गये। यह एक बड़ा अहम् मुद्दा है। इसमें मेरा सुझाव है कि जो मुख्य मंत्री जी जो घोषणा करें उस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें सभी को समर्थन देना चाहिए ताकि नहर खुदवाने का काम जल्दी से जल्दी हो सके और केन्द्र सरकार पर दबाव हो, इसमें कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में ब्यास नदी का जो पानी बह रहा है, वह 3.8 एम०ए०एफ० पानी इराडी ट्रिब्यूनल ने दिया था। ब्यास का हिस्सा 3.8 एम०ए०एफ० है उसमें से 18 लाख एकड़ फीट के करीब पानी बह रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी इस बात को अपने जवाब में बताए कि कितना पानी आ रहा है और किसके हिस्से का पानी कहां चल रहा है। यदि किसी एक इलाके का पानी किसी दूसरे इलाके को दिया जा रहा है तो यह घोर अन्याय है। कृपया मुख्य मंत्री जी इस बारे में जवाब देते समय इस बात को क्लीयर करें।

स्पीकर साहब, जहां तक सर्विसिज की बात है या फण्ड एलोकेशन की बात है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस बारे में यदि रिकार्ड के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाये तो सारी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। उसमें यह सारी बात आ जायेगी कि फण्डज के लिए और सर्विसिज के लिए किस को क्या-क्या दिया गया है मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो फण्ड डिस्ट्रिक्ट-वाईज या कान्स्टीच्यूऐंशी वाईज या जो भी ये उचित समझें कोई भी यूनिट मानकर चलें, उस हिसाब से सारी स्थिति स्पष्ट की जाये। इस फण्ड में 19-20 का तो फर्क हो सकता है क्योंकि कोई एरिया बैकवर्ड हो सकता है और वहां पर ज्यादा जरूरत हो सकती है इसलिए वहां पर ज्यादा पैसा दिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, यदि फण्डज के एलोकेशन में पोलिटिकली कन्सीडेशन होगी तो यह प्रदेश के हित में नहीं है। यदि किसी एक का हक किसी दूसरे को दिया जा रहा है तो उस बारे में भी मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि सदन को बताया जाये।

अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब दो साल पहले बजट आया था तो उसमें मैंने डाईवर्सिफिकेशन के बारे में कहा था। डॉ० गोलेबल बहुत बड़े साईंटिस्ट थे। वे एक बार यहां पर आए थे उन्होंने इस लाईन पर बात की थी डब्ल्यू०टी०ओ० की मार किसानों पर पड़ेगी। उनका कहना था कि यदि क्रोप्स की डाईवर्सिफिकेशन नहीं हुई तो इससे किसान लुट जायेगा और बिखर जायेगा यदि किसानों की क्रोप्स की डाईवर्सिफिकेशन न हुई तो किसान गरीबी और गुरबत के कगार पर खड़ा हो जायेगा। मैंने दो साल पहले भी बजट पर बोलते हुए यह कहा था कि इसके लिए बजट की एक स्पैसिफिक एलोकेशन होनी चाहिए और इसके लिए कोई एक ऐक्शन प्लान तैयार हो और उस पर एक सिस्टेमैटिक ढंग से एक्शन हो तो किसान को बचाया जा सकता है क्योंकि आज के दिन क्रोप्स रोटेशन बदलना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। चाहे कल्टीवेशन की बात हो, चाहे रैमूनिरेशन की बात हो, चाहे कैश क्राप की बात हो, चाहे लाईव स्टाक की बात हो और चाहे फिशरीज की बात हो, चाहे कोई भी बात किसी भी तरह की हो इसमें क्रोप डाईवर्सिफिकेशन की स्पेशल एलोकेशन आफ दी बजट होनी चाहिए। खुद मुख्य मंत्री जी ने परसों कहा था कि डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए तो इस बारे में मेरा कहना है कि इस पर पूरी तरह से अमल होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में को-आप्रेशन की भी बात आई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जहां सूखाग्रस्त इलाका है, उस सूखाग्रस्त इलाके में लोन्ज की जो इन्स्टालमेंट है, उसके सस्पैंशन की बात कही गई थी या उसमें इन्ट्रस्ट छोड़ने की बात कही गई थी, आज हमारे इलाके में बुरी तरह

से सूखा पड़ा हुआ है। हमारे यहां खरीफ की फसल भी और कुछ रबी की फसल की भी सोइंग नहीं हो सकी क्योंकि वहां पर इरीगेशन या यों कहें कि ट्यूबवैल्ज से या कैनाल से एश्योरड इरीगेशन नहीं है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि उस इलाके में जो लोन्ज पर ब्याज है उसको माफ किया जाना चाहिए और जो इन्स्टालमैंट हैं उनको डैफर किया जाना चाहिए।

स्पीकर साहब, यहां पर इरीगेशन की भी बात आई है। स्पीकर साहब, मेरे हल्के में कई कैनाल ऐसी हैं जहां टेल पर पानी नहीं पहुंचता। वे सारी नहरें अटी पड़ी हैं और उनमें बड़ी जबर्दस्त तरीके से बीड की ग्रोथ होयी हुई है और इसी प्रकार से उनके अन्दर छोटी-मोटी झाडियां हैं, वे भी जमी हुई हैं। मैं चाहूँगा कि इन कैनाल्ज की सफाई करवाई जाये ताकि उनमें पानी टेल तक पहुंच सके।

स्पीकर साहब, मैं पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के बारे में जो अचीवमैंट हैं उस बारे में बताना चाहता हूँ कि 50 लीटर से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी देने का टारगेट है। इस स्कीम के लिए वर्ल्ड बैंक से या दूसरे स्थानों से लोन्ज भी आ रहे हैं। मेरे हल्के में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर प्राईवेट वाटर के कन्ट्रैक्टर्ज हैं, वे वहां पर पानी की सप्लाई कर रहे हैं। उन द्वारा दिए जाने वाले पानी का कोई एनालिसिस नहीं है और न ही कोई मैडिकल टैस्ट हैं। Whether it is suitable for the human consumption or not. इसमें मेरा सुझाव यह है कि 55-56 साल की आजादी के बाद भी अगर पानी की खरीद करनी पड़ेगी तो यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। मेरी कान्स्टीच्यूएंशी में एक गांव सिवाना है उसमें दूर से पानी आ रहा है यानि दूसरे जिले से आ रहा है। पिलाना या बौन्द से आ रहा हैं। दूसरे जिले के लोग ट्रैक्टर पर पानी लेकर आते हैं और 2-2 रुपये में पानी का एक मटका वहां पर मिलता है। वहां पर पशुओं के लिए भी पीने का पानी नहीं है। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां पर पीने के पानी का प्रबंध किया जाये।

स्पीकर सर, जहां तक बेरी हल्के की रोडज की बात है, मैंने फस्ट सैशन में भी यह बात उठाई थी कि 1995 के बाद अब तक जितनी भी फण्डज की ऐलोकेशन हैं उनमें बड़ा भेद-भाव हो रहा है। बेरी से सेरिया, दुबलधन से माजरा की सड़क टूटी हुई है। स्पीकर साहब, बेरी से दादरी जो रोड है उस पर आप खुद भी गए थे और आपने देखा होगा कि वहां पर दुबलधन में 4-4 फुट के गढ्ढे सड़क में पड़े हुए हैं। इस बात की जांच करने के लिए आप पांच आदमियों की एक स्पैशल कमेटी बना दें उस कमेटी का सारा खर्चा मैं वहन करूंगा। उस सड़क पर इतने बड़े-बड़े गढ्ढे हैं कि उसमें से मुख्यमंत्री जी, किसी मंत्री या एम०एल०ए० की गाड़ी नहीं निकल सकती है अगर कोई गाड़ी वहां से गुजर जाए तो I am ready to resign from the politics as well as विधान सभा। स्पीकर सर, वहां पर इतने जबरदस्त और बड़े-बड़े गढ्ढे हैं। (विघ्न एवं शोर)

श्री बलवन्त सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, अभी दो मिनट पहले माननीय कादियान साहब जी एक बात कह रहे थे कि राजनीति से परे हट कर हमें हरियाणा प्रदेश के विकास कार्यों के लिए या किए गए अच्छे कामों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ देना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने विकास कार्यों के लिए 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम चलाया हुआ है इसके तहत उन्होंने जो कार्य किए हैं वे इस ढंग से किए हैं कि जिस भी हल्के में वे जाएं उस हल्के का नुमाईदा वह चाहे कोई भी हो वह गांव के लिए कुछ भी मांगें या कोई भी विकास कार्य की मांग करें या उनको गांव की कोई समस्या बताएं तो उस समस्या का समाधान जरूर होगा। मैं अपने माननीय साथी डॉक्टर कादियान जी से यह जानना चाहूँगा कि इन्होंने विधान सभा में जो बात उठाई है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी इनके क्षेत्र में गए थे

[श्री बलवन्त सिंह मावना]

तो क्या इन्होंने यह मांग की थी कि दुबलधन के रास्ते में जो सड़क है वहां पर कोई परेशानी है या अपने हल्के से सम्बन्धित कोई और मांग उन्होंने रखी थी या क्या ये वहां पर गए थे। अगर ये वहां पर गए थे और इन्होंने कोई मांग रखी थी और वह काम नहीं हुआ हो तभी विधान सभा में कहने के लिए इनका हक बनता है।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप कॉन्टीन्यू करें और अब आप वाईंड अप भी करें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मैंने जो रोड्ज़ बताई हैं बेरी से सेरिया, दुबलधन से भाजरा दुबलधन के रास्ते खराब थे और 30-35 हजार रुपये इकट्ठे करके गांव के लोगो ने पी० डब्ल्यू० डी० की रोड पर अपने पैसे खर्च करके मिट्टी डलवाई है। ढीबल से कलावड़ सड़क, बेरी से दुजाना मेहराना, बेरी से रिटौली कबूलपुर कसान सड़क बेरी से काहनोर की जो सड़के हैं उनकों बनवाएं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप इन सड़कों के बारे में लिख कर दें । अब आप बैठें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, मेरे हल्के में एम०पी० माजरा गांव है इसमें कंसोलीडेशन नहीं हुआ है इससे बहुत बड़ी तंगी पूरा गांव भुगत रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि एम०पी०माजरा गांव जो समस्या को फेस कर रहा है उसमें जल्दी से जल्दी कन्सोलीडेशन हो ताकि लोगों को खेतों में रास्ते तथा दूसरी सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

इसमें स्पीकर सर, मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि खजाने भरे हुए हैं लेकिन जिस तरह से कैट की रिपोर्ट है उसके हिसाब से वित्तीय घाटा, राजस्व घाटा दोनों बढ़ रहे हैं। जो नॉन प्लान एक्सपैंडिचर हैं उसमें 87 फीसदी टोटल बजट का चला गया है। फिसकल डैफिसिट कंट्रोल से बाहर चला गया है TGDP नीचे चला गया है। हुडको और मार्किटिंग बोर्ड से रैगुलर लोन दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप अब बैठ जाएं। आपका समय हो गया। अब आप बैठ जाएं।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, मेरा सुझाव है जिस दिशा में प्रदेश जा रहा है यह बड़ी चिन्ता का विषय है। अगर हम विधान सभा में ये बातें नहीं कहेंगे तो ये बातें कौन सी जगह पर होंगी। मेरा कहना है कि डि-सैन्ट्रैलाईजेशन आफ पावर हो। सी०एम०साहब के पास 45 डिपार्मैंटस हैं। यहां पर दूसरे साथी भी बैठें हुए हैं ये यह कहना चाहते हैं कि एक टीम वर्क होना चाहिए इसलिए इन साथियों में उन डिपार्टमैंटस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरे स्पीकर सर, जो टैक्स कम्पलायंस है .....

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, बहुत हो गया आप अब अपनी सीट पर बैठ जाएं। कैप्टन अजय सिंह जी आप बोलें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा समय दीजिए मैं अभी वाईंड-अप कर देता हूँ, (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मुझे वाईंड अप करने दो। स्पीकर सर, मुझे यह तो कहने दोगे कि मैं राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। कैप्टन साहब आप बोलें। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाएं।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : सर, मुझे एक मिनट का समय दिया जाए। *******

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) आप जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : * * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन अजय सिंह जी, आप बोलें। (शोर एवं व्यवधान)। कादियान साहब, आप बैठ जाएं। कैप्टन जी आप बोले। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, 5 मार्च, 2003 को राज्यपाल महोदय, ने सदन में जो अभिभाषण पढ़ा है मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। (शोर एवं व्यधान) अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में चर्चा की है। उसके बारे में मैं सदन में कहना चाहूँगा, वैसे तो इस बारे में सदस्यों ने काफी चर्चा की है लेकिन मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहूँगा। स्पीकर सर, हमारा जो इस बारे में 'काम रोको प्रस्ताव' था उसमें मुख्य मुद्दा यह था कि खास तौर पर दक्षिणी हरियाणा में रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिले हैं, वहां पर पिछले दिनों सूखा पड़ा था तो हमें उम्मीद थी कि सरकार किसानों को कुछ राहत देगी। हमारे जिले में राहत के नाम पर 27 हजार रुपए मिले हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर 50 गांव तो ऐसे हैं जहां पर एक बीज तक पैदा नहीं हुआ है और हमें अखबारों से पता चलता है कि हमारे एरिया के हिस्से में राहत के लिए 27 हजार रुपए पूरे जिले के लिए आए हैं। यह पढ़कर हमें बहुत हैरानी हुई और जिनकी फसल खराब हुई है आप ही बताएं कि उन पर क्या बीता होगा। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० के पानी का मुद्दा हमारे लिए जीवन-मरण का मुद्दा है। स्पीकर सर, जब से सुप्रीमकोर्ट का आदेश आया है उसके बाद से एस०वाई० एल० के लिए बहुत बड़ी-बड़ी अनेकों रैलियां हमारे यहां पर हुईं और इस बात की भी चर्चा थी कि हरियाणा के मुख्य मंत्री एन०डी०ए० की सरकार को स्पोर्ट कर रहे हैं और हमारे मुख्य मंत्री सैन्टर की सरकार पर अपने प्रभाव से जो आदेश हुए हैं, उनसे 15-3-2003 के बाद इस बारे में कार्यवाही करवाएंगे लेकिन इस बारे में कोई कार्यवाही सैन्टर की तरफ से नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी सरकार ने एस०वाई०एल जो हमारे इलाके में बनी हुई है उसकी रिपेयर के लिए अपने पैसों का कोई प्रावधान नहीं रखा है? दूसरा जो इराडी ट्रिब्यूनल के अंदर एक वैकेन्सी खाली पड़ी हुई है क्या उसको भरने के बारे में सरकार ने प्रधनामंत्री जी से मुलाकात की है क्योंकि जब तक इराडी ट्रिब्यूनल की वैकेंसी नही भरी जाएगी तब तक आपकी यह रिपोर्ट इम्पलीमैंट नहीं हो सकती क्योंकि जो जजमैन्ट है उसका आधार इराडी ट्रिब्यूनल ही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार ही यही है। अध्यक्ष महोदय, राजीव लौंगोवाल समझौते के बारे में भी कल यहां पर कुछ लोगों द्वारा चर्चा की गयी कि इस पर हरियाणा के मुख्य मंत्री के दस्तख्त नहीं थे। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि जब उस समझौते पर प्रधानमंत्री के दस्तख्त हो गये जोकि सबसे ज्यादा उच्च पद पर हैं तो फिर हरियाणा के मुख्य मंत्री के दस्तक की जरूरत की कोई ऐसी बात नहीं है। राजीव लौंगोवाल समझौते के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है इसलिए इसमें तो ऐसी कोई बात न थी।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांट ऑफ आर्डर है। ये कह रहे हैं कि उस समझौते पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के दस्तख्त की जरुरत नहीं थी। मैं इनसे कहना

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री रामपाल माजरा]

चाहता हूँ कि अगर उस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के दस्तख्त की जरूरत नहीं थी तो ये हमें बता दें कि फिर उस समझौते पर लौंगोवाल के दस्तख्त की क्या जरूरत थी? उसके दस्तख्त उस समझौते पर किस अहमियत से हुए थे, किस हैसियत से हुए थे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये हमें इतना बता दें कि क्या राजीव लौंगोवाल समझौते के खिलाफ हैं? इस समझौते के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो आधार था वह राजीव लौंगोवाल समझौता ही था। अगर सरकार के वश की बात नहीं है तो ये एन०डी०ए० सरकार से अपना समर्थन विदड्रा कर लें। (विघ्न)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, ये बार बार राजीव लौंगोवाल समझौते की बात कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि राजीव लौंगोवाल समझौते से यह बात क्लीयर हो गयी है कि प्राईम मिनिस्टर ने पार्टी विशेष के अध्यक्ष के साथ वह समझौता किया था। पंजाब सरकार का तो मान भी लें कि उनका उस में रिप्रैजेंटेटिव था लकिन हरियाणा सरकार का कोई रिप्रैजेंटेटिव उसमें नहीं था। अध्यक्ष महोदय, जब दो स्टेट का डिस्प्यूट होता है तो दोनों को ही बुलाया जाता है और दोनों की सहमति से ही कोई फैसला किया जाता है। ये बार बार राजीव लौंगोवाल समझौते की बात कह रहे हैं मैं इनको बताना चाहूँगा कि हमने उस वक्त उसका विरोध किया था विरोध ही नहीं किया था बल्कि हमने असैम्बली से अपने इस्तीफे भी दिए थे। अध्यक्ष महोदय, इस समझौते से पहले जो पानी के बारे में फैसला हुआ था उसमें स्पष्ट लिखा था कि जो 7.2 एम०ए०एफ० पानी था उसमें से 3.5 एम०ए०एफ० पानी हरियाणा को मिलेगा और 3.5 एम०ए०एफ० पानी पंजाब को मिलेगा। इसके साथ ही यह भी लिखा था कि अगर पानी बढ़ेगा तो पंजाब को 3.5 एम०ए०एफ० पानी से ज्यादा फालतू पानी किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। जो पानी बढ़ेगा केवल हरियाणा को ही मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यह राजीव लौंगोवाल समझौते से पहले वाले समझौते में लिखा था। राजीव लौंगोवाल समझौते से तो हरियाणा प्रदेश के हितों पर कुठाराघात हुआ है, क्योंकि उसमें हम बंधकर रह गए हैं। अब इस समझौते के अनुसार पंजाब को 4.8 एम०ए०एफ० पानी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इराडी ट्रिब्यूनल ने जो अन्तरिम रिपोर्ट दी है उससे हरियाणा का शेयर 3.83 एम०ए०एफ० हो गया है। यानी इससे नुकसान हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि 7.2 एम०ए०एफ० के बाद जितना पानी बढ़ा था वह टोटल हरियाणा को मिलना चाहिए था लेकिन यह शेयर हरियाणा के बजाए पंजाब को चला गया है और राजीव लौंगोवाल समझौते की वजह से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस नहर की कंस्ट्रक्शन पंजाब सरकार एक साल के अंदर अंदर पूरी करे। लेकिन इन्होंने एक साल के अंदर तो अपनी जुबान नहीं खोली, एक शब्द पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में नहीं कहा, एक शब्द भी पंजाब सरकार के बारे में बोला हो तो बता दें। ये बिल्कुल गूंगे बनकर रह गये क्योंकि इसमें इनका निहित स्वार्थ था। पंजाब में इनकी पार्टी की सरकार थी इसलिए इन्होंने कुछ नहीं कहा और जैसे ही वह एक साल पूरा होने को आया उससे एक दिन पहले ही यानि लास्ट दिन ये कहने लगे कि अगर केन्द्र सरकार ने इसकी समय सीमा तय नहीं की तो हम सड़क जाम कर देंगे, आन्दोलन कर देंगे, धरना देंगे। इन्होंने पूरे एक साल तो कोई सड़क जाम नहीं की, कोई आन्दोलन नहीं किया और न ही पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में कोई शब्द बोला और न ही पंजाब के मुख्य मंत्री से ये इस बारे में मिले। इससे पता लग जाता है कि इन लोगों की इस बारे में कितनी सीरियसनैस है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सारा बेड़ा गर्क कर दिया था। राजीव लौंगोवाल समझौते से हरियाणा प्रदेश का बेड़ा गर्क हुआ था। कल भी हमारा यही स्टैंड था आज भी वही स्टैंड है। हमेशा इस बारे में

हमारा स्टैंड क्लीयर है कि राजीव लौंगोवाल समझौते से हरियाणा प्रदेश का अहित हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर हमारा अहित नहीं होता तो हरियाणा को ज्यादा पानी मिलना चाहिए था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में अपनी बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, आप बैठे। आप किस लिहाज से खड़े हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूरी पार्टी के बारे में कहा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, आप बैठें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश राजीव लौंगोवाल समझौते के आधार पर ही हुआ है। यह ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस संपत सिंह जी ने जो बात कही है उससे वे अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं और साथ ही प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं। राजीव लौंगोवाल समझौते के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। दूसरा जो मुद्दा है जिसके बारे में मैं खास तौर पर कहना चाहूँगा वह पानी के बंटवारे के बारे में है। हमारे दक्षिणी हरियाणा का पानी का हिस्सा एक एम०ए०एफ० है उसके बारे में ऐस्टीमेट्स कमेटी की 25वीं रिपोर्ट में बाकयादा दिया है कि एक एम०ए०एफ० पानी का हिस्सा हमारे दक्षिणी हरियाणा के लिये था और वह पानी सिरसा के खेतों में जा रहा है। आपने हमारे इलाके के हिस्से का पानी ले लिया इस बारे में आपको मानवता के नाते तो सोचना ही चाहिए। जो हमारा अधिकार है उसके बारे में यह सरकार चुप है एक तरफ यह सरकार सेम की समस्या को खत्म करने के लिए 170.64 करोड़ रुपये खर्च कर रही है लेकिन हमारे यहां पानी की इतनी अधिक समस्या हो रही है उसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। हमारे यहां पानी इतना नीचे चला गया है कि 170 फुट गहराई तक पानी का एक कतरा भी नहीं मिला इस वजह से हमारे यहां का किसान सूखे की मार झेल रहा है। अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि पानी का बंटवारा सही तरीके से करना चाहिए अब मैं शिक्षा के बारे में अपनी बात कहना चाहूँगा। मैंनें अभिभाषण में पढ़ा है कि चौधरी देवी लाल के नाम से सिरसा में यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है लेकिन क्या कभी सरकार ने सोचा है कि हरियाणा प्रदेश के चार जिले ऐसे हैं जहां पर पूरे प्रदेश की एक चौथाई पापुलेशन पढ़ती है और इस इलाके में एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी मैडिकल कॉलेज, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। वहां सिर्फ प्राइवेट कॉलेज हैं जो दुकान की तरह खोल रखा है। क्या कभी वहां सरकार ने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडीकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोलने के बारे में विचार किया है। हमने नीरपुर में पोस्ट ग्रेजुएट रिजनल सैंटर का काम 100 एकड़ भूमि पर चालू करवाया था और वहां 60-70 लाख रुपये लगाए थे। वहां चारदीवारी बना दी गई थी, सड़क बन गई थी, ऐडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनना शुरू हो गया था लेकिन इस सरकार ने आते ही वहां काम बंद कर दिया। अगर आप सिरसा में यूनिवर्सिटी चौधरी देवी लाल के नाम से खोल सकते हैं तो हमारे यहां भी चौधरी देवी लाल के नाम से खोल दें, हमें कोई एतराज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां जो रीजनल सैंटर का काम रोक रखा है उसे चालू कराया जाए। हमारे यहां के नौजवान बच्चों को दूर-दूर पढ़ने जाना पड़ता है। मेरा आग्रह है कि उस रीजनल सैंटर को बनाने का काम जरूर करें। अब मैं रेशनलाईजेशन ऑफ टीचर्ज के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि वह 1/60 की बजाय 1/30 का होना चाहिए लेकिन जिस प्रकार से बदलियां की गई हैं उनका मैं विरोध करता हूँ। इसके साथ ही मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने कैसीनो बिल राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया है। वह बिल बहुत ही गलत बिल था। गवर्नर महोदय को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ। कैसीनो खोलकर

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

यह सरकार अपना घाटा पूरा करना चाहती थी। कैसीनो खुलने से शराब और शबाब का राज होगा। क्या यह बड़ा अच्छा कार्य होगा? दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार जगह-जगह चौधरी देवी लाल जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। (विघ्न) मैं भी चौधरी देवी लाल जी की पार्टी में रहा हूँ साल या दो साल। अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी देवी लाल जी की बहुत इज्जत करता हूँ। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार जगह-जगह चौधरी देवी लाल जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं क्या उनकी देख-रेख के लिए भी सरकार ने कुछ सोचा हैं। जैसा कि चौधरी बंसीलाल जी उनको तोड़ने की बात करते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार चौधरी देवी लाल जी की मूर्तियां एक शहर में तीन-तीन स्थापित की गई हैं उसी प्रकार से शहीदों की मूर्ति भी स्थापित की जायें ताकि उनकी याद को ताजा रखा जा सके।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, मूर्तियां गिराने की बात उचित है या अनुचित।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको अनुचित मानता हूँ। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके साथ शहीदों की मूर्तियां भी स्थापित की जानी चाहिएं। माननीय मुख्य मंत्री पिछले दिनों रेवाड़ी क्षेत्र में खेलों के आयोजन के सिलसिले में गये हुये थे उस दिन हम गांव चीताडूंगरा में एक शहीद की शहादत के लिए गये हुऐ थे हमने सोचा था कि माननीय मुख्य मंत्री वहां पर श्रद्धांजलि देने आयेंगे लेकिन वे नहीं आये। जबकि मैंने सुना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कहीं भी शहीद की शहादत हो वहां हैलीकाप्टर द्वारा श्रद्धांजलि देने जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक 'काम रोको प्रस्ताव' भी इस बारे में दिया था रेवाड़ी शहर में जो कालोनियां बनी हुई थी उनको गिराया जा रहा है जबकि वे म्यूनिस्पिल कमेटी का टैक्स भी भर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आपने बहुत समय ले लिया अब आप बैठिए ताकि दूसरे मैम्बर्ज को भी समय मिले।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे दस मिनट और दे दीजिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे 5 मिनट और दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि रेवाड़ी में जो 38 कालोनियां हैं उनको रेगुलराईज करने बारे क्या सरकार कोई कदम उठा रही है? मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन कालोनियों को नोटिस दिया गया है जबकि वहां पर 80 प्रतिशत बड़े-बड़े मकान बने हुए हैं। आपको अगर पकड़ना है तो प्रापर्टी डीलर्स को पकड़ो जिन्होंने इन व्यक्तियों को गुमराह किया है। आम लोगों ने तो जमीन लेकर मकान बनाये हैं आज उन मकानों को तोड़ा जा रहा है। मैं चाहूँगा कि उन कालोनियों को रेगूलराईज किया जाये। अगर तोड़ने हैं तो उन मकानों को तोड़ो जो गुडगांव में 18-18 मंजिल के बने हुए हैं अगर किसी मंजिल पर आग लग जाये तो फायर ब्रिगेड भी वहां नहीं पहुंच सकता। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठें। अब सरिता नारायण बोलेंगी।

श्रीमती सरिता नारायण (कलानौर ,अनुसूचित जाति) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए समय दिया। आज हरियाणा सरकार के तीन साल पूरे हो चुके हैं। आज जिस प्रकार से हरियाणा में विकास के कार्य हो रहें हैं। उससे हरियाणा की काफी उन्नति होगी। इसमें चाहे बिजली का काम हो चाहे कृषि का क्षेत्र हो या शिक्षा का या खेलों

का आज की हमारी हरियाणा की सरकार में शिक्षा के मामले में अनुसूचित जाति और कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त वर्दी के साथ पुरस्कार और मुफ्त लेखन सामग्री और प्री-मैट्रिक तक छात्रवृति दी जाती है। कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से किसानों को सहायता मिलेगी और वे अपनी समस्याएं उनको बता सकते हैं। किसानों को अनुदान राशि देने के लिए 10 लाख रुपये की राशि निर्धारित करना, 81.30 लाख रुपये सबसिडी देकर किसानों को छोटे ट्रैक्टर मुहैया कराना, अनुसूचित जाति के किसानों तथा महिलाओं को फव्वारा सयंत्रों की स्थापना कर कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 हजार रुपये का अनुदान देना, घुमन्तू कबीले के बच्चों को स्कूल जाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में एक रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर पांच रुपये करना, ये हरियाणा सरकार ने बडे ही अच्छे काम किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहृदय से सरकार का धन्यवाद करती हूँ। हरियाणा सरकार ने सभी पुलिस मंडलों पर एक-एक महिला पुलिस थाना स्थापित किया है जिससे अब महिलाएं बिना झिझक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। पुलिस मुख्यालयों पर महिला अपराध के विषय में महिला प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं। सड़कों के बारे में भी सरकार ने बड़ी तेजी से काम किए हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आप किसी भी सड़क पर जाईये आपको हर एक सड़क चमचमाती हुई नजर आएगी। काफी नयी सड़कों का निर्माण करना व अधूरी सड़कों को पूरा करना सरकार का एक ध्येय है। हरियाणा सरकार आज हरियाणा के अंदर विकास के कार्यों को बड़ी तेजी से कर रही है। सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने का भी काम किया है। जैसे ओलम्पिक में आज जो बच्चा गोल्ड मैडल लाता है उसे एक करोड़ रुपया, सिल्वर मैडल लाने वाले को पचास लाख रुपये और कांस्य पदक लाने वाले को पच्चीस लाख रुपये देकर सरकार ने आज बच्चों का जो उत्साह बढ़ावा है उससे आज हर बच्चा मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर खेलकर अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करने की सोच रहा है। इसके साथ-साथ स्त्री पुरुष के अनुपात को ठीक रखने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए जो देवीरुपक नाम की योजना बनायी है मैं उसके लिए सहृदय से हरियाणा सरकार का धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से पेयजल के मामले में हरियाणा सरकार ने चालीस लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से बढ़ाकर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगी कि जो मेरा कलानौर हल्का है जहां से मैं चुन कर आयी हूँ उसमें जो भी पुरानी सरकारें रही हैं जिनका सबसे ज्यादा राज रहा है, उन्होंने उस हल्के को ऐसा बना रखा था कि उसका कोई वारिस ही नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद आज मेरे हल्के के अंदर बहुत ही विकास के कार्य हुए हैं। चाहे सड़कों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो या फिर पेयजल की बात हो, आज मेरा हल्का किसी भी चीज से वंचित नहीं है इसके लिए मैं अपनी चौटाला साहब की सरकार का धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे हल्के का कोई वारिस हमारे साथ आया है और मेरे हल्के को और हल्कों के बराबर चमकाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को कहना चाहूँगी कि मेरे हल्के के अंदर गांवों में काफी विकास कार्य हुए हैं लेकिन कलानौर जो प्रोपर क्षेत्र है उसमें आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। उसकी सभी गलियां टूटी पड़ी हैं और गलियों में जो नालियां है उन्होंने बड़े-बड़े नालों का रूप धारण कर लिया है जिसके कारण जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और बदबू फैली हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान कलानौर प्रोपर क्षेत्र की ओर दिलवाना चाहूँगी जहां ये इतने बढ़िया काम करवा रहे हैं, वहीं मेरे कलानौर की ओर विशेष ध्यान देकर वहां की छोटी-छोटी समस्याएं सुलझाने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में कई छोटे-छोटे लिंक सड़कों को बनाकर कलानौर को एक दूसरे से जोड़ा है इस बारे मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगी कि कलानौर की कुछ सड़कों पर मिट्टी तो डल गई हैं लेकिन थोड़ा बहुत काम बाकी है वह भी करवाया जाये। अध्यक्ष

[श्रीमती सरिता नारायण]

महोदय, मैं उन सड़कों का नाम आपके माध्यम से लिखवाना चाहूंगी। वे सड़के हैं बहुजमालपुर से सिंहपुरा तक, सांगाहेड़ा से पिलाना तक, गुढ़ान से खैरड़ी तक गड्ढीखेड़ी से गांव भाली तक, आंवल से लाहली तक, बनियानी से आंवल तक। बनियानी से लाहली तक, बनियानी से सुनारिया तक, गरनावठी से माड़ौधी तक, कलिंगा से सह तक कलिंगा से बसाना तक और खरक से चांग तक। इन सड़कों पर कुछ काम तो हो गया है मगर कुछ काम बाकी है। मुख्य मंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि इन सड़कों का बकाया काम भी जल्दी से जल्दी करवाया जाये। पिछली सरकारों के समय में इन सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और मेरे हल्के को लावारिस समझा गया। अब माननीय चौटाला साहब की सरकार ने मेरे हल्के की तरफ ध्यान दिया है इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं। अध्यक्ष महोदय, खरक व कलिंगा मेरे हल्के के बड़े गांव हैं। पिछली सरकारों के समय में इन गांवों की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और यहां के लोग अपने आपको निराश महसूस करने लगे और कहने लगे थे कि उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन गांवों का दौरा किया और 30-35 लाख रुपये देकर इन गांवों में विकास कार्य करवाये, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूँ। इन गांवों की सभी गलियों को पक्का करवाया गया चाहे किसी गली को पक्का करने में आठ लाख रुपये लगे हों, चाहे दस लाख रुपये लगे हों। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरे हल्के में कलिंगा से सह माईनर है जिसका लैवल ठीक नहीं है, इसकी सफाई पिछले कई सालों से नहीं हुई है, मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस माईनर की सफाई करवाई जाये ताकि मेरे हल्के के लोगों को पानी मिल सके। इसके अतिरिक्त भूतियान, पिलाना कटेसरा, लाहली व काहनौर माईनरों को चौड़ा करके उसका लैवल ठीक किया जाये ताकि मेरे हल्के के अंदर पानी सुचारू रूप से मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरे हल्के के कुछ गांवों में पीने के पानी की टंकियों की सफाई भी सुचारू रूप से नहीं हुई है, कुछ गांवों की टंकियों में तो छोटे-छोटे कीड़े चल रहे थे मैं थोड़े दिन पहले वहां गई थी और मैंने स्वयं देखा था।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आप उन गांवों के नाम तो बतायें जिन गांवों में पीने के पानी की टंकियों में छोटे-छोटे कीड़े चल रहे हैं।

श्रीमती सरिता नारायण : अध्यक्ष महोदय, वे गांव हैं, पटवापुर व लाहली। इसके अतिरिक्त सर्जीदा कल्याणा के कॉलेज के पास बसें नहीं रुकती। यह कॉलेज को-एजूकेशन है, लड़के तो भाग कर बस में चढ़ जाते हैं लेकिन लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो बसें वहां से गुजरती हैं, वे वहां रुकें ताकि लड़कियों को कॉलेज आने-जाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके अतिरिक्त लाहली गांव से भी लड़कियां श्री व्हीलर में बैठकर कॉलेज जाती हैं, वहां पर श्री व्हीलर वाले ज्यादा सवारियां बैठा लेते हैं जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि लाहली गांव में भी बसें रुकें। इसके अतिरिक्त कलिंगा गांव से भिवानी नजदीक ही लगता है और बच्चे भिवानी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन कलिंगा से भिवानी के लिए कोई बस सर्विस नहीं है इसलिए मुख्य मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि कलिंगा से भिवानी तक बस सर्विस लोगों को दी जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं एक सड़क का नाम और बताना चाहूंगी जो बननी बहुत जरूरी है। यह सड़क खरक की है जो टूटी हुई है। इस सड़क को बनाने के लिए पैसे भी आ गये हैं मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनवाया जाये क्योंकि खरक में दादी जापती वाल एक धर्मस्थल है जहां पर साल में दो बार मेला लगता है और आस-पास के लोग

वहां आते हैं ताकि लोग मेले का आनन्द उठा सकें। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान प्रोपर कलानौर की और भी दिलाना चाहूँगी कि कलानौर नगरपालिका पहले भंग कर दी गई थी अब दोबारा से उसे बहाल कर दिया गया है। अब उसकी तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाये और दूसरे कस्बों की तरह उसको भी अच्छा सजाया जाये। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के की कुछ ऐसी चौपालें, स्कूल्ज़ और हस्पताल हैं, जिनमें कुछ न कुछ काम होना है, किसी का फर्श खराब है तो किसी की दीवार खराब है, किसी की छत खराब है, मेरा मुख्य मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि उनका सर्वेक्षण करवाकर जल्दी से जल्दी उन्हें ठीक करवाया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने फैसला लिया है कि चौपाल चाहे हरिजन की हों, चाहे बैकवर्ड क्लासिज की हों या जनरल हों यानि जितनी भी चौपालें हैं उन सब की मुरम्मत करवाएंगे।

श्रीमती सरिता नारायण : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेती हूँ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : बैठक का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री राम किशन फौजी (बवानी खेड़ा) (अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर बोलने का लिए जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ । जब गवर्नर साहब ने अपना अभिभाषण पढ़ा तो मैं सोच रहा था कि इसमें सारी सही बातें होगीं। अध्यक्ष महोदय, जब मैं फौज में नौकरी करता था तो उस वक्त मैं सोचा करता था कि हरियाणा प्रदेश के राजनीतिज्ञ चाहे कोई कितने बड़े पद पर क्यों न हो वह इस सदन के अन्दर सत्य बोलता होगा। मुझे भी भगवान की कृपा से और चौधरी बंसी लाल जी की मेहरबानी से इस सदन में आने का अवसर मिला। मैंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुना। इस अभिभाषण के अन्दर 98 परसैन्ट असत्य बातें थी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के अन्दर सबसे पहले कल्पना चावला के बारे में हमारी सरकार ने जो गिफ्ट का प्रोग्राम किया हैं मैं उसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके साथ-साथ मैं एक सुझाव यह भी देना चाहता हूँ कि जिस परिवार के अन्दर यह बेटी पैदा हुई है उस परिवार को हमारी सरकार ऑनर करें क्योंकि ऐसा करने से उनका मनोबल बढ़ेगा। दूसरा मेरा सुझाव है कि हरियाणा सरकार द्वारा भारत सरकार के पास इसे भारत रत्न दिए जाने का प्रस्ताव पास करके भेजा जाए ताकि और दूसरी लड़कियों को उससे प्रेरणा व सम्मान मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं खासकर एस०वाई०एल० के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस पर हर साथी ने अपने-अपने विचार यहां पर दिए हैं। जब पहले इस सभा का पहला सत्र आया तो उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को माना था और यहां ब्यान दिया था कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर एस०

[श्री राम किशन फौजी]

लाई० एल० चौधरी बंसी लाल जी ने बनवाई थी और वह इसलिए बनवाई थी कि उसमें चौधरी बंसी लाल ने कमीशन खाना था। सत्य बात तो यह हैं कि चौधरी बंसी लाल जी ने न तो कमीशन खाया और न कभी कमीशन खाने की नीयत रही है। चौधरी बंसी लाल जी हिन्दुस्तान के अन्दर एक ऐसे नेता हैं जिन के ऊपर किसी प्रकार का कोई धब्बा नहीं है। उन्होंने न कभी कमीशन खाया और न कमीशन खाने की सोची। (विघ्न) यहां पर शराबबंदी की भी बात बार-बार आती है। यहां पर सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि चौधरी बंसी लाल जी ने अपने बेटे को पैसा कमाने के लिए और अपने परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए शराबबंदी की थी। अध्यक्ष महोदय, यह निराधार बात है। चौधरी बंसी लाल जी ने शराबबंदी हरियाणा के हित के लिए की थी और यह बाकायदा कैबिनेट की मंजूरी के बाद की थी और गवर्नर साहब ने बाकायदा इसकी परमिशन दी थी। अध्यक्ष महोदय, इनको यहां पर गलत बयान-बाजी नहीं करनी चाहिए। ये जो इस विषय में कह रहे हैं वह बिल्कुल निराधार कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह मौजूदा सरकार कैसीनों का बिल सदन में ले कर आई तो उस वक्त हम सभी ने उसका विरोध किया और यहां तक कि हम वाक आऊट भी करके गए थे लेकिन तब भी सरकार ने हमारी बात को नहीं माना। लेकिन इस विषय पर मैं महामहिम राज्पाल महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे हरियाणा प्रदेश को बचा लिया। अगर उस बिल को वे पास कर देते तो प्रदेश का पता नहीं क्या होता। मुख्य मंत्री चौटाला जी कहते हैं कि शराबबंदी के समय जिन बच्चों के थैलों में किताबें होनी चाहिए थीं उनके थैलों में किताबों की जगह शराब की थैलियां थीं। शराबबन्दी के दौरान झोलों के अन्दर से शराब की थैलियां थीं यह गलत है। शराब की थैलियां नहीं थीं (विघ्न) लेकिन अगर यह कैसीनों का बिल पास हो जाता तो पढ़ने वाले बच्चों के झोलों के अन्दर कट्टे और हथियार होने थे। (विघ्न) देसी कट्टे जिन्हें बोलते है वे यू०पी० के अन्दर तथा हरियाणा के हर बच्चों के पास हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : क्या आपके बच्चे के पास भी हैं? (विघ्न) फौजी साहब, आप गवर्नर एड्रैस से सम्बन्धित बात ही कहें और कोई बात न कहें (विघ्न)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है कि गवर्नर साहब ने हरियाणा प्रदेश को बचाया है। (विघ्न) आपके माध्यम से सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि सरकार को अब भी कैसीनों बिल को वापिस ले लेना चाहिए। इस बिल का पास होना कोई अच्छी बात नहीं है। (विघ्न)स्पीकर सर, अब मैं खासकर कृषि की बात करता हूँ। हर रोज अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए यह कर दिया, वह कर दिया किसानों के लिए यह विकास कर दिया लेकिन आज किसानों की हालत इतनी नाजुक है कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किसानों को क्या दिया। किसानों को नहरों का पानी नहीं मिला, किसानों को बिजली नहीं मिली और हरियाणा सरकार ने डीजल के रेट बढ़ाए हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार को हम इसलिए दोषी मानते हैं क्योंकि हरियाणा सरकार का सैंटर की सरकार में शेयर है, हरियाणा की सरकार केन्द्र के अन्दर हिस्सेदार है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज गांवों में किसान इस बात से चिंतित हैं कि सरकार अगला कदम क्या उठाएगी। लोगों को पता है कि यह मौजूदा सरकार कोई भी भला काम नहीं कर सकती है जो भी काम करेगी वह किसानों के विरुद्ध ही करेगी। (विघ्न) किसानों के बारे में आज सरकार वाह-वाही लूट रही है तथा सरकार बड़े लम्बे-चौड़े भाषण देती है कि हमारी सरकार आने के बाद किसान ने इतना अनाज पैदा किया। इस ज्यादा अनाज पैदा करने

में सरकार का क्या शेयर है ? किसानों ने अपने ट्यूबवैल्ज लगवाकर और डीजल खरीद कर खेती की सिंचाई की है, इसमें सरकार का क्या सहयोग है ? क्या सरकार ने किसानों को कोई रियायत या राहत दी है। सरकार ने किसानों को कोई भी रियायत नहीं दी है। अध्यक्ष महोदय, हर रोज हम अखबारों में ब्यान पढ़ते है कि सरकार ने इतने हजार कनैक्शन्ज दे दिए और ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन्ज दिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कोई आदमी बोला और कहने लगा कि मैं अपनी मां को बेचता हूँ लेकिन किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि बेटा मां बेचने की चीज नहीं होती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : फौजी साहब, आप गवर्नर एड्रैस पर बोलें कोई चुटकले मत कहें। (विघ्न) आप कोई कहावत न बताएं और केवल गवर्नर एड्रैस पर ही बोलें अगर कोई भजन गाना है या सांग वगैरह करना है तो वह बाहर जा कर करना। (विघ्न) यह विधान सभा है कोई चुटकला सुनाने की जगह नहीं है। अब आप कॉन्टीन्यू करें और एक मिनट में वाईंड अप भी करें।

श्री राम किशन फौजी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने किसानों को कितने ट्यूबवैल कनैक्शन्ज दिए हैं यह ये बताएं। अगर किसी किसान ने एक ट्यूबवैल का कनैक्शन लेना है तो उसके लिए उसको 90 हजार रुपए सिक्योरिटी के जमा करवाने पड़ते हैं। इतना महंगा कनैक्शन आम किसान नहीं ले सकता। अध्यक्ष महोदय, अगर किसान के पास इतना पैसा होता तो वह बाजार में या शहर में जाकर कोई धन्धा कर लेता। इस सरकार ने किसानों को ******* है।

श्री अध्यक्ष : यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (विघ्न)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले बिजली पानी मुफ्त देने की बात करी थी लेकिन अब इन्होंने बिजली के दाम कई बार बढ़ा दिए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राम किशन जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गए हैं। अब आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलते हुए अभी एक मिनट तो हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा किसान ट्यूबवैल कनैक्शन ले नहीं सकता है, अगर कोई ले भी ले तो इस सरकार ने वहां पर इलैक्ट्रोनिक मीटर लगा दिए हैं जो कि ठीक नहीं चलते हैं और किसानों का बहुत बिल आ जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : आपने तो बंसी लाल जी का भी समय ले लिया है अब आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। फौजी जी जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

श्री राम किशन फौजी : * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। फौजी जी जो बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाएं। बैठिए, बैठिए। बिशन लाल सैनी जी, आप बोलें। (शोर एवं व्यवधान) सैनी जी, आप गवर्नर एड्रैस पर बोलना चाहते हैं तो आप शुरु करें। (शोर

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री अध्यक्ष]

एवं व्यवधान) फौजी, आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) बिशन लाल सैनी जी, आप शुरू करें। (शोर एवं व्यवधान) राम किशन जी आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) इनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान) फौजी साहब, आप बैठें। अब आपका समय समाप्त हो गया है। आपने बहुत समय ले लिया है जबकि आपकी पार्टी बहुत छोटी है इसलिए अब आप बैठें।

श्री राम किशन फौजी : * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : फौजी साहब, अब आप बैठ जाएं। अब इनकी कोई बात रिकार्ड न करें। अब बिशन लाल सैनी बोलेंगे।

डॉ० बिशन लाल सैनी (जगाधरी) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो 5 मार्च को इस सदन में अपना अभिभाषण पढ़ा, मैं उस पर आपकी इजाजत से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। जो प्रस्ताव भाई उदय भान जी ने सदन में रखा है उस पर परिचर्चा के दौरान विपक्ष के साथियों ने भी अपनी बातें कहीं। इसी तरह से सत्ता पक्ष के साथियों ने भी इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए अपनी बातें रखीं। एक बात सबकी तरफ से उभरकर सामने आयी। कुछ साथियों ने यह कहा कि ''सरकार आपके द्वार'' जो प्रोग्राम है वह बहुत ही अच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे हरियाणा में इसको बहुत ही अच्छी तरह से चलाया हुआ है। लेकिन उधर के कुछ साथियों ने यह बोला कि यह प्रोग्राम एक ढकोसला है। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के साथियों की तरफ से कहा गया कि इस प्रोग्राम के तहत मुख्य मंत्री जी मौके पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका हल निकालते हैं **(इस समय माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक बात कहना चाहता हूँ कि ''सरकार आपके द्वार'' प्रोग्राम जो आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश के अंदर चलाया हुआ है वह एक बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जाकर खुद लोगों के बीच में बैठकर और वहां के नुमाइन्दे को अपने साथ बिठाकर लोगों की समस्याएं सुनकर और उनका मौके पर ही उनका निदान करना एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि एक साथी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वे पार्टी पोलटिक्स से ऊपर उठकर जो ''सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम है उसमें वहां के विधायक को भी अपने साथ लेकर लोगों की समस्याएं सुने। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि मुझे याद है कि जब ''सरकार आपके द्वार'' का द्वितीय चरण जिला यमुनानगर में हुआ था और यमुनानगर में जब मुख्य मंत्री जी ने वह प्रोग्राम वहां पर लगाना था तो उससे एक दिन पहले की रात को स्वर्गीय जयप्रकाश जी जिनका निधन हो चुका है, और जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनके घर पर मुख्यमंत्री जी गए और घर जाकर उन्होंने उनसे कहा कि कल आपके हल्के की समस्याएं पूछी जाएंगी। आप भी वहां आकर अपने लोगों की समस्याएं मुझे बताएं ताकि मैं उनका मौके पर ही निदान कर सकूं। उपाध्यक्ष महोदय, इससे प्रशंसनीय बात और कोई नहीं हो सकती। आज आप पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी भी गांव में जाकर देखिए हर गांव के अंदर कोई न कोई विकास का काम या तो चल रहा है या हो चुका है। कहीं पर बैकवर्ड क्लास की चौपाल बन रही है। कहीं हरिजन चौपाल का निर्माण हो चुका है, कहीं मुर्दाघाट के रास्ते पक्के करवाए जा रहे हैं, कहीं गांव के चारों तरफ कच्ची फिरनी को पक्का करवाने का काम किया

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गया है। प्रदेश के प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ने का काम जो मुख्य मंत्री जी ने किया है वह ''सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया है और इससे ज्यादा अच्छा काम कोई हो नहीं सकता। उपाध्यक्ष महोदय, ''सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम के अन्तर्गत मैं अपने जगाधरी विधानसभा क्षेत्र का भी जिक्र करना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी ने प्रथम चरण में जो ''सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम लगाया था उसमें 33 नयी सड़कें मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार की थीं वह सारी की सारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। (थम्पिंग) द्वितीय चरण में 19 नयी सड़कें मंजूर की गई थीं उनका भी 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और 20 प्रतिशत वहां के लोगों द्वारा मिट्टी न गिराए जाने के कारण लेट हुआ है। ''सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम रहा है और इसकी हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में चर्चा हुई है। मुख्य मंत्री जी ने अभी सदन में एक वक्तव्य दिया था मैं भी इस पर बात कहना चाहता था। आज प्रदेश के अंदर गांवों के अंदर जो गरीब जनता है उसके लिए एक बहुत ही विकट समस्या पैदा हो चुकी है क्योंकि परिवार बढ़ चुके हैं जहां एक परिवार था वहां चार बन चुके हैं जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब परिवारों के पास रहने के लिए जगह नहीं है और जो घरों कूड़ा कर्कट है उसको बाहर डालने के लिए गढ्ढे नहीं हैं जहां कि वे कूड़ा कर्कट डाल सकें। इसलिए वे लोग सड़कों पर ही कचरा डालते हैं। मैं भी इस बारे में कहना चाहता था लेकिन मुख्य मंत्री जी ने पहले ही बोल दिया। सरकार ने मन बनाया है कि प्रदेश के अंदर जितने भी गांव हैं जहां पंचायती जमीन है, वह जमीन लेकर के और जहां पंचायती जमीन नहीं है, वहां पर जमीन ऐक्वायर करेंगे। जिनके पास कूड़ा कर्कट डालने के लिए जगह नहीं है या रहने के लिए मकान नहीं है, उनको मकान बनाकर आसान किश्तों पर दिये जाएंगे जैसे कि शहरों में हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाकर दिये जाते हैं। इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का तहदिल से धन्यावाद करना चाहूँगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों की 50 साल से भी पुरानी मांग थी कि वहां चितंग नदी पड़ती है उस पर गांव पाबनी और मांगल जगीर गांव पड़ते हैं। उनके विकास के बारे में पिछली जितनी सरकारें आईं सबने वायदे किए परन्तु किया कुछ नहीं। मुख्य मंत्री जी ने मेरे हल्के के लोगों के एक बार कहने पर, ''सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम में एक ऐप्लीकेशन देने पर उस पुल का निर्माण 6 महीने में कर दिया इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। इसके अलावा कई और भी ऐसे काम हैं जो सराहनीय रहे हैं। तलाकौर से बाल छप्पर तक की सड़क जो कि बहुत पुरानी मांग थी उसको पूरा करवाया गया है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि तलाकौर से लेकर बाल छप्पर तक की जो सड़क बनी है उस पर भी चितंग नदी पड़ती है और इस सड़क पर लोगों का आना-जाना बहुत है उस पर पुल बनवाने का काम करें ऐसा मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा। डिप्टी स्पीकर सर, जैसा कि पहले जिक्र आया पिछले साल प्रदेश के अन्दर बिजली की हालत खराब रही। सूखे की स्थिति होते हुये भी सरकार ने बढ़िया वोल्टेज के साथ बिजली दी उससे किसानों ने अपनी फसल बचाने का काम किया है। जगह-जगह नये-नये सब स्टेशन लगाये गये हैं । डिप्टी स्पीकर सर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में दो नये बिजली घर बनाये गये हैं जिनका निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है। एक 66 के.वी. का सब-स्टेशन तलाकौर गांव में दूसरा 66 के.वी. का सब स्टेशन सालवन गांव में है जिनका काम पूरे जोरों पर चल रहा है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जुलाई के महीने तक ये दोनों सब स्टेशन अपना काम शुरू कर देंगे जिससे इलाके के लोगों की वोल्टेज और बिजली की समस्या का निदान हो पायेगा। डिप्टी स्पीकर सर, जैसा कि कृषि का जिक्र हुआ है। हालांकि इस प्रदेश के अन्दर सूखे की मार बहुत हुई लेकिन सरकार के द्वारा समय पर बिजली का प्रबन्ध, समय पर पानी का प्रबन्ध, ठीक बीज, खाद और दवाईयों

[डॉ० बिशन लाल सैनी]

का प्रबन्ध करवाने की वजह से इस साल अनाज का उत्पादन पिछले सालों की बनिस्पत ज्यादा हुआ है। डिप्टी स्पीकर सर, आज प्रदेश के अन्दर दूसरे प्रदेशों की बनिस्पत गन्ने का रेट सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। इसके बारे मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे हल्के यमुनानगर के किसानों को गन्ने का रेट 87 रुपये क्विंटल के हिसाब से दिया जा रहा है जबकि दूसरे जिलों के किसानों को 104, 106 और 110 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया जा रहा है। मेरी अर्ज यह है कि एक ही प्रदेश में दो तरह के रेट से गन्ना बिक रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा मेरे हल्के यमुनानगर के किसानों को गन्ने का रेट दूसरे जिलों की तरह ही 104, 106 और 110 रुपये क्विंटल के हिसाब से दिया जाये जोकि सहकारी मिलों में दिया जा रहा है। यह मेरी आपसे जोरदार अपील है।

श्री उपाध्यक्ष : वाईंड अप करें।

डॉ० बिशन लाल सैनी : डिप्टी स्पीकर सर, यह सब कहते हुये राज्यपाल महोदय ने इस सदन में जो अभिभाषण पढ़ा मैं उसका पुरजोर समर्थन करते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : मांगे राम गुप्ता जी, हमने आपको कहा था कि आपको बोलने का मौका जरूर देंगे। आपकी पार्टी के जो सम्मानित सदस्य बोलना चाहते हैं उनको भी हम बोलने का अवसर जरूर देंगे।

श्री मांगे राम गुप्ता (जीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अपनी परम्परा को निभाते हुये जब भी कोई बिधान सभा का बजट अधिवेशन शुरू होता है तो पहले दिन राज्यपाल महोदय सरकार की जो नीति है, नीयत है, उसको अपने अभिभाषण के द्वारा इस सदन में प्रस्तुत करते हैं और 5 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण इस सदन में प्रस्तुत किया। उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट में भी यह परम्परा है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते पार्लियामैंट में सैशन शुरू हुआ तो राष्ट्रपति जी ने इंग्लिश में अभिभाषण पढ़ा उसका अनुवाद वाईस प्रैजिडेंट ने हिन्दी में करना था इसी कारण से जब वह हिंदी अनुवाद पढ़ने लगे तो उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। तबीयत का तो पता नहीं लगता। उन्हें अपना अभिभाषण रोकना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी और वह पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन संपत सिंह जी बैठे हैं सरकार के बहुत सीनियर मंत्री हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि सरकार अपने जवाब में यह बात स्पष्ट करें कि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा। सरकार की जो नीति आपने उनको प्रस्तुत की वह उन्होंने पढ़ी। अभिभाषण पढ़ते वक्त वे बड़े स्वस्थ व खुश लग रहे थे पर समझ नहीं आया कि उन्होंने कई पैराज ** क्यों किये।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कोई कन्वैंशन तोड़ी है क्या?

प्रो. संपत सिंह : उन्होंने पैराज ड्राप नहीं किये बल्कि पढ़े मान लिया जाये कहा था। ड्राप एंड डिलीट अलग चीज होती है। उन्होंने कहा था पढ़े मान लिये जायें और इसका मतलब है कि गवर्नर एड्रैस का पार्ट एंड पार्सल है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीर पाल सिंह : मांगे राम जी, आपके समय में जब आप वित्त मंत्री थे, महामहिम राज्यपाल महोदय यहां पर आये और कई पैराज पर उन्होंने कह दिया कि पढ़े मान लिये जायें इसलिये आप जैसे सभ्य विधायक ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातों का प्रयोग करे तो यह चिंता का विषय है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री मांगे राम गुप्ता : कोई शोर शराबा हुआ हो, कोई अभिभाषण की प्रतियां फाड़ी गयी हों या राज्यपाल महोदय नाराज हो गये हों तब तो बात है।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : महामहिम राज्यपाल महोदय लगभग 55 मिनट बोले और 31 पेज के करीब का अभिभाषण पढ़ा।

श्री मांगे राम गुप्ता : 60 मिनट भी हो सकते थे 62 मिनट भी हो सकते थे। राज्यपाल महोदय ने वे पैराज ********** किये जिन पर हम एग्री नहीं कर सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष : यह ड्रॉप शब्द जो इस्तेमाल किया गया है यह कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री मांगे राम गुप्ता : वे पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे और न ही पढ़ा।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने डीमड टू रीड करके सारा अभिभाषण पटल पर रखा। जो चीज पटल पर आई उसमें आप कमियां निकालो या खूबियां निकालो।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. का मुद्दा सारे हरियाणा के लोगों की जीवन रेखा है। कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी या ग्रुप से संबंधित हो, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता और न ही किया। इस पर हाउस में बहुत चर्चा हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि संपत सिंह जी ने जिक्र किया कि राजीव-लौंगोवाल समझौता हुआ था उसके विरोध में 21 विधायक इस्तीफा देकर गये। बहुत बड़ी कुर्बानी दी, हम मानते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज कई बातें आई कि सोनिया पर दबाव डाला जाये। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह पर दबाव डाला जाये। हमारे साथियों का यह सुझाव था कि सड़क पर आ जाना चाहिये। जेलें भरी जानी चाहिएं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि ऐसी बात हम लेकर चलें जिसका लाभ या हानि हमें दिखाई देती हो। 21 विधायकों के इस्तीफा देने से कोई मामला हल नहीं हुआ। कई एजीटेशन चौधरी देवीलाल और दूसरे नेताओं ने किये लेकिन मामला फिर भी हल न हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट का क्लीयर कट फैसला है इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि एक साल में पंजाब सरकार पानी नहीं देती, नहर नहीं खुदवाती तो केन्द्रीय सरकार उस नहर को खुदवाये। मैं नहीं समझता कि इसमें इफ एंड बट की कोई बात है। मेरा संपत सिंह जी से सुझाव है अगर उनको जंचे तो वे नोट कर लें। जब ये विरोधी पक्ष में थे और 3-4 महीने चुनाव में रह गये थे तो ये इस्तीफा देकर शहीद हो गये। उपाध्यक्ष महोदय, आज चाहिये यह कि हरियाणा विधान सभा के सभी पार्टी के 90 विधायक, 15 लोकसभा और राज्यसभा के मैंबर्ज को अपने इस्तीफे लेकर सामूहिक तौर पर प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिये और हम चाहते हैं आप केन्द्र सरकार से कहें कि यदि एक महीने के अंदर-अंदर नहर का काम शुरू नहीं होगा तो हरियाणा विधान सभा के सभी सदस्य और हरियाणा का राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सदस्य इस्तीफा दे देंगे। फिर देखें कोई फैसला होता है या नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि हमें समय पर कुर्बानी देनी चाहिये। यूं खाली उंगली कटवाकर शहीद होने से कोई फायदा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : डिप्टी स्पीकर सर, श्री गुप्ता जी बहुत सीनियर मैंबर हैं और मैं इनसे बार-बार राय लेता रहता हूँ, सीखता रहता हूं। लेकिन कई बार ये ट्रैक से उतर जाते हैं और इन्हें ट्रैक पर लाने के लिये सहारा देना मेरा भी फर्ज बनता है। चाहे कोई सीनियर भी गलती करे तो उसे सही रास्ता दिखाना चाहिये। इन्होंने यह शब्द तो कह दिया कि पंजाब सरकार एक साल

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[प्रो० सम्पत सिंह]

में न बनाये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पंजाब सरकार एक साल में नहर बनाये। बाद में लिखा है कि यदि वह एक साल में नहीं बनायेगी तो उसके बाद जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार की होगी और केन्द्रीय सरकार उस केन्द्रीय एजैंसी से यथाशीघ्र बनवाये। पंजाब सरकार को तो एक साल का टाईम बाउंड सुप्रीम कोर्ट ने किया था। लेकिन केन्द्र सरकार के लिए टाईम बाउंड नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुप्ता जी को बताना चाहूँगा कि मैं सुबह से एक सैंटैंस बार-बार कह रहा हूँ कि पिछले एक साल से नहर बनवाने के बारे विपक्ष का कोई भाई नहीं बोला क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है नहर न बनने से हरियाणा प्रदेश का जो सबसे ज्यादा नुक्सान हुआ है उसके लिए दोषी कांग्रेस पार्टी है और ये उस पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह रहे। इन्हें चाहिए कि ये ऐसी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दे जो पार्टी इतनी बुरी है, जो हरियाणा का अहित कर रही है, हरियाणा का नुक्सान कर रही है, हरियाणा के हितों पर कुठाराघात कर रही है और हरियाणा की जीवन रेखा को खत्म कर रही है। जो चीज हरियाणा को ऑक्सीजन देने वाली है उसको कांग्रेस पार्टी खत्म करने में लगी है। इससे बुरा हरियाणा की जनता के साथ और क्या होगा और इससे बड़ा क्राईम कोई और नहीं कर सकता सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया और कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की जनता के हितों पर चोटें मारी है इससे बड़ा henious क्राईम नहीं हो सकता। पिछले एक साल से हरियाणा के हितों पर चोट लगती रही और नस कटती रही लेकिन इन भाईयों ने चूं तक नहीं किया और आज दो दिन हुए नहीं हैं इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तब तो इन्होंने नसीहत देनी शुरू कर दी और अब शहीदों की लिस्ट में आना शुरू हो गये। अब कह रहे हैं कि यह कर दो, वो कर दो लेकिन एक साल तक चूं नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, तब ये क्यों नहीं बोले। इन्हें किस बात का डर था, किससे डरे हुए थे। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा के लोगों को पता है कि इन्होंने उनका बेड़ा गर्क किया है, नाश किया है। (शोर एवं व्यवधान) आज इनकी जुत्तियों में तो दाल बंटती है और किसी के स्टैंड का भी पता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जय प्रकाश जी, प्लीज आप बैठें। पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर प्रो० सम्पत समय लेकर बोल रहे हैं।

चौ० जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, समय लेकर बोल रहे हैं तो हमें ऐसे ही कुछ भी थोड़े ही कह सकते हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, अब रैफ्रैंस आ गया, इन लोगों की हालत ऐसी हो गई है ये दूसरों से इस्तीफा मांग रहे हैं। इनकी स्वयं अपनी पोजीशन क्या है, कल जब एस०वाई०एल० का जिक्र आया तब चौधरी भजन लाल जी ने जिक्र किया कि यह मामला तो 1962-64 से चल रहा है तो हुड्डा साहब ने कहा कि आपको क्या मालूम। चौधरी भजन लाल जी ने कहा कि मैं मुख्य मंत्री रहा हूँ मुझे सारा मालूम है तो इन्होंने कहा कि आप तो कागजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। (शोर एवं व्यवधान) फिर ग्रीन ब्रिगेड के अध्यक्ष जय प्रकाश जी ने कहा कि इन्होंने तो इसको लेकर रैली की है तो भजन लाल जी ने कहा कि वे सैशन के बाद रैली करके दिखायेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, विपक्ष के भाईयों की यह तो पोजीशन है। ये आपस में तो एक हैं नहीं और दूसरों से इस्तीफा मांग रहे हैं। आज ये अपोजीशन में हैं इन्हें कुछ करके दिखाना चाहिए, पहले अपना इस्तीफा देना चाहिए। केवल मात्र स्टंटबाजी से बात नहीं बनेगी। इनको हरियाणा के हितों के लिए यूनाईटिड फाईट करना

चाहिए, फिर ये स्पोर्ट की बात करें।

चौ० जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री उपाध्यक्ष : बरवाला जी, चेयर की आज्ञा के बिना बोल रहे हैं, इसलिए इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। बरवाला साहब, आप बैठें।

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, केवल मात्र राजनीतिक स्टंटबाजी से बात नहीं बनेगी। पहले इन्हें हरियाणा के हितों के लिए यूनाइटेड फाईट करनी चाहिए, और यूनाईटेडली लड़ना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले ये यूनाइट हों फिर ये स्पोर्ट की बात करें। (शोर एवं विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो ऐसी कोई बात इनको शहीद करने की कही नहीं थी। इसमें शहीद वाली कौन सी बात है। ये जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह मसला कांग्रेस या लोकदल का नहीं है। अगर हमारी पार्टी का और पंजाब की कांग्रेस पार्टी का कोई डिस्प्यूट हो तो हम सोनिया जी को या कैप्टन अमरेन्द्र जी को कहें। यह मसला पंजाब और हरियाणा की जनता के हित का है। पंजाब की जनता के हित के लिए जैसे अन्य चीफ मिनिस्टर का जिक्र आया उसमें प्रकाश सिंह बादल का भी जिक्र आया। मैं कहना चाहूँगा कि बादल साहब से कौन सी नहर खुदवाने की चेष्टा की गयी। कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, उसके लिए यह मुश्किल है क्योंकि यह दोनों प्रदेशों का अपने अपने हित का मसला है। आपको पता है कि अपने प्रदेश के हित के लिए ही कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट का कन्टैम्प्ट बर्दाश्त किया। लोग उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए, अगर वह उसको मान लेता। उसे अपना राज ही नहीं अपनी जिन्दगी भी प्यारी है। कोई भी चीफ मिनिस्टर अपनी स्टेट के हितों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। (विघ्न) इसमें कांग्रेस का क्या सवाल है। सम्पत सिंह जी, हम कहते हैं कि अपने हित के लिए आप शहीद होने की बात न करो। आपका बहुत बड़ा स्टैण्डर्ड 19 मैम्बरों वाला रहा होगा इतिहास में लेकिन उसको कोई नहीं मानता। सम्पत सिंह जी, आज आप सरकार में हैं, सरकार चला रहे हैं। आप हरियाणा की जनता के हितैषी बनते हैं और अपने आप को किसानों की सरकार कहलवाते हो। किसानों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दे करके आपकी सरकार बनाई है। आज आप भी इस्तीफे दो, एम०पीज० भी इस्तीफे दें तो तब जाकर प्रधानमंत्री जी को पता लगेगा कि आप वाकई में हरियाणा की नुमाईन्दगी करते हैं। इसके बाद ही प्रधानमंत्री जी को पता लगेगा कि वाकई हरियाणा की जनता बहुत दु:खी है, उनको पता चल जायेगा कि अब ये लोग और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : कोर्ट का फैसला आए एक साल हो गया है।

श्री मांगे राम गुप्ता : एक साल तो 15 जनवरी को हो चुका है। आपने तो चूं तक नहीं की। चूं से काम चलने वाला भी नहीं है और न न्यू से काम चलेगा और न ही यूं से काम चलता है। आओ मैदान में। (विघ्न) हम तैयार हैं इस्तीफा देने के लिए। (शोर एवं विघ्न)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से इनके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये शहीद कहां होना चाहते हैं। इन्होंने 10 तारीख को पुण्डरी में एक रैली की थी। उस 10 तारीख की रैली में एक प्रेमसागर नाम के ज्योतिषी को बुलवाया गया

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री राम पाल माजरा]

और उससे स्टेज पर से कहलवाया गया कि 9 मार्च को चौटाला साहब की सरकार जायेगी। उस रैली के सबसे ज्यादा सिपहसालार मांगे राम गुप्ता जी थे। ये तो बहुत आतुर हैं गद्दी पर बैठने के लिए। डिप्टी स्पीकर साहब, अब ये गण्डे तागे पर आ गये हैं। अब इनके पास बात कहने के लिए कोई रही नहीं, लेकिन अब ये गण्डे तागे के जरिये चाहते हैं कि इनकी सरकार आ जाये। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि चौटाला साहब की सरकार चलेगी लोगों के सिर पर चलेगी, विधायकों के सिर पर चलेगी लेकिन गण्डे तागे के बल पर इनकी सरकार नहीं बनेगी।

श्री मांगे राम गुप्ता : माजरा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह बात मैं मानता हूँ कि पुण्डरी के लोकमंच पर से यह बात हुई थी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन माजरा साहब, आप मेरी बात सुनने की हिम्मत रखो। मैं उस बात को इसलिये स्पोर्ट करता था, वह खाली ज्योतिष के आधार पर स्पोर्ट नहीं कर रहा था। मैं इसलिये स्पोर्ट करता था, चूंकि मेरी आत्मा गवाही दे रही थी। मैं यह समझता था कि यह सरकार किसानों की हमदर्द बनती है क्योंकि किसानों के लिये इसने कुर्बानी दी है। ये किसानों के हमदर्द बनते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली और पानी मुफ्त में देंगे। आपने वायदे पूरे नहीं किये तो किसान सड़क पर आया। फिर कण्डेला में आठ-नौ आदमी शहीद हुये। उनमें से 6 आदमी तो मेरे अपने गांव के हैं और बाकी दो-तीन दूसरे साथ लगते गांवों के लोग शहीद हुए हैं। उस वक्त नौ आदमी इनकी गोलियों से शहीद हुए। जो लोग इनके करड़े भक्त रहे थे वे किसान लोग बिजली के बिल की माफी के कारण मेरे विरोधी रहे थे। लेकिन इन्होंने अपने समर्थकों को ही गोलियों से भून डाला। वहां पर सैकड़ों आदमी घायल कर दिये गये। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, आप ज्योतिषी वाली कही बात पर हिम्मत क्यों हार रहे हो, 9 तारीख आने में तो अभी दो दिन रहते हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हिम्मत नहीं हार रहा। मैं तो 1977 से यूं ही इनके खिलाफ लड़ता आ रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और न मैं कोई परवाह करता हूँ। मैंने चौधरी देवीलाल जी की भी कोई परवाह नहीं की। मैं उनको भी यही कहा करता था और आगे भी इसी प्रकार से लड़ूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, यदि इस सरकार के आदमियों की गिनती की जाये तो इस सरकार में केवल गोयल साहब एक मात्र बनिया मंत्री हैं और केवल एक ब्राह्मण विधायक श्री राम भगत जी इनको स्पोर्ट कर रहे हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि 40 के करीब तो किसान समर्थक बैठे हैं और 16 इसमें हरिजन हैं। यह सरकार तो किसानों और हरिजनों की ही सरकार है। दुलीना में पांच हरिजनों की हत्या हो गई थी और हरिजनों ने आह्वान किया था कि सभी हरिजन एम०एल०ए० सरकार छोड़कर बाहर आ जाएं। कण्डेला में किसानों ने, हरिजनों ने एम०एल०एज० का आवाहन किया था कि वे सरकार को छोड़ कर फौरन बाहर आ जायें क्योंकि इस जालिम सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है। (विघ्न)

नगर विकास मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है। गुप्ता जी से मैं इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा कि जब मेडिकल कॉलेज, अग्रोहा की ग्रांट सरकार ने बन्द कर दी थी तब अग्रवालों ने भी इसी तरह से कहा था कि अग्रवाल विधायक इस्तीफा दें। चौधरी भजन लाल तथा चौधरी बंसी लाल, दोनों सरकारों ने मेडिकल कॉलेज अग्रोहा की ग्रांट बंद की थी और इस बात पर अग्रवालों द्वारा इस्तीफा देने की बात पर तो किसी के कान पर जूं तक नहीं

रेंगी थी। उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग उंगली कटवा कर शहीद बनना चाहते हैं और मेरा नाम लेते हैं। ये बताएं कि उस वक्त इन्होंने खुद क्यों इस्तीफा नहीं दिया?

श्री मांगे राम गुप्ता : डिप्टी स्पीकर सर, माजरा साहब ने प्वाइंट आउट किया था मैं उसका जवाब दे रहा था कि किसान और हरिजनों के बलबूते पर जो सरकार बनी हुई हो और हरिजन और किसान यह फैसला ले लें कि हरिजनों और किसानों के एम०एल०एज० इस सरकार को छोड़कर बाहर नहीं आएंगे तो हम इन एम०एल०एज० को गांवों में और घरों में दाखिल नहीं होने देंगे। मुझे यह जंचता था कि हरियाणा का किसान बहादुर है और अपने फैसले पर अडिग है। ये एम०एल०एज० सरकार का साथ छोड़ देंगे और अगर ऐसा हो तो 9 तारीख तक यह सरकार कहां रहनी थी। इसी बेस पर मैंने यह बात कही थी। (विघ्न) मैं इन्कार नही करता। (विघ्न)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे दिन के उजाले में इनके गांव में जाकर आया हूँ। (विघ्न)

श्री राम बीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। यहां पर अभी गुप्ता जी कह रहे हैं कि दुलीना में 5 हरिजन मारे गए और प्रदेश की जनता ने कहा था कि हरिजन विधायक इस्तीफा दें। मैंने विधानसभा में पिछले सत्र में भी कहा था कि किसी ने यह सोच कर उनको नहीं मारा था कि वे हरिजन हैं और जो लोग इस अभियोग के तहत पकड़े गये हैं जिनके खिलाफ इन्क्वायरी हो रही है और मुकद्दमा चल रहा है उनमें से भी 7 लोग हरिजन हैं। गुप्ता जी यह नहीं कह सकते कि वे लोग हरिजन थे इसलिये मारे गये थे इस तरह से भ्रमित करने की कोशिश न करें। इस बात की सारे सदन ने निन्दा की है और इनको भी इसकी निन्दा करनी चाहिये और उन लोगों की भी निन्दा करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से ये सवर्ण और हरिजनों को लड़ाकर अपनी राजनीति करते हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : मांगे राम जी, अब आप वाईंड अप करें।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप कहते हैं तो मैं तो अभी बैठ जाता हूँ। हमने तो हमेशा आपको कहा है कि हम तो इस चेयर की कद्र करते हैं। इस चेयर पर चाहे आप बैठे हों, चाहे कोई और बैठा हो, हम तो हमेशा चेयर की कद्र करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मांगे राम जी, तभी तो हम भी आपकी कद्र करते हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप बोलें तथा अब आप वाईंड अप भी करें।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा टाइम तो हुआ ही नहीं है क्योंकि मुझे तो ये बीच में ही टोक रहे हैं और मैं तो ज्यादा बोला ही नहीं हूँ।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इतना बढ़िया माहौल है लेकिन ये लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और विधानसभा में आकर जात-पात की बात कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता : क्या कण्डेला में किसान नहीं मारे गये थे इसमें जात-पात की बात कहां है?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मांगे राम जी बहुत बढ़िया आदमी हैं और हुड्डा साहब विरोधी पक्ष के नेता हैं जो कि इस समय यहां पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के एक ओहदेदार ने गांव सुहरा में हुई बैठक में यह कहा था कि, कि पार्टी जाए भाड़ में, मैं तो कत्ल करने वाले लोगों के साथ हूँगा। इनके लोगों ने इस तरह का माहौल पैदा किया। (विघ्न)

[श्री धीरपाल सिंह]

कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। हुड्डा साहब, आपको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि आपकी पार्टी के एक ओहदेदार ने इस प्रकार का काम किया था। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : आप उसका नाम बताएं। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : मैं क्यों बताऊं आपको उसका नाम पता है। (विघ्न) मुझे उसका नाम पता है लेकिन मैंने उसका नाम नहीं लेना है, वह आपकी पार्टी का ओहदेदार है। आपकी पार्टी के ओहदेदार ने हालात खराब किए हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : इनका तो दोनों तरफ रोल था दूलिना में और था और बादशाहपुर में कुछ और था। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति वहां पर कुछ और कहता था, 24 घंटे इनकी जय बोले और वहां पर जाकर यह बात कहता है। (विघ्न) ऐसे आदमी के खिलाफ कोई ऐक्शन जरूर होना चाहिए था और इनको जरूर ऐक्शन लेना चाहिए था। लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। ये यहां पर आकर दोगली बात करते हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : मांगे राम जी, एक मिनट बैठें। बलवीर सिंह जी बोलना चाहते हैं। ये कभी कभी तो बोलने के लिए खड़े होते हैं।

श्री बलवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सम्मानित साथी भी बैठे हुए हैं और विपक्ष के नेता भी बैठें हैं। इनकी पार्टी का तो यह काम है और हमेशा ही दोगली नीति है। 'बुढ़ा मरो चाहे जवान, हत्या तांई काम'।

श्री उपाध्यक्ष : मांगे राम जी अब आप बोलें। (विघ्न) मांगे राम जी बोलिए अब आप रैस्ट न करें।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ यह बात कर रहा हूँ और इस विधान सभा के सैशन में यह बातें रिकार्ड हुई हैं। मैंने मुख्य मंत्री जी को इस हाउस में जब वे बैठे थे यह बात कही थी। मैंने कहा था, मुख्यमंत्री जी, किसानों ने आपकी सरकार बनाई है। इसमें उनका पूरा शेयर है और यह बात मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। (विघ्न) इसमें 36 बिरादरी भी शामिल है लेकिन आपकी सरकार को बनाने में ज्यादा शेयर किसान का ही है। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय पार्टी का नारा था कि हमारी सरकार आएगी तो 'बिजली पानी मुफ्त और पिछले बिल माफ'। (विघ्न) यह तो आप कहते थे। (विघ्न) मुझे इसमें क्या दिक्कत है। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार बन गई। मैंने कहा कि उन किसानों पर 10-12 साल का इतना भारी बिल हो गया है और वह अदा नहीं कर सकते हैं। किसान के गले में फांसी आ गई है, इसको आप काट दो। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बारे में रिकार्ड देखें, मुख्य मंत्री जी ने यह ब्यान दिया था, उन्होंने कहा था कि गुप्ता जी यह तो आपकी पार्टी थी, आपकी सरकार थी जिसमें किसानों को गोलियों से मारा गया था। मुख्यमंत्री जी ने आगे कहा कि किसान तो हमारे अपने भाई हैं, हम गोली की बात क्या, लाठी की बात क्या, हम तो आपस में बैठकर के इस मामले को सुलझा लेंगे तुम्हें क्या दिक्कत है। उस वक्त मैंने उनसे यही कहा था कि सुलझा लो। सम्पत सिंह जी, यह सुलझाया है आपने? किसानों को गोलियों से भून दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, बैठिए। एक बात जब पहले हो चुकी है आप उसको रिपीट न

करें। इसका कोई फायदा नहीं है। आपके पास कोई और बात हो तो उसको एक मिनट में कहें। आप समय का भी ध्यान रखें।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई बात रिपीट नहीं करूंगा। आप जिस वक्त कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बोलते हुए सैनी जी ने भी गन्ने के बारे में कहा था। सम्पत सिंह जी इस बात को नोट कर लें। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, इन्होंने उनका नोट कर लिया होगा आप इस बारे में चिन्ता न करें। जब वे बोले होंगे उन्होंने जरूर नोट किया होगा।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, चिन्ता करने के लिए ,विचार करने के लिए, सोचने के लिए और इनको बताने के लिए हम यहां पर आए हैं। इनके दर्शन करने के लिए थोड़े ही यहां पर आये हैं। यह कोई माता का मन्दिर थोड़े ही है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम गन्ने का 110 रुपये प्रति क्विंटल का रेट दे रहे हैं और यह दाम हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है, दूसरी तरफ आज किसान को गन्ने का 87 रुपये प्रति क्विंटल का रेट दे रहे हैं। यह यमुनानगर में है...। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, यह इस सरकार का काम है। आज यह सरकार गेहूँ के बारे में ढोल पीट रही है कि 59 लाख टन गेहूँ सरकार ने खरीद लिया है तो मैंने उस मामले में इनको स्पोर्ट किया और कहा कि 59 लाख टन नहीं 69 लाख टन है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, गेहूँ के बारे में ये फतवा लेना चाहते हैं कि दूसरे प्रदेश के किसान गेहूँ लेकर आए और उन किसानों से भी गेहूँ इस सरकार ने खरीदा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानकर चल रहा हूँ कि दूसरे प्रदेश की गेहूँ भी हरियाणा में आई और इस सरकार ने खरीदी है और इसका मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, गेहूँ दूसरे प्रदेशों से आयी भी और खरीदी भी गयी इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे क्या कारण हैं? उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले भी विधानसभा सैशन में कहा था कि वह गेहूँ हरियाणा सरकार के बलबूते पर नहीं खरीदा बल्कि वह केन्द्र सरकार के बलबूते पर खरीदा है। वह केन्द्र सरकार का पैसा था। हालांकि सरकार को उससे आमदनी हुई, आढ़ती को आमदनी हुई, इनके चेहतों को आमदनी हुई, बोरी खरीदने में आमदनी हुई और सुविधा शुल्क में आमदनी हुई। इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, आप यह बताएं कि क्या केन्द्र सरकार ने उन स्टेट्स को पैसा नहीं दिया था जहां से गेहूँ हरियाणा में आया था?

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, पैसा तो दिया होगा लेकिन इसे आप उनकी कमजोरी कह सकते हैं, नालायकी कह सकते हैं। इसलिए मैं तो इस बात के लिए सरकार को मुबारिकबाद देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जैसा भी गेहूं आया चाहे वह गीला आया या सूखा आया उसको खरीद लिया गया। आज 750/- रुपये क्विंटल गेहूं का भाव बाजार में है जबकि सरकार ने 620/-रुपये क्विंटल के रेट से गेहूं खरीदा है। आज किसान के घर में खाने के लिए गेहूं के दाने नहीं है उनको मोल लेकर खाना पड़ता है इसी तरह व्यापारी के घर में दाना नहीं है आज सारा गेहूँ सरकार के गोदामों में है। (विघ्न) यह गेहूँ सरकार ने अपने बलबूते पर नहीं खरीदा है। अगर सरकार ने यह गेहूँ अपने बलबूते पर खरीदा होता तो इनको पता लगता। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, अब आप बैठिए।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे वाईड अप तो करने दें। गेहूँ खरीदने के बारे में तो कोई दो राय नहीं है लेकिन गन्ने के बारे में बहुत भेदभाव हुआ है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, अब आप बैठिए। मैंने आपको टाईम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप औरों का भी ध्यान रखें।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बहुत मेहरबानी लेकिन मैं एक मिनट और लेकर बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, फिर आप हाउस छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। आखिर तक आप यहीं बैठे रहोगे।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक हाउस एडजर्न नहीं होता मैं उठकर कभी नहीं जाता।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह बात दूसरे मैम्बर्ज को भी कहें। आप देख ही रहे हैं कि हाजरी की यहां पर क्या हालत हो गयी है?

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने आप को ही कंट्रोल कर सकता हूँ दूसरों को आप कंट्रोल करें। मेरा फर्ज है कि अगर आपने हाउस बुलाया है तो मैं टाईम पर आऊं तथा जब भी आप हाउस एडजर्न करें तो उसके बाद ही हम जाएं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल दो बातें कहना चाहता हूँ। किसान के साथ गन्ने के मामले में जो भेदभाव हो रहा है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। तीन महीने में गन्ने की पेमेंट हुई है। नवम्बर में मिल चालू हुई है और किसान के गन्ने की पेमेंट आपने सैशन से पहले 28 फरवरी को करवायी है यानि तीन महीनों के बाद पेमेंट हुई है, इसका क्या फायदा है? जब आपको लगा कि सैशन आ रहा है तो जाकर आपने पेमेंट करवायी है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, यमुनानगर जिले में 1150 गांव अटैच हैं लेकिन वहां के किसानों को गन्ने का भाव 87/- रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया गया है जबकि उस एरिये के गन्ने में सबसे ज्यादा रिकवरी है। इतनी रिकवरी तो हमारे एरिये के गन्ने में भी नहीं है इसलिये वहां के किसान के साथ बड़ा भेदभाव है। आप इंक्वायरी करवाकर वहां के किसान के गन्ने की एवरेज ले लें। हरियाणा में बिके हुये गन्ने और पंजाब में जाकर जो गन्ना बिका है, उसकी अगर आप एवरेज लें तो 80/-रुपये से ऊपर गन्ने का रेट नहीं पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यमुनानगर के किसानों को उनके गन्ने का 87/- रुपये से ज्यादा रेट नहीं मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से दूसरा सुझाव और है वित्त मंत्री जी इसको नोट कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, यह नोट आप बजट के समय पर करवाया करो।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बजट पर ही बोलना चाहता था लेकिन आपने मुझे गवर्नर ऐड्रेस पर भी बोलने का समय दे दिया तो अब नोट भी तो करवाना ही पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी, एक बात और नोट कर लें। मैं एक बात बिजली के बिलों के बारे में कहना चाहता हूँ, आज जो बिजली के बिलों की हालत है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, अब तो आप रिपीट कर रहे हो, अब आप बैठें।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं नहीं, अब आप बैठें।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का नाम लेते ही आप मुझे बैठने के लिये कह रहे हैं। आप मेरा सुझाव तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव आपको उस टाइम देना चाहिए था।

श्री मांगे राम गुप्ता : मैं यह कह रहा था कि एक बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो गई है। हरियाणा के लोगों के साथ एक बड़ी भारी ज्यादती है कि एक वर्ग तो बगैर पैसे दिए बिजली का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे वर्ग पर उसका भार पड़ रहा है। सरकार को घाटा रहता है। यह बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। इस बारे में आप लोग कुछ करें। हम आपके अहसानमंद रहेंगे। मुख्य मंत्री जी के अहसानमंद रहेंगे, अभय चौटाला जी, आपके अहसानमंद रहेंगे। आप इस बीमारी को खत्म कीजिए। या तो आप बिजली फ्री ही कर दें या सबको एक समान रेट से ही दें। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : मांगे राम जी, आप बैठ जाएं। अब श्री भीम सेन मेहता जी बोलेंगे।

श्री भीम सेन मेहता (इन्द्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे 5 मार्च 2003 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अभिभाषण में जितनी भी सरकार की उपलब्धियां थीं जिन पर चर्चा की गई उनमें से कोई एक शब्द भी झूठ नहीं बोला गया। हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है कि जो भी विकास के कार्य थे जिनकी घोषणा की गई थी वे सारे के सारे कार्य कराए गए हैं और जो भी समस्याएं थीं उनका आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के लोगों के हितों की रक्षा करते हुये समाधान किया है। आज सारे का सारा प्रदेश इस बात का गवाह है कि पिछली सरकारों के समय सड़कों की क्या हालत थी? आज सड़कों की रिपेयर की गई है, जहां दोबारा से बनाने की जरूरत थी वहां सड़कों को दोबारा से बनाया गया है। जहां पुलों की जरूरत थी पुलों का निर्माण कराया गया है, स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। हजारों की तादाद में स्कूलों में नये कमरे बनाये गये हैं। जहां अध्यापकों की कमी थी वहां अध्यापक लगाए गए हैं। इस तरह से चाहे खेती के विषय में है, चाहे जन-स्वास्थ्य के विषय में हो, चाहे स्वास्थ्य के विषय में हो, हर क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना करता हूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कानून और व्यवस्था को संभालने में पुलिस विभाग ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है इसके लिये पुलिस विभाग भी बधाई का पात्र है कि किस तरीके से उन्होंने इस व्यवस्था को बनाये रखा हुआ है। अब मैं सड़कों के बारे में कहना चाहूँगा। मेरे हल्के में मुख्यमंत्री जी तीन बार 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत आये और उसमें उन्होंने जितनी भी घोषणाएं कीं वह सारी की सारी पूरी हुई और जिन सड़कों की घोषणा हुई वे भी बनकर तैयार हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधे घंटे के लिये बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय आधे घंटे के लिये बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री भीम सेन मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जहां मेरे हल्के में नयी सड़कें दीं, पुरानी सड़कों का पुनर्निर्माण किया, वहीं मेरे हल्के की चार मुख्य सड़कें हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं एक तो इन्द्री से डमरी तक की सड़क है मेरा निवेदन है कि इस सड़क को चौड़ा किया जाये साथ ही इसका पुनर्निर्माण भी किया जाए। दूसरी सड़क इन्द्री से रनदौली तक की है इसके बनने से इसके साथ लगते 30 गांवों के लोगों को लाभ होगा। तीसरी सड़क मटकमाजरी से डमरी है। बधनौरा पुल, हुगलीपुल की सड़क का निर्माण किया जाये। पिछले सैशन में कृषि मंत्री जी ने इसके बारे में आश्वासन दिया था कि इन्द्री शहर में सब्जी मण्डी का निर्माण हो जायेगा। परन्तु किसी कारणवश आज तक सब्जी मण्डी का निर्माण नहीं हो पाया है। इससे हमारे किसानों को नुकसान हो रहा है। हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है वहां पर सब्जी की फसल होती है और दूसरी फसलें भी होती हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर सब्जी मण्डी वहां पर बन जाये तो किसानों को ज्यादा फायदा होगा। इसी प्रकार से इन्द्री शहर में ऐसी कोई शिक्षा संस्था नहीं है जहां ज्यादा शिक्षा प्राप्त करके हमारे नौजवान साथियों को रोजगार के लिये शिक्षा प्राप्त हो। जैसे कि जे.बी.टी या ओ.टी. की कक्षायें हैं इसके बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये कक्षायें शुरू की जायें। भादसों गांव की पंचायत ने माननीय मुख्यमंत्री जी को 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के समय यह विश्वास दिलाया था कि बिल्डिंग के लिये पैसा ग्राम पंचायत देने के लिये तैयार है आप वहां पर एक आई.टी.आई. खोलने के लिये तुरन्त विचार करें। माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर विशेष ध्यान दें ताकि हमारे हल्के में प्रगति के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ सकें। इन्द्री शहर की बरसों से एक मांग रही है। हमारा क्षेत्र जीरी का ज्यादा उत्पादन करता है। जैसे दूसरे क्षेत्रों में हेफैड के सैलर लगाये गये हैं उसी तरह हमारे क्षेत्र में भी हेफैड के सैलर लगाये जायें ताकि किसानों को ज्यादा मदद मिल सके और ज्यादा फायदा हो सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि बिजली के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में आपने ज्यादा से ज्यादा योगदान दिया है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत इन्द्री क्षेत्र के गांव धनोखड़ा में एक पावर हाउस बनाने की मंजूरी दी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो पावर हाउस मंजूर किया गया है उसे शीघ्रातिशीघ्र बनाया जाये ताकि पब्लिक और वहां के किसानों को इसकी ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। सिंचाई के बारे में चर्चा चली। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में इन्द्री एस्केप है उसकी दोबारा खुदाई करवायी जाये ताकि गर्मियों के दिनों में पीने का पानी ठीक प्रकार से उपलब्ध हो सके। जैसा कि माननीय सदस्य सैनी साहब ने कहा हमारे क्षेत्र में गन्ना बहुत ज्यादा होता है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि गन्ने के भाव में हमें भी एक समानता दी जाये ताकि यह बात किसानों तक जाये। क्योंकि आपने समय के लिये पहले ही पाबन्दी लगाई है इसलिये ज्यादा समय न लेते हुये आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और गवर्नर महोदय का जो अभिभाषण है उसका पुरजोर समर्थन करते हुये सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इसका पुरजोर समर्थन करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मांगे राम गुप्ता जी, आपके नोटिस के लिये बता दूं कि आपके जो सम्मानित सदस्य बोलना चाहते थे उनमें चन्द्र मोहन, जतिन्द्र मलिक और हुड्डा साहब रह गये हैं। इसके अलावा दो सम्मानित सदस्य हाउस में उपस्थित नहीं हैं जिन्दल साहब और बलबीर पाल शाह। हुड्डा साहब को बुलवाना था लेकिन वो चले गये हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई सम्मानित सदस्य बोलना चाहता है तो वह अब भी बोल सकता है वरना श्री राम भगत जी को बोलने के लिये कह रहा हूँ।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात अधूरी रह गई थी।

श्री उपाध्यक्ष : अभी बहुत समय है सैशन अभी चल रहा है इस बार आपके समय आड़े नहीं आयेगा।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब का जिक्र किया गया उन्होंने किसी मैरिज में जाना था।

प्रो० राम भगत (नारनौंद) : उपाध्यक्ष महोदय, 5 मार्च को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण सदन में रखा गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हूँ और आपने मुझे इस पुनीत कार्य पर बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पावन दस्तावेज की शुरुआत भारतवर्ष और हरियाणा प्रदेश की उस महान बेटी कल्पना चावला से की जिसने अदम्य साहस का परिचय देते हुये नारी जाति और राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिये तथा अंतरिक्ष की ऊँचाईयों को मापते हुये अपनी कल्पनाओं को हकीकत का रूप देते हुये अपनी शहादत दी, अपने प्राणों की बाजी लगाई, उस महान बेटी को श्रद्धांजलि देते हुये इस दस्तावेज की शुरुआत की गयी है। इससे साबित होता है कि हरियाणा के मुख्य मंत्री और हरियाणा प्रदेश की सरकार इस देश की गरिमा बढ़ाने वाले वीर और मानव मूल्यों के लिए, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले वीर और वीरांगनाओं के प्रति गम्भीर है। आने वाली पीढ़ी में हमेशा उनकी एक स्मृति बनी रहेगी। वे इतिहास के पन्नों में शाश्वत रहेंगे। इस सरकार ने अच्छे पुरस्कार, कुरुक्षेत्र में प्लैनेटोरियम की स्थापना तथा करनाल के अन्दर एक मेडिकल कॉलेज उनके नाम पर खोलने का प्रस्ताव सैन्टर गवर्नमैंट को भेजा हुआ है। यह वास्तव में बहुत ही सराहनीय कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार ने देश की जंगे आजादी में बढ़-चढ़ कर भाग लेने वाले और बचपन से लेकर अपनी जिन्दगी के अन्तिम सांस तक कमेरा वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले, प्रजातन्त्र के सहआयामी और योद्धा, स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी की नीतियों और आदर्शों के अनुरूप इस हरियाणा प्रदेश को समस्त भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सारे संसार के अन्दर विकास, खुशहाली, प्रगति, 36 बिरादरी का भाईचारा शान्ति और अमन में एक अग्रणी प्रदेश बनाने के लिये कार्य किया है। उनका पूरा ब्यौरा इस दस्तावेज में दिया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, समय की पाबन्दी है इसलिये मैं अपने हल्के की लम्बित समस्याएं और सरकार की उपलब्धियों का तथा अपनी उन समस्याओं का भी जिक्र करूंगा और हरियाणा सरकार से पुरजोर अपील करूंगा कि वे मेरे हल्के की इन समस्याओं की तरफ ध्यान दें और उन पर जल्दी कार्य करने की मेहरबानी करें। आज शिक्षा के बारे में हरियाणा प्रदेश की सरकार बहुत ही ठोस नीति लेकर आई है। इस क्षेत्र में शिक्षा की कोई विशेष नीति नहीं आई है। एक अराजकता का माहौल था। कई स्कूलों के अन्दर कोई अध्यापक नहीं था। जब कोई नयी फैकल्टी खोली जाती थी मैडिकल की, नान-मैडिकल की, इन्फर्मेशन टैक्नोलोजी की वहां पर अध्यापक नहीं होते थे और शहरों के जो अच्छे-अच्छे स्टेशन होते थे वहां पर अध्यापकों की भीड़ लगी रहती थी। वहां पर अध्यापक सरप्लस रहते थे। लेकिन

[प्रो० राम भगत]

आज के हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति बनाई है। रैशनेलाइजेशन के तहत स्कूलों में जो खाली पद थे उनको भर दिया गया है। विशेषकर ग्रामीण अंचल के लिये बहुत ही ठोस नीति इन्होंने बनाई है कि कोई भी प्राध्यापक, मास्टर जिसकी फ्रैश पोस्टिंग होगी उसकी पहली अप्वाइंटमैंट गांव के अन्दर होगी और पांच साल तक ग्रामीण अंचल में उसे सेवा करनी पड़ेगी। इसी तरह से जिस अध्यापक ने आज तक ग्रामीण अंचल में कोई सेवा नहीं की है उस अध्यापक को भी पांच साल तक गांव में जाना पड़ेगा। इसी तरह से अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज, 17-18 इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी, आई.टी.आई.जैसी संस्थायें हरियाणा में खोली गई हैं उसके कारण हरियाणा के जो युवा हैं, उनको इन्फर्मेशन टैक्नोलोजी, ज्ञान विज्ञान, इण्डस्ट्री आदि में किसी भी किस्म की कोई डिग्री और डिप्लोमा करना चाहता है, उसको अब पूरा मौका हरियाणा में ही मिल जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे हल्के में जो नारनौंद का कस्बा है उसके 25 किलोमीटर के रेडियस में कोई कॉलेज नहीं है। मैंने पहले भी हरियाणा सरकार से इस बारे में मांग की थी कि नारनौंद के अन्दर कॉलेज खोला जाये ताकि वहां के आसपास के इलाके की समस्या दूर हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी समस्या होती है खासकर 10+2 और ग्रेजुएशन करने के लिये लड़कियां जब दूसरे शहरों में भीड़ वाली बसों में जाती हैं तो वास्तव में मां-बाप को बड़ा अजीब सा महसूस होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि नारनौंद में एक कॉलेज खोला जाये। इसके अतिरिक्त मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान नारनौंद के अंदर एक आई०टी०आई० संस्था मंजूर हो रखी है उसकी तरफ भी दिलाना चाहूँगा तथा निवेदन करूंगा कि इस संस्था पर भी जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सामाजिक न्याय की बात है, हरियाणा सरकार ने हर वर्ग के लोगों को पूरा न्याय देने का काम किया है। यह माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी की दूरदृष्टिता की सोच ही है जो उन्होंने समाज के हर वर्ग की संवेदनाओं को समझते हुए उनके दु:ख दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही नीतिगत फैसले लिए हैं और समाज की भलाई के लिए बहुत से अच्छे कार्यक्रम लागू किए हैं जो वास्तव में ही सराहनीय हैं। माननीय चौटाला साहब ने जो देवीरूपक स्कीम लागू की है वह पूरे विश्व में बहुत ही सराहनीय स्कीम है। इससे हमारे मुख्य मंत्री जी की दूरदृष्टिता का पता चलता है। एक बच्ची का जन्म लेना प्राकृतिक अधिकार होता है। लेकिन उसको संसार में आने से पहले ही मार दिया जाता है। इस स्कीम के लागू होने से अब बच्चियों को भी जिंदा रहने तथा इस संसार में आने का सपना पूरा होगा तथा जनसंख्या में मेल और फीमेल का अनुपात सही होगा। इसके अतिरिक्त इस स्कीम के लागू होने से हरियाणा जैसे सम्पन्न प्रदेश में जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा था उस पर पूरी तरह से नियन्त्रण होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारी सरकार की कृषि के बारे में भी विशेष ठोस नीतियां आई हैं। वे बहुत ही सराहनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि नारनौंद, घिराय, बरवाला और हांसी के बीच में शुगर मिल बनवायें। इस बारे में इन क्षेत्रों के सभी सदस्यों ने पहले भी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करके हिसार क्षेत्र में शुगर मिल बनवाने की मांग रखी थी और वहां के किसानों की भी यह पुरजोर मांग है कि वहां पर एक शुगर मिल खोली जाए ताकि वहां के किसानों को अपना गन्ना बेचने में दिक्कत न हो। (शोर एवं व्यवधान) इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने जो परम्परागत फसलें हैं उनसे हटकर डायवर्सीफिकेशन के तहत दूसरी फसलों को प्रोत्साहन देने की नीति लाई है। इस बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी किसान जो गैरपरम्परागत फसलें हैं चाहे वह तिलहन है, दलहन

है, फल फ्रूट हैं या सब्जियां हैं या होर्टिकल्चर से संबंधित फसलें हैं उनको तभी पैदा करेगा जब किसान को कुछ ज्यादा फायदा नजर आयेगा और सरकार की तरफ से किसानों को कुछ इन्सैंटिव दिया जायेगा। आज के दिन भारत सरकार और हरियाणा सरकार को धान के रख-रखाव, स्टोरिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर कराड़ों रुपये खर्च करना पड़ रहा है। यदि उस पैसे का दसवां हिस्सा भी किसानों को इन्सैंटिव के रूप में दे दिया जाये तो किसानों का ध्यान दूसरी फसलों की तरफ डाईवर्ट हो सकता है और किसान दूसरी फसलें पैदा करना शुरू कर देगा। इसके अतिरिक्त किसान जो सब्जियां, फल, तिलहन या दलहन अपने खेतों में पैदा कर रहे हैं उस फसल की मार्केटिंग भी किसान को मिलनी चाहिए और साथ-साथ सरकार की तरफ से उन फसलों को खरीदने व निर्यात की व्यवस्था भी होनी चाहिए तभी किसान डायवर्सीफिकेशन की नीति को अपनायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बड़े ही सराहनीय कार्य किए हैं। आज काड़ा विभाग ने ऐसी-ऐसी जगह 15-15 और 20-20 फिट ऊंचाई के इलाकों में पानी पहुंचाया है जहां सोचा भी नहीं जा सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे हल्के के कुछ गांव ऐसे हैं जो आज भी रेगिस्तान की तरह हैं। मेरा अपना गांव मसूदपुर तथा डाटा, गुराना, सींघड, सिंघवा, खानपुर आदि गांवो में 6.5 हजार एकड़ से 7 हजार एकड़ ऐसा क्षेत्र है जो पानी न मिलने के कारण बिना बिजाई के रह जाता है। इन गांवो की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने गुराना माईनर के नाम से 3.50 हजार एकड जमीन की सिंचाई के लिए 13 बुर्जी का माईनर मंजूर किया है जो बहुत ही सराहनीय काम है लेकिन हमने पूरे आठ के आठ गांवो की 6.5 हजार एकड़ से 7 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए माईनर की मांग की थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और जैसा हमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाकी के जो गांव बचे हैं उनके लिए पैरलल एक स्कीम बन रही है। मेरा निवेदन है कि इन 4-5 गांवों के लिए पैरलल स्कीम जो बनाई जा रही है। उसको जल्दी से जल्दी इम्पलीमेंट किया जाये ताकि इस रेतीले इलाके में भी हर प्रकार की फसल पैदा हो सके और ये गांव भी हरियाणा प्रदेश की बहबूदी और खुशहाली में अपना योगदान देते हुए खुद अपने पांव पर खड़े हो सकें। हमारी सरकार ने इरीगेशन के अन्दर कुछ नये आयाम जोड़े हैं। नये तरीकों में माइक्रो इरीगेशन और इसी प्रकार से स्प्रीकंलर सैटस से की जाने वाली इरीगेशन है। स्प्रीकंलर सैटस से की जाने वाली सिंचाई को रेतीले इलाके में प्रोत्साहित किया जाये ताकि वहां कम पानी में ज्यादा फसल पैदा की जा सके और पानी की बचत हो सके। इसके साथ-साथ मेरा अनुरोध है कि सी०एम० एनाउंसमेंट के तहत मेरे हल्के की जो 3-4 मांगें है उनको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। इन डिमांडज में एक मांग तो बढ़ाला गांव की माईनर की है। दूसरी उकलान्द गांव की स्कीम है और एक बुढाना गांव की स्कीम है। इन तीनों गांवों की स्कीमें इस वक्त निलम्बित पड़ी हुई हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन स्कीमों को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है और यहां पर आधुनिक तरीके से सड़के बनायी गई हैं। हमारे यहां तो कई सड़कें पाश्चात्य देशों में बनी हुई सड़कों से भी अच्छी बनाई गई हैं यानि पैरिस से भी अच्छी क्वालिटी की सड़कें यहां पर बनाई गई हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पिछली सरकारों के साढ़े आठ साल के अरसे में केवल 1100 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनी थी जबकि हमारी मौजूदा सरकार ने सिर्फ साढ़े तीन साल के अरसे में 6 हजार किलोमीटर लम्बी नई सड़कें बना कर एक रिकार्ड कायम किया है। ये बातें तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ जबकि असल में हमारे ये विपक्ष के साथी इस बात को मान चुके हैं कि इतने

[प्रो० राम भगत]

विकास के तो काम कोई सरकार आज तक नहीं करवा सकी जितने विकास के काम इन साढ़े तीन साल में हुए हैं। मौजूदा सरकार ने जो काम इन साढ़े तीन सालों में किए हैं उनका रिकार्ड तो गिनिज बुक में आना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में 3-4 सड़कें बनायी जानी जरूरी हैं। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में आज से 25-30 साल पहले जो सड़कें मंजूर हुई पड़ी हैं उनको पूरा करवाया जाये। एक सड़क बांस से पूठी है। यह सड़क 1995 के फल्ड में बह गई थी और उसके बाद से वहां पर बस भी नहीं जा रही। पूठी और बांस दोनों बहुत बड़े-बड़े गांव हैं और इन गांवों की आबादी 10-10 हजार से ऊपर है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर साहब आप वाईंड अप करें।

प्रो० राम भगत : मैं अपनी बात कहते हुए सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि वहां पर इन सड़कों के टैण्डर हो चुके हैं। मैटीरियल भी पड़ चुका है लेकिन पता नहीं महकमे की कमजोरी है या ठेकेदार की हरकत है। आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि पूठी की सड़क की जल्दी ही रेजिंग करके इसकी रिपेयर की जाये। इसी प्रकार से डाटा से बयाना खेड़ा जो सड़क है, वहां 3-3- फुट रेत चढ़ा हुआ है। यह 1987 से मंजूर है और इसके भी पिछले 6-7 महीने से टैण्डर हो चुके हैं लेकिन पता नहीं इस पर भी काम क्यों नही हो रहा। अत: मेरी मांग है कि इसको भी सरकार जल्दी से जल्दी बनवाये।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं जन-स्वास्थ्य विभाग के बारे में बात कहना चाहूँगा। इस विभाग द्वारा मेरे हल्के में बहुत बढ़िया काम हुए हैं। मेरे हल्के में 17-18 डिगियों पर इस वक्त काम चल रहा है और कुछ नई बनाई जा रही हैं, कुछ की रिपेयर हो रही है और कुछ का अगुमैन्टेशन भी हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि जिन गांवों की डिगियों का काम अधूरा पड़ा है और उनके लिए मैटिरियल भी आ चुका है कृपया उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। मेरे ख्याल में पाईप की उपलब्धता न होने के कारण वहां पर काम पूरा नहीं हो पा रहा। अत: मेरा निवेदन है कि इसकी तरफ ध्यान देते हुए इन कामों को पूरा किया जाये।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बातें कहना चाहूँगा। मेरे हल्के के एक बड़े गांव की पी०एच०सी० की बिल्डिंग पीछे बाढ़ में टूट गई थी। अत: मेरा अनुरोध है कि इस पी०एच०सी० को दुबारा बनाया जाये। यहां पर स्वास्थ्य मंत्री रंगा साहब बैठे हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस पी०एच०सी० की बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बनवाया जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए और धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगेराम गुप्ता जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो सदस्य बोल चुके हैं उनकी स्थिति बताई थी। आप यह न समझना कि आपको ही मैं बता रहा था। हमारे यहां 3 पार्टियां और हैं जैसे बहुजन समाज पार्टी के सैनी साहब को समय मिल गया। जगजीत सिंह संगलाल साहब भी अपनी पार्टी के इकलौते मैम्बर है इनको भी समय मिल चुका है। इसी प्रकार से कर्ण सिंह दलाल भी अपनी पार्टी के अकेले मैम्बर हैं उनको भी समय दिया जा चुका है। इसी प्रकार से हरियाणा विकास पार्टी के दो मैम्बर हैं। इनमें से राम किशन फौजी जी को बोलने का समय दिया जा चुका है और चौधरी बंसी लाल जी हैं नहीं। इसके बाद इन्डीपेन्डैंटस में जो मैम्बर हाजिर हैं उन सबको आलमोस्ट टाईम मिल गया है। बी०जे०पी० के हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं उनमें से कँवर पाल सिंह, सरिता नारायण व बीना

छिब्बड़ को समय दिया जा चुका है। इनके तीन सदस्य हाजिर नहीं थे। हम इनको भी समय देना चाहते थे लेकिन वे सदन में उपस्थित नहीं हैं। उसके बाद अब इण्डीपेन्डेंट में जो मैम्बर्ज बैठे हैं उनमें से एक तेजवीर जी भी बैठे हुए हैं। अब मैं तेजवीर जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी बात कहें।

श्री तेजबीर सिंह (पुण्डरी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के 5 मार्च के अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे समय दिया है। मैं इस अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जननायक चौधरी देवी लाल जी के आदर्श की सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए होती है, का परिपालन करते हुए मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कुशल एवं ओजस्वी नेतृत्व में हरियाणा सरकार के पिछले तीन सालों के दौरान प्रदेश में विकास और जन-कल्याण कार्यक्रमों को एक नई दिशा दी है। नई शिक्षा नीति, उद्योग नीति, सूचना-प्रौद्योगिकी नीति, शहरी विकास नीति, जैव-प्रौद्योगिक नीति और लोकप्रिय कार्यक्रम 'सरकार आपके द्वार' से प्रदेश में विकास के लिए एक नये युग का सूत्रपात हुआ है। नवयुवकों, छात्रों, ग्रामीणों, किसानों, महिलाओं ,कमजोर वर्गों, कर्मचारियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों जैसे समाज के सभी वर्गों को सुविधाएं दी हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया है। आज हरियाणा उच्च नैतिक मूल्यों को संजोए हुए आधुनिक प्रौद्योगिकीय के बल पर विकास की नई बुलन्दियां छू रहा है। इससे प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली है तथा प्रदेशवासियों में नए उत्साह और विश्वास का संचार हुआ है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एस०वाई०एल० कैनाल पर भी बोलना चाहूँगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा का पक्ष मानते हुए पंजाब सरकार को एस०वाई०एल० कैनाल का निर्माण एक वर्ष में 15 जनवरी, 2003 तक पूरा करने के आदेश दिए थे लेकिन पंजाब सरकार ने इसका निर्माण नहीं करवाया है। हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री जी से आग्रह किया है कि इसका निर्माण कार्य किसी सैंट्रल ऐजैंसी को दे दिया जाए ताकि इसका काम जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और हरियाणा को अपने हिस्से का पानी मिल सके। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को उनके प्रयासों के लिए बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह कैनाल जल्दी ही बन कर तैयार हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे राज्य में भी एक समस्या है और मैं सरकार की सराहना करना चाहूँगा कि इसे कण्ट्रोल करने के लिए 'देवीरुपक' योजना शुरू की गई है इसके अन्तर्गत प्रजनन आयु के दम्पतियों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन दम्पतियों को 500/- रुपये मासिक की धनराशि 20 वर्षों तक दी जाएगी जिन्होंने पहले बच्चे के जन्म पर, जो कि लड़की हो, नसबन्दी अथवा नलबन्दी करवा ली हो। इसी प्रकार उन दम्पतियों को 200/- रुपये मासिक की राशि 20 वर्षों तक दी जाएगी जो अपने पहले, लड़के के पश्चात तथा दो बच्चों, लड़कियों के बाद नसबन्दी अथवा नलबन्दी करवाएंगे। देशभर में इस प्रयास की सराहना की गई है और अन्य राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाने पर विचार कर रही हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम शुरू करके प्रदेश में तरक्की और विकास को एक नई दिशा दी है इसके अन्तर्गत पिछले लगभग तीन वर्ष के भीतर 33 हजार विकास कार्य पूरे हुए हैं और पिछले वर्ष 2 अक्तूबर से तीसरा चरण शुरू हो चुका है जिसके अन्तर्गत मुख्य मंत्री जी ने 48 हल्कों का दौरा पूरा कर लिया है और आने वाले समय में अप्रैल तक बाकी हल्के भी कवर हो जाएंगे। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की इस सोच का जो उन्होंने चौधरी देवी लाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए काम शुरू किया है उसकी सराहना करता हूँ। जो कदम उन्होंने उठाया है यह एक ऐतिहासिक कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि हरियाणा की अर्थ-व्यवस्था का मुख्य आधार है। पिछले दो वर्षों से

[श्री तेजवीर सिंह]

राज्य के कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति के बावजूद सरकार द्वारा समय पर सिंचाई हेतु पानी, बिजली, बीज, खाद आदि की समुचित व्यवस्था किए जाने के कारण वे अपने उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। तिलहनों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। वर्ष 2001-02 में गेहूँ का उत्पादन 94 लाख 37 हजार टन हुआ तथा इस वर्ष 95 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह से वर्ष 2001-02 में धान का उत्पादन 40 लाख 86 हजार टन प्राप्त हुआ जबकि इस वर्ष राज्य में सूखे की मार के बावजूद भी 37 लाख 2 हजार टन धान का उत्पादन हुआ है। इस वर्ष गन्ने की फसल बहुत अच्छी है तथा 10 लाख टन गुड़ के उत्पादन होने का अनुमान है जोकि एक नया कीर्तिमान होगा। यह सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ने की अच्छी कीमतें दिए जाने के कारण ही हुआ है। यह तो आप सभी जानते हैं कि राज्य में दी जाने वाली गन्ने की कीमतें देश में सबसे अधिक हैं। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : तेजवीर सिंह जी, आप समय का भी ध्यान रखें।

श्री तेजवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय का ध्यान रखते हुए जल्दी ही खत्म कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, 5 मार्च को राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है मैं उसका समर्थन करता हूँ और मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को बधाई देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं अब आपके माध्यम से सरकार को अपने हल्के पुण्डरी की समस्याओं के बारे में अवगत करवाना चाहूँगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सब इनको अपनी कैटेगरी में शामिल न करें। ये नये विधायक हैं इनको अच्छी बात करने दें। तेजवीर जी आपकी जो मांगे हैं आप उनके बारे में लिखकर दे दें और उन पर सरकार गौर कर लेगी।

श्री तेजवीर सिंह : ठीक है सर, मैं अपनी बातें और मांगें लिखकर दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन के जिस-जिस मैम्बर ने भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय मांगा था उन सभी को बोलने का मौका दिया गया है। यहां पर कई मैम्बर्ज जिन्होंने बोलने के लिए अपना नाम दिया था वे अब यहां पर बैठे नहीं है। अब मुख्यत: बैंचिज खाली नज़र आ रहे हैं और अब काफी समय भी हो चुका है। मैं अब चाहूँगा कि सदन की आज की बैठक को यहीं समाप्त कर दिया जाए क्योंकि सभी मैम्बर्ज इस पर बोल चुके हैं। अब सोमवार को सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। Hon,ble Members, now the House is adjourned till 9.30 A.M. on Monday, the 10 th March, 2003.

*14.58 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Monday, the 10th March, 2003)

36921—H.V.S.—H.G.P., Chd.